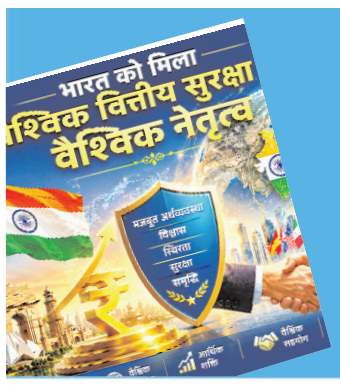

दैनिक

आज की जनधारा

सीधी और सच बात, साहस के साथ

डाक पंजीयन 29/2010-2012

वेब संस्करण
www.aajkijandhara.com
www.jandhara.in
Jandhara24x7
@AJandhara/Jandhara24/7
AajkiJandhara & Jandhara24x7
9981126516, 9425203900

दो राज्यः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4 संस्करणः भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर से एक साथ प्रकाशित

RNI.NO.MPHIN/ 25/A3544

वष : 01, अंक : 231, भोपाल, मंगलवार 23 जून 2026, पृष्ठः 12,मूल्यः 2/- | aajkijandhara.news | aajkijandhara | NewsAkj | ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष-9, वि.सं. 2083

लखनऊ की कोचिंग में आग, 15 मौतें

इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स, बचने के लिए बाथरूम में छिपे, दम घुटा, एसी में शॉर्ट सर्किट की आशंका

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 2:15 बजे एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी (कोचिंग) और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3डी आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। जानकारी के मुताबिक, आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में थंब इम्प्रेशन वाले गेट लॉक हो गए थे। छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। जयंत नाम के एक बच्चे ने पहले फ्लोर से कूद कर जान बचाई। लेकिन वह नीचे ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

अभी आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी पहुंची थीं। फायरकर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा, जिससे शव निकाले हैं।

घटनास्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई थीं। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मंजर को देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने लाशें निकलती देखी

हैं। सीएम योगी घटनास्थल पहुंचे। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर जाएंगे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं।

मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर बोलीं- अटॉप्सी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने कहा,अलीगंज में आग की घटना घटी है। जितने को हम बचा सकते हैं, हम उनको बचाएंगे। जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पंचनामा करके ऑटोप्सी करानी जरूरी है। अभी सब शुरू हो गया है।

अखिलेश यादव ने हादसे पर दुख जताया: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

रो पड़े डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

इस भयानक अग्निकांड की त्रासदी और इसमें जान गंवाने वाले मासूमों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बेहद भावुक हो गए। मीडिया से बात करने के दौरान इस दर्दनाक घटना का जिक्र आते ही डिप्टी सीएम खुद को संभाल नहीं पाए और कैमरे के सामने ही फफक-फफक कर रो पड़े।

प्रधानमंत्री ने किया मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। बचाव कार्य चल रहा है और अधिकारी हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भी ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

राहुल गांधी ने जताया दुख: राहुल गांधी ने भी इस भीषण अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया: रक्षामंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है, जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

बीजेपी मेयर रोते हुए बोलीं- आदिवासी महिला हूं इसलिए षडयंत्र

- **अंबिकापुर में 3 लाख रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल, कांग्रेस बोली- भ्रष्टाचार का खुला खेल**

सरगुजा। अंबिकापुर नगर निगम की भाजपा महापौर मंजूषा भगत पर मीना बाजार लगाने की अनुमति दिलाने के एवज में 3 लाख लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेयर ने इस ऑडियो को फर्जी बताया है। सोमवार को मेयर अजाक थाने पहुंचीं। ऑडियो बनाने के साथ उसे वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

मीडिया से बात करते हुए महापौर रोने लगीं और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ षडयंत्र रचा जा रहा है। वे आदिवासी महिला हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21 जून की शाम उन्हें फोन पर बताया गया कि आपका किसी ने ऑडियो जारी किया है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वह ऑडियो सुना। महापौर ने कहा कि उन्हें नहीं लगा कि वह आवाज उनकी है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है।

वहीं, कांग्रेस ने 3 लाख घूस लेने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। इधर, युवक कांग्रेस ने कलेक्टोरेट चौक पर प्रदर्शन किया और सड़क पर स्पीकर लगाकर लीक ऑडियो को पब्लिक को सुनाया।

रोते हुए बोलीं महापौर-मेरे खिलाफ षडयंत्र हुआ: मीडिया से बात करते हुए महापौर मंजूषा भगत भावुक हो गईं और रोने लगीं। उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने थाना प्रभारी से मांग की कि वायरल ऑडियो की बारीकी से जांच की जाए और इसमें जिस व्यक्ति अनुराग मिश्रा की आवाज बताई जा रही है, उसकी भी जांच की जाए।

महापौर ने कहा कि इस ऑडियो से वे और उनका परिवार मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वे कई दिनों शेष पृष्ठ 10 पर

ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से हटाया, अभिषेक सस्पेंड

कोलकाता। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच सोमवार को पार्टी में बगावत ने बड़ा मोड़ ले लिया। उलुबेरिया पूर्व के विधायक ऋ्रब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निलंबित करने और ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। यह फैसला बागी खेमे की एक अहम बैठक में लिया गया, जिसमें खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने वाले नेताओं ने नई संगठनात्मक समिति के गठन के तुरंत बाद प्रस्ताव पारित कर अभिषेक बनर्जी के निलंबन की घोषणा की। बागी गुट ने वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नई गठित संगठनात्मक समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। ऋ्रब्रत गुट की बैठक न्यू टाउन के एक होटल में हुई, जिसमें बागी विधायकों और कोलकाता नगर निगम समेत तीन जिलों के 70 पार्षदों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में हावड़ा मध्य से विधायक अरूप रॉय को ममता बनर्जी की जगह पार्टी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर संवैधानिक संकट को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक को संबोधित करते हुए ऋ्रब्रत बनर्जी ने कहा कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर तीन साल में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी।

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक कर रहे हैं। सीजेपी ने नीट पेपर लीक में सुसाइड करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज शाम 5:30 बजे प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर पर मोमबत्तियां लेकर आने की अपील की। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि हजारों लोग जंतर-मंतर पर आ रहे हैं और यह प्रदर्शन धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है। पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे हमारे साथ हैं।

पिकअप वाहन ट्रक से टकराया, 6 मजदूरों की मौत

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा-बैतूल नेशनल हाईवे पर एक पिकअप वाहन की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार मजदूर दूर जा गिरे। हादसा सोमवार सुबह करीब 10 बजे टेमनी खुर्द के पास हुआ। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। केवल एक मृतक की पहचान हो पाई है, जबकि 5 शव अभी अज्ञात हैं। जिला अस्पताल में अब तक 20 घायल लाए जा चुके हैं। इनमें एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल कॉलेज, नागपुर रेफर किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं। 20 से 25 डॉक्टर घायलों के उपचार में जुटे हैं। सर्जिकल आईसीयू में 3 मरीज भर्ती हैं। ऑर्थोपेडिक्स विभाग में 4 मरीज भर्ती हैं।

थरूर बोले- जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने बयान के कारण एक बार फिर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल, थरूर ने 21 जून को श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने जम्मू-कश्मीर की स्थिति और हालात में आ रहे सुधार पर बात की। चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन इस दौरे के बाद मुझे पहले से ज्यादा पॉजिटिव महसूस हुआ।

सीफूड फैक्ट्री में गैस रिसाव, 5 की मौत

नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक निजी फिश मील निर्यात फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को बताया कि रातभर में तीन और महिलाओं की मौत हो गई। इससे पहले 21 जून की शाम तक दो मौतें दर्ज की गई थीं। हादसा 21 जून को पेरियापालयम के पास कन्निगाइपैर गांव में स्थित फैक्ट्री की उत्पादन इकाई में हुआ था।

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत को धमकी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल एआरवाय न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। खासकर सिंध और बलूचिस्तान में पानी की कमी लगातार बढ़ रही है। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64.1फीसदी पानी की कमी है। राइस कैनाल में 38फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

मुस्लिम हमें काफिर बोलते हैं: मंत्री विजयवर्गीय

इंदौर। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा- यहां सड़क बन रही है। यहां हिंदू भाई भी रहते हैं और मुस्लिम भाई भी रहते हैं। कई मुस्लिम भाई हमको काफिर बोलते हैं। अगर हम काफिर हैं, तो हमारी बनाई सड़क पर मत चलो। आपके घर में लाड़ली बहना-लाड़ली लक्ष्मी योजना का पैसा आ रहा है, तो मत लो।

उन्होंने कहा, हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही हमारी नीति रही है। आप हमें वोट दो या नहीं दो, हमारा काम जनता की सेवा करना है। जनता की सेवा करना उनका दायित्व है। राजनीतिक समर्थन मिले या न मिले, विकास कार्य जारी रहेंगे। मंत्री विजयवर्गीय ने आगे कहा कि उनकी सरकार और पार्टी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।

उद्धव के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल

- **4 साल में दूसरी टूट, शिंदे बोले- छक्का लगाया, आदित्य ने पाला बदलने वालों को बिकाऊ कहा**

मुंबई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद सोमवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। बागी सांसदों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनके नंदनवन बंगले पर बैठक की। इसके बाद बागी सांसदों ने शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी बदलने का ऐलान किया।

इस दौरान शिंदे ने कहा कि जब 2022 में हमने पार्टी और धनुष-बाण बचाने के लिए विद्रोह किया था, तब 40 विधायक थे और अब छक्के लग चुके हैं। हमारी लड़ाई बालासाहेब के विचारों को बचाने के लिए है, इसीलिए आज ये 6 सांसद बालासाहेब की असली शिवसेना में शामिल हुए।

उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा- पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया है कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। कम से कम यह मान लीजिए कि लालच की वजह से आपने रातोंरात बिना किसी शर्म के यह सब छोड़ दिया। 6 सांसदों के शामिल होने के बाद लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। वहीं उद्धव गुट में 9 में से सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। 2022 के बाद शिवसेना में दूसरी बार टूट हुई।

उद्धव की बैठक में 4 विधायक नहीं पहुंचे: इससे पहले उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमेंमौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई।

ट्रम्प के इशारों पर काम नहीं करता: नेतन्याहू

- **लेबनान में इजराइली सेना हटाने से इनकार, अमेरिका-ईरान की बातचीत फिर शुरू**

तेल अवीव/तेहरान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लोग यह समझते हैं कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पर काम करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यरुशलम में आयोजित एक समिट में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं। वहीं इजराइल में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रम्प चाहते हैं। लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं।

इजराइली पीएम ने कहा कि इजराइल और अमेरिका करीबी सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने-अपने हित हैं और हर मुद्दे पर उनकी राय एक जैसी नहीं होती। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जरूरत महसूस होगी तब तक इजराइली सेना दक्षिणी लेबनान में रहेगी।

राम मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारी हटाए

- **सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए, धर्म सेना अध्यक्ष का मोदी को लेटर, ट्रस्ट भंग करने की मांग**

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारियों को सोमवार को हटा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को ड्यूटी में लगाया गया है। हटाए गए कर्मचारियों को दूसरी जगह ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके अलावा, गणनास्थल पर 3 सीसीटीवी बढ़ाए गए हैं। अब सीसीटीवी की संख्या बढ़कर 4 हो गई है।

इधर, धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। चढ़ावा चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी आज सीएम योगी आदित्यनाथ को शुरुआती रिपोर्ट सौंप सकती है। टीम रविवार शाम को योगी से मिलने पहुंची थी, लेकिन उनके मानसून सेशन की मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से मुलाकात नहीं सकी थी। एसआईटी ने जिन लोगों से पूछताछ की है, उन्हें अगले आदेश तक अयोध्या से बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है।

इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव भी शामिल हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि गोपाल राव अयोध्या छोड़कर कर्नाटक चले गए हैं।

बंगाल में मदरसों को मिलने वाली रकम आधी हुई

- **महिलाओं को नौकरी में 33फीसदी आरक्षण, सरकारी कर्मचारियों को 38फीसदी डीए, भाजपा सरकार का पहला बजट**

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में कहा गया कि सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को भरेगी और इसमें महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए फंड 5,713 करोड़ से घटाकर 2,165.42 करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 4 लाख 30 हजार करोड़ के बजट में पूर्व सीएम ममता बनर्जी के समय शुरू हुई सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं (जैसे- अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा) को जारी रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 38फीसदी कर दिया गया है। वहीं, कोलकाता में एक नए एयरपोर्ट बनने की भी घोषणा की गई है।

मानसून सत्र के बाद मध्य प्रदेश सरकार में बड़ा फेरबदल

आधा दर्जन मंत्रियों पर संकट, नए चेहरों की एंट्री तय

अंशुमन खरे

मध्य प्रदेश की राजनीति में मानसून सत्र के बाद बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि इस बार बदलाव सिर्फ खाली पदों को भरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव और कुछ चेहरों की विदाई भी तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार और संगठन स्तर पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा पूरी हो चुकी है। इसी समीक्षा के आधार पर पांच से छह मंत्रियों को हटाया जा सकता है, जबकि सात से आठ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जो मंत्री अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें आगे मौका नहीं दिया जाएगा। अंतिम निर्णय भाजपा संगठन और केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद लिया जाएगा। इस संभावित विस्तार को सिर्फ प्रदर्शन से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसके पीछे क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की रणनीति भी है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 और अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों

को देखते हुए भाजपा हर वर्ग और क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश में है। बुंदेलखंड लंबे समय से मंत्रिमंडल में अपेक्षित हिस्सेदारी की मांग करता रहा है। सागर, दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ जैसे जिलों से नए चेहरों को मौका देकर पार्टी इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर सकती है। सागर के प्रदीप लारिया और पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के नाम इसी क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से चर्चा में हैं। महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भी पार्टी का फोकस है। विंध्य क्षेत्र की नेता और पूर्व सांसद रीति पाठक, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और इंदौर की विधायक मालिनी गौड़ के नाम नए चेहरे के रूप में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। भाजपा संगठन महिला नेतृत्व को मजबूत करने के संकेत पहले भी देता रहा है। वहीं ओबीसी समीकरण को मजबूत करने की कवायद भी इस फेरबदल में अहम मानी जा रही है। इसके अलावा सिंधिया समर्थक नेताओं और पुराने भाजपा नेताओं के बीच संतुलन बनाना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में नए मंत्रियों के चयन में राजनीतिक संदेश का भी ध्यान रखा जाएगा। कुछ मंत्रियों की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विजय शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद बढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और संगठन की नाराजगी के बाद उनकी स्थिति कमजोर बताई जा रही है। वहीं दिलीप अहिरवार के विभागीय प्रदर्शन को लेकर भी समीक्षा में चर्चा होने की बात कही जा रही है। प्रतिमा बागरी जाति प्रमाण पत्र विवाद के चलते भी सुर्खियों में रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य स्तरीय जांच समिति से रिपोर्ट मांगी है। उनके भाई की गिरफ्तारी का मुद्दा भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। इसके अलावा राधा सिंह और एदल सिंह कंषाना के विभागों की कार्यप्रणाली पर भी समीक्षा में सवाल उठने की खबर है। फेरबदल में केवल चेहरे ही नहीं बदलेंगे, बल्कि कुछ बड़े विभागों का संतुलन भी बदला जा सकता है। प्रहलाद पटेल को संगठन या सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है।

जल संकट से परेशान रहवासियों ने किया नपाध्यक्ष के निवास पर हंगामा

वार्डवासियों ने की जल्द से जल्द समस्या को दूर करने की मांग

आज की जनधारा

विदिशा। नगर पालिका अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 33 और 34 के रहवासी पिछले कई दिनों से जल संकट की समस्या से परेशान हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर करैयाखेड़ा रोड़ और आचार्य कॉलोनी के रहवासी सुबह नगर पालिका अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे और हंगामा कर दिया। इस दौरान बिट्टू, रंजीत लोधी, नेतराम का कहना था कि नगर पालिका द्वारा टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है, लेकिन लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष निवास पर नहीं मिली तो लोगों ने वहां से गुजर रहे टेंकर को रोका। आधा टेंकर पानी लाने पर आपत्ति दर्ज कराई तो चालक ने लोगों से अपशब्द कहे। जिससे लोग नाराज हो गए और नपाध्यक्ष के घर के बाहर नारेबाजी करने लगे।

आचार्य कॉलोनी निवासी महिला ने बताया कि कल रात एक बजे तक टेंकर का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया। वहीं अन्य रहवासी ने बताया कि सुबह टेंकर आया जो आधा ही भरा हुआ था, उसे भी चालक एक घर पर खाली करके चला गया। करैयाखेड़ा रोड निवासी युवक ने बताया कि दो से तीन दिन में एक बार टेंकर आता है। कई बार आधा टेंकर ही लाया जाता है। जिसके कारण से आसपास के लोगों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा जब टैंकरों की संख्या बढ़ा दी गई है तो फिर क्यों लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पिछले कई दिनों से पानी की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। टैंकर आता है लेकिन वह भी आधा भरा हुआ रहता है, कभी-कभी तो हम लोग इंतजार ही करते रहते हैं, लेकिन पानी का टैंकर नहीं आता है। जिसके कारण से दूर दराज लगे हुए हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा। उन्होंने बताया कि कई बार गंदा पानी भी टेंकर से सप्लाई हो रहा है। इसी सुधार की मांग को लेकर नपाध्यक्ष के निवास पर आए थे, लेकिन वह घर पर नहीं है। लोगों का कहना था कि हम अपनी समस्या को लेकर आए थे, लेकिन हमारी सुनने वाला यहां कोई नहीं है। अब हम अपनी समस्या आखिर किसके सामने रखें और उसका समाधान कैसे होगा, वह समस्या हमारे समक्ष खड़ी हुई है।

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाए, जिससे कि लोगों को हो रही दिक्कतों से निजात मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में रहवासी मौजूद थे।

वहीं नगर पालिका अधिकारी दुर्गेश ठाकुर ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है, वहां पर टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई है। अगर इसके बाद भी लोगों को पानी की दिक्कत आ रही है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और साफ और शुद्ध पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

गायत्री जयंती एवं अखंडदीप जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गायत्री शक्तिपीठ में विशेष रक्तदान शिविर आयोजित

आज की जनधारा

विदिशा। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गायत्री जयंती के उपलक्ष्य में अखिल विश्व गायत्री परिवार के गायत्री शक्तिपीठ राजीव नगर में 22 जून को विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विदिशा गगन बाजपेई उपस्थित रहे।

शिविर में गायत्री परिवार के परिजनों एवं समाजसेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए लगभग 25 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में सुमन कुशवाह, सौरभ गुप्ता, अमित नेमा, आकांक्षा श्रीवास्तव, ममता पाठक, एकता श्रीवास्तव, निधि तिवारी, शशांक तोमर, कमलेश अहिरवार, दीपक नामदेव, रश्मि द्विवेदी, हिमाद्रि सविता, जीत भदौरिया, अंकित श्रीवास्तव, संजीव सक्सेना, संगीता चावला, मनोज अग्रवाल, मुकेश आजाद, प्रभास सोनकर, आशीष कुमार सहित अन्य रक्तदाता शामिल रहे।

कार्यक्रम को सफल बनाने में गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी सुमन कुशवाह, प्रज्ञा पीठ के मुख्य ट्रस्टी मुकेश श्रीवास्तव, समाजसेवी विकास पचौरी, सिद्धि कुशवाह, संतोष सिंह भदौरिया, शंकरलाल करेले, संध्या कपूर, विजय श्रीवास्तव, सुमन श्रीवास्तव, लोकेश्वरी नेमा, अमित नेमा , गोपाल मीना एवं कार्यालय प्रभारी राजकुमार प्रजापति सहित अनेक कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।

मुख्य अतिथि गगन बाजपेई ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और इससे अनेक जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिलता है।

उन्होंने गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं मानवीय कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए समाजहित में ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया।

वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित

आज की जनधारा

विदिशा। रघुवंशी समाज साख सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले के उप पंजीयक ध्रुव कुमार झारिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभा में संस्था के प्रशासक कैलाश चंद्र यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एमएस भदौरिया, सुरेश बरकड़े, किशोर कुमार अहिरवार सहित संस्था के पूर्व अध्यक्ष सरदार सिंह (काका) रघुवंशी, रघुवंशी समाज जिलाध्यक्ष मोहर सिंह रघुवंशी, विपणन सहकारी संस्था बासौदा के पूर्व अध्यक्ष निरंजन सिंह रघुवंशी, जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, रामकृष्ण सिंह, हीरालाल, दिलीप सिंह, अयोध्या ट्रस्ट अध्यक्ष पीएस रघुवंशी, नटेरन ट्रस्ट अध्यक्ष भगत सिंह (अंडिया), वीर सिंह, मोहर सिंह मानौरा (शिक्षक) पूर्व सचिव, गुलाब सिंह, शंभु सिंह, अमर सिंह, निरंजन सिंह, भवानी सिंह, परमाल सिंह, मालम सिंह, हरनाम सिंह, चरण सिंह, वीरेंद्र सिंह (एडवोकेट), लखन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभा में संस्था की वार्षिक प्रगति, कार्यों एवं भावी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिला रघुवंशी समाज 24 को सौंपेगा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

आज की जनधारा

विदिशा। अयोध्या स्थित प्रभु श्रीराम जन्मभूमि मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं एवं चंदा राशि तथा आभूषणों से संबंधित समाचारों को लेकर समाज में गहरी चिंता व्याप्त है। इस विषय की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला रघुवंशी समाज द्वारा 24 जून सुबह 11 बजे कलेक्टोरेट परिसर में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में रघुवंशी समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने की मांग भी रखी जाएगी। रघुवंशी समाज ने सभी से शामिल होने की अपील की है।

करैयाखेड़ा रोड पर नाला निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप, सीएमओ ने दिए जांच के निर्देश

आज की जनधारा

विदिशा। शहर के करैयाखेड़ा रोड क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग और सीमेंट-कांक्रीट के निर्धारित अनुपात का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए नगरपालिका में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार करैयाखेड़ा रोड क्षेत्र से गुजरने वाला बड़ा नाला पहले कच्चा था। बरसात के दौरान होने वाली समस्याओं को देखते हुए नगरपालिका द्वारा इसका सीसीकरण कर पक्का निर्माण कराया जा रहा है। इसी दौरान रहवासियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे नाले की मजबूती और टिकाऊपन पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की शिकायत मिलने के बाद नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) दुर्गेश ठाकुर ने बताया कि निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान निर्माण सामग्री और उसके अनुपात की तकनीकी जांच की जाएगी। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है और निर्माण में निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री का उपयोग नहीं मिला, तो संबंधित हिस्से को तोड़कर दोबारा निर्माण कराया जाएगा। साथ ही दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विदिशा की जनता गंदे पानी से परेशान, स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतराःअरुण कुमार अवस्थी

आज की जनधारा

विदिशा। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अरुण कुमार अवस्थी ने नगर पालिका प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि विदिशा शहर के अनेक वार्डों में पिछले कई दिनों से गंदा एवं दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे नागरिकों में स्वास्थ्य को लेकर भारी चिंता व्याप्त है। अरुण अवस्थी ने कहा कि पीने के पानी में गंदगी और बदबू होने के कारण लोगों को मजबूरी में वही पानी उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे जलजनित बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन नगर पालिका इस मूलभूत सुविधा को भी सुनिश्चित करने में विफल साबित हो रही है। यदि समय रहते स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो शहर में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है।

अरुण अवस्थी ने जिला प्रशासन एवं नगर पालिका अधिकारियों से मांग की है कि दूषित पानी की आपूर्ति तत्काल बंद कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा जल प्रदाय व्यवस्था की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनता की इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो जिला कांग्रेस कमेटी जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

कांग्रेस जनता को इस प्रकार परेशान होते हुए नहीं देख सकती और उनके अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक लड़ेगी।

कुरवाई पुलिस ने पकड़ा 5 घंटे में चोरी का आरोपी

आज की जनधारा

विदिशा। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने फरार स्थाई/गिरफ्तारी वारंटियो की धरपकड़ हेतु आदेशित किया गया है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डा. प्रशान्त चौबे के निर्देशन में एसडीओपी कुरवाई रोशनी ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना कुरवाई प्रभारी आरके मिश्रा के नेतृत्व में आरोपी की तलाश पतारसी कर प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।

बताया गया कि 22/06/26 को फरियादीया रानी प्रजापति पति स्व. माखनलाल प्रजापति निवासी जोनाखेडी ने रिपोर्ट किया कि मेरे पति करीब 4 साल पहले शांत हो गये है। मेरे तीन बच्चे है मैं उनके साथ रहती हूं। 17/06/26 को मैं अपने बच्चों के साथ खाना खाकर घर के अंदर सो गयी थी। सुबह करीब 5 बजे मेरी नींद खुली तो घर के दरवाजे के सामने वाली दिवाल पर गड्ढा खुदा था, हड़बड़ाकर उठी तो कमरे में रखा सूटकेश खुला था। सूटकेश में रखा सामान चैक किया तो उसमें रखे 25 हजार रुपये नगद एक मंगल सूत्र जिसमें एक सोने का पेन्डल 11 गुरिया थे, एक जोड़ चांदी की पायल, बच्चों के आधार कार्ड बैक पासबुक नहीं थे, कोई अज्ञात व्यक्ति रात्री में घर की दीवार में छेद कर घुस कर सामान चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर थाना कुरवाई पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपराध की गंभीरता को देखते हुये तत्परता और सक्रियता दिखाते हुए आसपास के क्षेत्रों में अज्ञात आरोपी की तलाश कर मुखबिर की सूचना पर संदेही धारुसिह पिता धन्नालाल प्रजापति उम्र 37 साल निवासी ग्राम जोनाखेडी थाना कुरवाई से अपराध सदर में हिकमत अमली से पूछताछ की, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया एंव चोरी किया गया मशरुका अपने खेत की मेड के पास पत्थर के नीचे छिपाकर रखा होना बताया जो समक्ष पंचान संदेही/आरोपी धारुसिंह का मेमोरेण्डम लेख किया जाकर आरोपी के बताये अनुसार स्थान पर जाकर चोरी गया माल मशरुका कीमती 1 लाख 30 हजार जप्त किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट प्रदान करने पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। इस कार्यवाही में निरी.आरके मिश्रा, प्रआर 357 टीकाराम दांगी, प्रआर सुनील, आर इरफान, आर उवेश खान, मआर डिम्पी राय की महत्वपूर्ण योगदान रहा।

नगद ईनाम की घोषणा

आज की जनधारा

विदिशा। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के द्वारा थाना कोतवाली जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 112/2025 की विभिन्न धाराओं के फरार आरोपियों में इदरीश बेदी पुत्र नईम अख्तर निवासी मालवीय वार्ड नम्बर 16 और हनुमान नगर लोधीपुरा बुरहानपुर जिला बुरहानपुर तथा सिविल लाइन जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 303/2026 के फरार आरोपी हेमंत पुत्र स्व. नारायण प्रसाद पचौरी निवासी ए-21 बालाजी एवेन्यु थाना सिविल लाइन विदिशा की सूचना देने वालों को क्रमशः पांच-पांच हजार रूपए नगद राशि देने की उद्घोषणा की है। सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

महिलाओं के लिए निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस शिविर आज

आज की जनधारा

विदिशा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार महिलाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाने तथा उन्हें वाहन संचालन हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज मंगलवार 23 जून को जिला परिवहन कार्यालय, विदिशा में महिलाओं के लिए निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस शिविर का प्रातः 10 बजे से आयोजन किया गया है। शिविर में महिला आवेदिकाओं को लर्निंग लाइसेंस बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया में विभागीय कर्मचारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरजेश वर्मा ने बताया कि लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। मध्यप्रदेश के निवासी आवेदकों को परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सामान्यतः पुरुष आवेदकों को दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन के लर्निंग लाइसेंस के लिए 225 रुपये तथा दोनों श्रेणियों के लिए 425 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा करना पड़ता है, जबकि महिला आवेदिकाओं के लिए यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर आवेदक उत्तीर्ण घोषित हो जाता है और उसका लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। यह प्रक्रिया किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, एमपी ऑनलाइन केंद्र अथवा स्मार्ट मोबाइल फोन के माध्यम से पूरी की जा सकती है।

शिविर में आने वाली महिला आवेदिकाओं को अपना आधार कार्ड, जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट हो, अथवा मतदाता पहचान पत्र साथ लाना होगा। इसके अतिरिक्त जन्मतिथि प्रमाण के लिए दसवीं कक्षा की अंकसूची या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी ने जिले की पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे इस विशेष शिविर का लाभ उठाकर निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस बनवाएं तथा सुरक्षित एवं वैधानिक वाहन संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएं।

विद्युत लाइन चालू कराने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन

आज की जनधारा

विदिशा। सोमवार को गुलाबगंज तहसील के ग्राम मणिपुर निवासी किसान और ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम आवेदन दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के एक किसान के खेत में से अटल ज्योति और खेतों में लगे ट्यूबवेल तक लाइन निकली हुई है। किसान द्वारा लाइन को काट दिया गया है, जिसके कारण से गांव में अंधेरा फैला हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण महेंद्र सिंह, मोहन सिंह, चैन सिंह, भगवान सिंह, अमित आदि ने बताया कि मालन सिंह राजपूत द्वारा विद्युत लाइन को बंद कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से गांव के लोग काफी परेशान हो रहे हैं और इस संबंध में आवेदन देकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब उनसे विद्युत लाइन जोड़ने की बात करते हैं तो वह आत्महत्या करने की धमकी देते हैं और हम लोगों को बुरा भला बोलते हैं। उन्होंने कहा कि गांव के सभी लोग डरे हुए हैं।

इस मामले की शिकायत करने के लिए जिला मुख्यालय आए हैं। उन्होंने आवेदन देकर मांग है कि विद्युत मंडल के कर्मचारियों को भेजकर अटल ज्योति योजना की बिजली चालू कराई जाए। साथ ही जो किसानों के खेतों तक लाइन गई है उसको भी चालू कराया जाए। करीब 50 परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं। जल्द से जल्द विद्युत सप्लाई चालू करने की मांग की है।

युवा संगम कार्यक्रम में विदिशा चौथे स्थान पर, कलेक्टर को मिला प्रशंसा पत्र

आज की जनधारा

विदिशा। युवा संगम कार्यक्रम में द्वारा बहुमूल्य योगदान के लिए रोजगार आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा की है। मध्यप्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में विदिशा जिला उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। रोजगार आयुक्त मप्र गिरीश शर्मा द्वारा माह मई 2026 में युवा संगम कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला, अप्रेंटिसशिप मेला एवं स्वरोजगार गतिविधियों में आकांक्षी युवाओं के लिए उल्लेखनीय कार्य करने पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता को प्रशंसा पत्र प्रेषित किया गया है। प्रदेश में विदिशा जिला रैंक-4 पर रहा। यह उपलब्धि जिले की टीम एवं युवाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है।

समीक्षा — समयावधि में समाधान कराना सुनिश्चित करें:कलेक्टर श्री गुप्ता

टीएल बैठक में विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति एवं लंबित प्रकरणों की व्यापक समीक्षा

आज की जनधारा

विदिशा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा आहूत समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, लंबित प्रकरणों, राजस्व मामलों तथा जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टोरेट के बेतवा सभागार में आयोजित इस बैठक में विभागवार प्रस्तुत की जाने वाली पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है।

बैठक में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग, केंद्रीय मंत्री एवं प्रभारी मंत्री से प्राप्त पत्रों तथा उनके उत्तरों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में प्रवेश की स्थिति, आईटीआई एवं एनआरसी भर्ती की प्रगति तथा लाड़ली बहना योजना के ट्रांजेक्शन फेल प्रकरणों की जानकारी इसके साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा तथा बंद एवं हैंडओवर की गई नल-जल योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दुकानों पर की गई कार्यवाहियों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में प्रवेश की स्थिति, घुमक्कड़ सर्वे की प्रगति तथा राहत राशि वितरण की समीक्षा भी की जाएगी। अंतर-विभागीय समन्वय से जुड़े विषयों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है।

जल संरक्षण और वर्षा प्रबंधन पर विशेष फोकस

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा साथ ही वर्षा ऋतु में जलभराव की समस्या को रोकने के लिए किए गए उपायों और तैयारियों का आकलन किया जाएगा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी कम से कम एक या दो आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा एक विद्यालय का निरीक्षण कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की समीक्षा। कृषि एवं राजस्व विषयों की समीक्षा अंतर्गत कृषि वर्ष के दौरान ग्रामवार सर्वेक्षण में प्राप्त आवेदनों और उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी ली जाएगी। किसानों को मूंग के स्थान पर उड़द की खेती के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी प्रयासों का मूल्यांकन किया गया है। कलेक्टर ने एपीसी बैठक के प्रमुख बिंदु की भी गहन समीक्षा की है। तदानुसार कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की गई है।

लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में शासकीय भूमि एवं भवनों पर विभागवार अतिक्रमण की स्थिति, अविवादित नामांतरण के 180 दिवस से अधिक लंबित प्रकरण, 45 दिवस से अधिक लंबित बंटवारे तथा 90 दिवस से अधिक लंबित सीमांकन प्रकरणों की एवं तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के राजस्व प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली गई है।

इस दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लंबित ऋण प्रकरणों की अघतन जानकारियां अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) द्वारा प्रस्तुत की गई वहीं ऐसे खातों की जानकारी जिनका समयोजन नहीं हुआ है। वहीं संस्थागत वित्त अधिकारी द्वारा तहसीलवार लंबित आरआरसी प्रकरणों का विवरण साझा किया गया है। शासन निर्देशों एवं पत्राचार की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सांसद व प्रभारी मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों स्तर के पालन प्रतिवेदन,जिला स्तरीय समितियों के सदस्यों के प्रभारी मंत्री द्वारा किए जाने वाले नामांकन की स्थिति, शासन को भेजे गए मांग पत्रों एवं अन्य पत्राचार की जानकारी ली जाएगी। समय अंतराल पर कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों, आदेशों तथा अर्द्धशासकीय (डीओ) पत्रों के उत्तरों की समीक्षा इसके अतिरिक्त विभागवार पौधारोपण प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई है।

उक्त समीक्षात्मक बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर जिला पंचायत सीईओ समेत विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे तो वहीं खंड स्तरीय अधिकारियों से विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद किया गया है।

महेश नवमीं के दूसरे दिन गौशाला में गौसेवा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

आज की जनधारा

विदिशा। महेश्वरी समाज विदिशा द्वारा महेश नवमीं के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सोमवार को गोपाल कृष्ण गौशाला में गौसेवा एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष गोविंद राठी, संरक्षक गोपाल दास राठी, नगर अध्यक्ष निलेश सुर्जन, महिला मंडल की जिलाध्यक्ष रेखा मालपानी, मार्गदर्शक मीना माहेश्वरी, प्रदेश सचिव दिनेश काबरा एवं कोषाध्यक्ष संजय राठी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नगर सचिव आशीष माहेश्वरी कोठारी ने बताया कि समाजजनों ने गौशाला में गौमाता की सेवा की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि आज 23 जून तीसरे दिन भगवान शिव के उत्पत्ति दिवस के अवसर पर भगवान श्री भोलेनाथ का अभिषेक एवं ब्लड डोनेशन कैम्प आयोजित होगा। वहीं शाम को महेश्वरी धर्मशाला से भव्य शोभायात्रा प्रारंभ होगी जो मुख्य मार्ग से होते हुए महेश्वरी भवन तलैया पहुंचेगी। जहां महाआरती के पश्चात प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। आशीष माहेश्वरी ने सभी से कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

आज की जनधारा City Dhara

मंगलवार 23 जून 2026. www.aajkijandhara.com

सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन बदलेगा अंदाज

पंडे-पुजारी और ड्राइवर सीखेंगे मेहमाननवाजी का मंत्र

उज्जैन। सिंहस्थ 2028 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार प्रशासन का फोकस सिर्फ घाट, सड़क और व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं के पूरे अनुभव को बेहतर बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन के पंडों, पुजारियों और ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को खास मेहमाननवाजी और व्यवहार की ट्रेनिंग देने की तैयारी शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र सिंहस्थ में हर बार देश-विदेश से लोग उज्जैन पहुंचते हैं। लेकिन कई बार श्रद्धालुओं को स्थानीय स्तर पर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पंडों के व्यवहार, पूजा व्यवस्था को लेकर शिकायतें और ऑटो-टैक्सी चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने जैसी समस्याएं आयोजन की छवि पर असर डालती रही हैं। इस बार प्रशासन इन चुनौतियों को पहले ही

खत्म करने की कोशिश में जुट गया है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इस जिम्मेदारी के लिए ग्वालियर स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) को चुना है। संस्थान पंडों, पुजारियों और ड्राइवरों को श्रद्धालुओं के साथ बेहतर संवाद, विनम्र व्यवहार और सेवा भावना का प्रशिक्षण देगा। योजना के दूसरे चरण में इसी तरह की ट्रेनिंग प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों से जुड़े लोगों को भी दी जा सकती है। प्रशिक्षण में पंडा समाज और पुजारियों को सिखाया जाएगा कि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं से किस तरह सम्मानपूर्वक बातचीत करें। तनाव या भीड़ के दबाव में धैर्य बनाए रखने, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की मदद करने तथा सही जानकारी उपलब्ध कराने जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं को उचित मार्गदर्शन देने की कला भी सिखाई जाएगी। वहीं ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए प्रशिक्षण का फोकस अलग होगा। उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग, प्राथमिक उपचार, यात्रियों से बेहतर व्यवहार, सही किराया लेने और पारदर्शिता बनाए रखने की जानकारी दी जाएगी। शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के साथ ही जीपीएस और वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। आईआईटीटीएम की डायरेक्टर मोनिका प्रकाश के अनुसार प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों के रहने और खाने की व्यवस्था संस्थान परिसर में ही की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें फील्ड विजिट भी कराई जाएगी, जिससे वे वास्तविक परिस्थितियों को समझ सकें और बड़े आयोजन के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो सकें। प्रशिक्षण के दौरान कई लोगों का रोजमर्रा का काम प्रभावित होगा, इसलिए सरकार प्रतिभागियों को आर्थिक सहायता भी देगी। ट्रेनिंग में शामिल लोगों को प्रतिदिन 400 से 500 रुपए तक का भत्ता देने की योजना है। विशेषज्ञों द्वारा व्यवहार कौशल, संवाद क्षमता, आपदा प्रबंधन और सेवा प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेष सत्र लिए जाएंगे। सिंहस्थ 2028 सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की पर्यटन छवि से भी जुड़ा बड़ा अवसर है। प्रशासन की कोशिश है कि उज्जैन आने वाला हर श्रद्धालु यहां से बेहतर अनुभव लेकर लौटे। यही वजह है कि इस बार तैयारियां सिर्फ सुविधाओं के निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन लोगों को भी तैयार किया जा रहा है जो सीधे श्रद्धालुओं से जुड़ेंगे। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले बड़े आयोजनों में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है।

पांच दिवसीय मानसून सत्र होगा हंगामेदार

नीट और राज्यसभा चुनाव पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

भोपाल। मप्र विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने राजनीतिक एजेंडे तय कर लिए हैं। कांग्रेस जहां नीट परीक्षा विवाद, राज्यसभा चुनाव में कथित गड़बड़ी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, वहीं राज्य सरकार का मुख्य फोकस समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक और अनुपूरक बजट को पारित कराने पर रहेगा। ये इस बात के संकेत है कि इस बार मानसून सत्र काफी हंगामेदार होगा। जानकारों का मानना है कि इस बार सदन में सबसे ज्यादा चर्चा यूसीसी और नीट परीक्षा को लेकर हो सकती है। हालांकि कांग्रेस यूसीसी का तीखा विरोध करने से बच सकती है और अपने हमलों का केंद्र युवाओं तथा रोजगार से जुड़े मुद्दों को बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश 25 जुलाई तक इसे विधानसभा से पारित कराने की है। भाजपा इसे सामाजिक समानता और कानूनी एकरूपता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। कांग्रेस का फोकस नीट और बेरोजगारी कांग्रेस ने सत्र के लिए जिन मुद्दों को प्रमुखता से चुना है, उनमें नीट परीक्षा में कथित अनियमितताएं, राज्यसभा चुनाव में नामांकन निरस्त होने का विवाद, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं शामिल हैं। पार्टी रणनीतिक रूप से यूसीसी को मुख्य मुद्दा बनाने से बच रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि यूसीसी पर अत्यधिक आक्रामक रुख अपनाने से सामान्य मतदाताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है और इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल सकता है। यूसीसी का प्रारूप तैयार, जनता से मांगे जा रहे सुझाव समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, प्रारंभिक मसौदा तैयार कर चुकी है।

जनजातीय समुदाय को प्रस्तावित छूट

यूसीसी के मसौदे में अनुसूचित जनजातीय समुदाय को विशेष छूट देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसके तहत जनजातीय समाज अपनी पारंपरिक संस्कृति, रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता रहेगा और यूसीसी की परिधि से बाहर रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही प्रावधान कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकता है। प्रदेश की बड़ी जनजातीय आबादी को छूट मिलने के कारण कांग्रेस के लिए यूसीसी का व्यापक विरोध करना आसान नहीं होगा।

सत्र में टकराव के आसार

मानसून सत्र भले ही केवल पांच दिन का हो, लेकिन नीट परीक्षा, राज्यसभा चुनाव विवाद, बेरोजगारी और यूसीसी जैसे मुद्दों के कारण सदन में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। सरकार जहां यूसीसी को ऐतिहासिक सुधार के रूप में पेश करेगी, वहीं कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में प्रदर्शित हुई 64 योगिनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री 64 - व्हिस्पर्स ऑफ द अनसीन

संस्कृति विभाग एवं काली ट्रस्ट के सहयोग से निर्मित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच

भोपाल। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (MIFF) 2026 मुंबई में कलाकार एवं साधक डॉ. बीना उन्नीकृष्णन की 64 योगिनी प्रदेश के मितावली स्थित मंदिर पर बनी डॉक्यूमेंट्री 64 - व्हिस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन हुआ। संस्कृति विभाग एवं काली ट्रस्ट के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहली बार प्रदर्शित की गई। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (Mumbai International Film Festival - MIFF) दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म समारोह है। यह विशेष रूप से वृत्तचित्र, लघु कथा और एनीमेशन फिल्मों को समर्पित है। इस अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण

मंत्रालय (MIB) के अतिरिक्त सचिव श्री प्रभात जी ने डॉ. बीना उन्नीकृष्णन एवं उनकी टीम को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री दीपक नारायण, एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दीप्ति चावला, डॉ. बीना उन्नीकृष्णन, सिनेमैटोग्राफर प्रदीप समेत अन्य अतिथियों की उपस्थिति रही। **हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं 64 योगिनी मंदिरः अपर मुख्य सचिव श्री शुक्ला-** मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा सामान्य प्रशासन श्री शिव शेकर शुक्ला ने कहा

कि मध्यप्रदेश के मितावली (मुरैना), जबलपुर और खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मितावली का 64 योगिनी मंदिर, जिसने भारत की पुरानी संसद भवन की वास्तुकला को प्रेरित किया, यह आज यूनेस्को विश्व की ऐतिहासिक धरोहर स्थल की अस्थायी सूचि में भी शामिल है। 'Y64 – Whispers of the Unseen' जैसी परियोजना इस अद्वितीय विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचा रही है। डॉ. बीना उन्नीकृष्णन की कलात्मक यात्रा के माध्यम से यह फिल्म युवाओं को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए सृजनशीलता, साहस, आत्म-अन्वेषण और स्त्री शक्ति जैसे सार्वभौमिक मूल्यों से परिचित कराती है। **64 योगिनियों ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, यह मेरा सौभाग्य : डॉ. बीना उन्नीकृष्णन-** डॉ. बीना उन्नीकृष्णन ने बताया कि लगभग साढ़े बारह वर्ष पूर्व उन्होंने 64 योगिनियों के चित्रांकन की प्रक्रिया को केवल एक दस्तावेज के रूप में संजोने की शुरूआत की थी, लेकिन समय के साथ यह प्रयास समर्पण, धैर्य और आत्म-परिवर्तन की प्रेरणादायक सिनेमाई यात्रा बन गया। इस वर्ष उन्होंने 64 मूल चित्रों के साथ भारत के 14 शहरों में लगभग 15,000 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर हजारों लोगों को योगिनी परंपरा से परिचित कराया तथा कला, संस्कृति और अध्यात्म पर व्यापक संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा, जब मैंने यह यात्रा शुरू की थी, तब मैं केवल उत्तर खोजती एक कलाकार थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक पुस्तक, प्रदर्शनी, हजारों किलोमीटर की यात्रा और अंततः एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का रूप ले लेगी। योगिनियों ने मुझे भय से परे जाना और अपने स्त्रीत्व तथा अदृश्य मार्ग पर विश्वास करना सिखाया। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने योगिनियों को नहीं चुना, बल्कि योगिनियों ने मुझे चुना है। उन्होंने बताया कि यह डॉक्यूमेंट्री केवल योगिनी मंदिरों के इतिहास और रहस्य को नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आह्वान को पूरा करने के लिए आवश्यक साहस और समर्पण की कहानी भी प्रस्तुत करती है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। **विरासत और संस्कृति का अद्भुत संगम है फिल्म-** 64 योगिनि मंदिरों से प्रेरित यह अनूठी फिल्म, संस्कृति, अध्यात्म और विरासत का अद्भुत संगम है। कंकाली ट्रस्ट और मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री भारत के योगिनी मंदिरों से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का उत्सव भी है। यह डॉक्यूमेंट्री दर्शकों को ऐसे संसार में ले जाती है, जहाँ कला, आस्था, इतिहास और आत्म-परिवर्तन एक-दूसरे से जुड़कर एक अद्वितीय अनुभव का निर्माण करते हैं।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने चीता मित्रों से किया संवाद, संरक्षण प्रयासों की सराहना

भोपाल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने अपने दो दिवसीय कूनो नेशनल पार्क प्रवास के दौरान सोमवार को चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण एवं जन-जागरूकता संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परियोजना से जुड़े स्वयंसेवी चीता मित्रों के समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए उनसे वन-टू-वन चर्चा की। चीता मित्रों ने राष्ट्रपति को बताया कि कूनो नेशनल पार्क से लगे सभी गांवों में उनकी सक्रिय टीम कार्यरत है, जो ग्रामीणों को चीतों की सुरक्षा तथा उनके व्यवहार के प्रति जागरूक कर रही है। ग्रामीणों को यह भी समझाया जा रहा है कि चीते सामान्यतः मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाते तथा उनके आबादी क्षेत्र में दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को

सूचना दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में चीतों की पुनर्बसाहट की यह महत्वाकांक्षी परियोजना जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने परियोजना की सफलता में स्थानीय समुदायों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उल्लेखनीय है कि कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्स्थापन योजना को साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है। वर्तमान में देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क तथा 3 मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण में हैं।

सवालों के घेरे में स्मार्ट कचरा प्रबंधन

भोपाल में 13.50 करोड़ के स्मार्ट डस्टबिन बदहाल

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट कचरा प्रबंधन के उद्देश्य से लगाए गए स्मार्ट डस्टबिन अब खुद सवालों के घेरे में हैं। भोपाल में साढ़े 13 करोड़ के स्मार्ट डस्टबिन बदहाल नजर आ रहे है। कई डस्टबिन कबाड़ हो गये है। जिससे रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे है। भोपाल स्मार्ट सिटी ने राजधानी में रियल टाइम कचरा कलेक्शन के लिए स्मार्ट डस्टबिन के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। इस योजना के तहत शहर में वर्ष 2018 में पहले चरण में 40 स्मार्ट बिन लगाए गए थे। बाद में शहर के विभिन्न स्थानों पर 150 अतिरिक्त स्मार्ट बिन लगाए थे। इस योजना के तहत कुल

190 स्मार्ट बिन लगाए गए थे, जिन पर लगभग 13.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इन बिन को रियल टाइम कचरा कलेक्शन सिस्टम से जोडने का दावा किया गया था, लेकिन कई स्थानों पर इनकी खराब स्थिति और उपयोगिता, रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रत्येक स्मार्ट बिन में सेंसर आधारित तकनीक लगाई गई थी जो कचरे का स्तर निर्धारित सीमा तक पहुंचने पर कंट्रोल रूम को सूचना भेजने वाली थी। इसके बाद संबंधित कचरा वाहन को अलर्ट जारी कर बिन खाली कराने की व्यवस्था बनाई गई थी। **कई डस्टबिन हो गए कबाड़-** स्मार्ट सिटी प्रशासन का दावा था कि इस व्यवस्था से कचरा संग्रहण अधिक प्रभावी होगा। परियोजना के दौरान यह भी बताया गया था कि एक स्मार्ट बिन में लगभग दो टन तक कचरा संग्रहित करने की क्षमता है। हालांकि वर्तमान में शहर के कई स्थानों पर लगे स्मार्ट बिन खराब, क्षतिग्रस्त या रखरखाव के अभाव में बदहाल दिखाई दे रहे हैं। कई स्मार्ट बिन न्यू मार्केट की मल्टी पार्किंग के पास के पास रखे स्मार्ट बिन जंग खा रहे है, कई डस्टबिन कबाड़ हो गए हैं।

मप्र का पावर नेटवर्क होगा और मजबूत

7,668 करोड़ के निवेश से बिछेंगी नई ट्रांसमिशन लाइनें

भोपाल। मध्यप्रदेश में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए बिजली ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए 14वीं ट्रांसमिशन विस्तार योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेश में करीब 7,668 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके जरिए 4,867 सर्किट किलोमीटर नई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी और 9,608 एमवीए अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता विकसित की जाएगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश में बढ़ती बिजली खपत, नए बिजली उत्पादन संयंत्रों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और राष्ट्रीय ग्रिड से बेहतर समन्वय को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क को अधिक सक्षम बनाना है। इसके लिए वित्तीय सहायता आरईसी, पीएसडीएफ, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण और राज्य सरकार के सहयोग से जुटाई जाएगी। एमपी ट्रांसको ने इसके अलावा 4,387 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं का प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसे मंजूरी के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आयोग के आदेश के बाद इन परियोजनाओं पर भी काम शुरू होगा। समयबद्ध परियोजनाओं पर विशेष फोकस कंपनी का कहना है कि ट्रांसमिशन लॉस कम करने, बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को

पूरा करने के लिए पांच वर्षीय कार्ययोजना बनाई गई है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निवेश स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) संबंधी समस्याओं के समाधान और लगातार मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एमपी ट्रांसको के अनुसार एडीबी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, केएफडब्ल्यू और जाइका की सहायता से संचालित कई परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी की जा चुकी हैं। लगभग 1,200 करोड़ रुपये की जाइका परियोजना मार्च 2024 में सफलतापूर्वक पूरी हुई थी। फाइबर नेटवर्क से बढ़ रही अतिरिक्त आय ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ विकसित किए गए 15 हजार किलोमीटर लंबे 24-फाइबर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर नेटवर्क से कंपनी को अतिरिक्त राजस्व भी मिल रहा है। इसमें से लगभग 11 हजार किलोमीटर नेटवर्क भारत सरकार की पीएसडीएफ योजना के तहत स्थापित किया गया है। कंपनी ने अपनी जरूरत के लिए 8 फाइबर सुरक्षित रखे हैं, जबकि शेष फाइबर को व्यावसायिक उपयोग के लिए निजी कंपनियों को लीज पर दिया जा रहा है। पहले चरण में 9,250 फाइबर-पेयर किलोमीटर नेटवर्क लीज पर दिया जा चुका है और दूसरे चरण की प्रक्रिया जारी है।

48 साल बाद भी अधर में 22 अभयारण्यों की अंतिम अधिसूचना

इको-सेंसिटिव जोन घोषित न होने से संरक्षण व्यवस्था कमजोर, अवैध खनन-निर्माण से वन्यजीवों पर बढ़ा खतरा

भोपाल। मध्यप्रदेश के अधिकांश अभयारण्यों की सीमाओं का अंतिम निर्धारण और अधिसूचना दशकों बाद भी लंबित है। इसका सीधा असर वन्यजीव संरक्षण पर पड़ रहा है। अंतिम अधिसूचना नहीं होने के कारण कई अभयारण्यों के आसपास अवैध निर्माण और खनन गतिविधियां जारी हैं, जबकि ये क्षेत्र अब तक इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 26 अभयारण्यों में से 22 की अंतिम अधिसूचना अब तक जारी नहीं हो सकी है। इनमें कुछ अभयारण्यों के मामले 40 से 48 वर्ष पुराने हैं। बताया गया है कि चंबल क्षेत्र में आने वाले घाटीगांव और केन घडियाल सेंचुरी का अंतिम नोटिफिकेशन 1981 से लंबित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को 1982 से अब तक इंतजार करना पड़ रहा है। हैरानी वाली बात तो ये है कि इन सभी अभयारण्यों की अंतिम सूचना वन विभाग के रिकार्ड से नदारत है। जानकारी के अनुसार जब किसी वन्य क्षेत्र को अभयारण्य के तौर पर चिन्हित किया जाता है, तो उसके लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद अभयारण्यों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, जिसमें संबंधित जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और वन विभाग की अहम भूमिका होती है। इनके द्वारा सीमा चिन्हित कर अभयारण्यों की अंतिम अधिसूचना जारी की जारी है। इसके उपरांत

अधिसूचित क्षेत्र में पूरी तरह से खनन या निर्माण जैसे कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा निर्धारण और अंतिम नोटिफिकेशन में देरी के कारण संरक्षित क्षेत्रों की वास्तविक सीमाएं स्पष्ट नहीं हो पातीं, जिसका फायदा अवैध गतिविधियों में लगे लोगों को मिलता है। मप्र के अधिकांश अभयारण्यों के आसपास अवैध निर्माण और खनन किया जा रहा है, जिससे ये क्षेत्र जहां इको-सेंसिटिव जोन नहीं बन पा रहे हैं, तो वहीं वन्यजीवों के जीवन पर भी खतरा मडरा रहा है। इसकी मूल वजह अभयारण्यों की सीमाओं का निर्धारण करने अंतिम अधिसूचना जारी नहीं होना है।

सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों का भी पूरा पालन नहीं

सुप्रीम कोर्ट संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास इको-सेंसिटिव जोन बनाए जाने की आवश्यकता पर स्पष्ट निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में अभयारण्य अंतिम अधिसूचना के अभाव में इस व्यवस्था से बाहर हैं। इससे पर्यावरणीय सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण दोनों प्रभावित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार घाटीगांव अभयारण्य, केन घडियाल अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जैसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना 1981-82 से लंबित है। बताया जाता है कि कई मामलों में अंतिम अधिसूचना संबंधी रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं हैं।

तीन विभागों के बीच तालमेल की कमी

सूत्रों के मुताबिक अभयारण्यों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया में जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त भूमिका होती है। लेकिन इन विभागों के बीच समन्वय की कमी के चलते कई अभयारण्यों का सीमा निर्धारण वर्षों से अधूरा पड़ा है।

न्यूज । ब्रीफ

भाजपा जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापना की पहल

दमोह। भारतीय जनता पार्टी दमोह के जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर दमोह नगर में भारत के महान राष्ट्रनायक एवं प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने की पहल की है। जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान वर्ष पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे गौरवपूर्ण अवसर पर उनकी प्रतिमा की स्थापना न केवल उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि यह उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम भी बनेगी। पं. मुखर्जी भारतीय राजनीति के ऐसे आधार स्तंभ हैं, जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जम्मू-कश्मीर में ह्लएक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशानह्व के विरोध में उनका संघर्ष आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। दमोह नगर में उनकी प्रतिमा स्थापित होने से युवाओं को राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण की प्रेरणा मिलेगी तथा आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों से जुड़ सकेंगी। शासन-प्रशासन से आग्रह किया कि नगर के प्रमुख स्थान पर पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान का सम्मान किया जाए। उक्त पत्र की प्रतिलिपियां भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, दमोह जिला प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, दमोह सांसद राहुल सिंह एवं दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव को भी प्रेषित की गई हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया

पथरिया (दमोह)। जिसमें विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं पतंजलि योग पीठ के गंगाराम पटेल, सुरेश रैकवार, स्वदेश चौरसिया,नरेश राठौर एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप पटेल की गरिमामय उपस्थिति रही। विद्यालय के प्राचार्य केदार विदौलिया जी द्वारा योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंत में रमाशंकर पौराणिक द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया एवं विद्यालय एवं नगर में चल रहीं निःशुल्क योग कक्षाओं की जानकारी दी गई।

नव जागृति एवं शासकीय सरदार पटेल विद्यालयों की टीमों ने किया श्रमदान

दमोह। क्लीन बेलाताल के तहत नव-जागृति स्कूल दमोह एवं शासकीय सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह की टीम ने 22 जून सोमवार को टीम उम्मीद के साथ स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रतिदिन दो ट्राली प्लास्टिक कचरा बेलाताल से मुक्त किया जा रहा है, साथ ही कार्यक्रम में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के भाग लेने से आम जनता तक प्लास्टिक कचरा से होने वाले नुकसान एवं जन जागरूकता का माहौल तैयार हो रहा है। जहां एक और बेलाताल को पुराने प्लास्टिक कचरे से मुक्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग कचरा न डालें इसके लिए भी कार्य जारी है।

राज्यमंत्री लोधी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएं, त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

नोहटा कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान विभिन्न ग्रामों से पहुंचेए ग्रामीणों से की आत्मीय भेंट

आज की जनधारा

दमोह। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने आज कार्यालय नोहटा में जबेरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से पधारे क्षेत्रवासियों से आत्मीय एवं सौजन्यपूर्ण भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न जनहित एवं स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया गया, जिन्हें गंभीरतापूर्वक सुना एवं उनकी प्राथमिकता के आधार परे त्वरित निराकरण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान दिए।

वाणा तालाब में मुरम उत्खनन पर उठे सवाल, जन भगदीरी की वजह मशीनों से काम

आज की जनधारा

जबेरा (दमोह)। तहसील मुख्यालय जबेरा में इन दिनों वाणा तालाब से मुरम और मिट्टी का अवैध उत्खनन व बिना रॉयल्टी के परिवहन धड़ल्ले से जारी है। हैरत की बात यह है कि यह पूरा खेल जनपद कार्यालय, जबेरा थाना और कोरता मेन रोड के बिल्कुल नजदीक, दिन के उजाले में खेला जा रहा है। तालाब के गहरीकरण के नाम पर जेसीबी मशीनों से बड़े पैमाने पर खुदाई की जा रही है और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए इस कीमती मुरम को निजी मकानों की पुराई व अन्य निर्माण कार्यों के लिए ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। ईमानदार अधिकारी पर गिरी गाज, माफिया को राजनीतिक संरक्षण! स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यह विवाद नया नहीं है। कुछ समय पूर्व भी जब स्थानीय पत्रकारों ने इस अवैध कारोबार को उजागर किया था, तब उत्खनन माफिया गोविंद सिंह लोधी और राहुल सिंह लोधी ने पत्रकारों से अभद्रता की थी, जिसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद जब तत्कालीन निडर और ईमानदार तहसीलदार सोनम पांडे ने मामले की तहकीकात की और माफियाओं से उत्खनन की अनुमति (अनुग्रह पत्र) मांगी, तो वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। लापरवाही और अवैध कृत्य पाए जाने पर तहसीलदार ने मुस्तैदी दिखाते हुए दो जेसीबी और तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त करने की कड़ी कार्रवाई की थी। परंतु, राजनैतिक रसूखदारों के दबाव में न झुकने का खामियाजा अंततः महिला अधिकारी को भुगतना पड़ा और उनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया गया। क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का कहना है कि यदि प्रशासनिक अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की सजा इस तरह तबादले के रूप में मिलेगी, तो सिस्टम में निष्पक्षता कैसे बचेगी? नेताओं को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अवैध उत्खनन का विरोध करने पर ग्रामीणों को किया लहूलुहान- प्रशासन की सुस्ती से बेखौफ माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे खूनी खेल पर आमादा हैं, हाल ही में जबेरा निवासी देवी प्रसाद शर्मा ने इस अवैध मुरम विक्रय का विरोध करने की हिम्मत दिखाई, तो जेसीबी संचालक डालसिंह लोधी और उसके साथियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया पीड़ित देवी प्रसाद शर्मा ने बताया कि रात्रि करीब 10 बजे जब वे अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी डालसिंह लोधी ने उन्हें रोका और काम की शिकायत करने पर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते डालसिंह और उसके साथियों ने उन पर प्राणघातक हमला बोल दिया।

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ के हमले में युवक घायल, ग्रामीणों को किया गया सतर्क

पटना मोहली गांव में खेत पर कार्य के दौरान हुई घटना, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

आज की जनधारा

दमोह। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के मोहली परिक्षेत्र अंतर्गत पटना मोहली गांव में सुदामा यादव नामक 32 वर्षीय युवक को आज 22 जून को प्रातः 06 बजे के लगभग उसके खेत में बाघ द्वारा हमला करके घायल कर दिया गया। श्री यादव के चिल्लाने पर समीप के गांव वाले आवाज करते हुए आए और उनकी आवाज से बाघ जंगल की ओर भाग गया। स्थानीय बीट गार्ड और अन्य वन कर्मियों द्वारा सुदामा को रहली शासकीय अस्पताल ले जाया गया। जहां उसका उपचार चल रहा है सुदामा को हाथ में और कमर में चोट आई है। उन्हें सागर जिला चिकित्सालय हेतु रेफर कर दिया गया है। पटना मोहली गांव मे मुनादी करके अन्य ग्रामीणों को भी सचेत रहने बाबत समझाइश दी जा रही है।

वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर आयोजित, कार्यक्रम की तैयारियों का संस्कृति मंत्री श्री लोधी ने किया निरीक्षण

आज की जनधारा

दमोह। प्रदेश संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जबेरा विधानसभा अंतर्गत स्थित खेल स्टेडियम सिंग्रामपुर में आगामी 24 जून को महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के पश्चात राज्यमंत्री श्री लोधी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया तथा सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध, सुव्यवस्थित एवं गरिमामय ढंग से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए।

उन्होंने कहा रानी दुर्गावती जी का बलिदान साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन उनकी गौरवशाली विरासत के अनुरूप भव्यता एवं श्रद्धा के साथ किया जाए। उन्होने कहा 24 जून को आयोजित होने वाले बलिदान दिवस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे तथा उनके अद्वितीय शौर्य एवं बलिदान का स्मरण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फुलपगारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, जनपद सीईओ, रुपेश सेन, सत्येंद्र ठाकुर विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

615 करोड़ की नल-जल योजना अधूरी, कई गांवों में टंकियां बनीं शोपीस

आज की जनधारा

पचोर/राजगढ़। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना सारंगपुर विकासखंड के कई गांवों और पड़ाना नगर में अभी तक पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सकी है। करोड़ों रुपये की लागत से चल रही नल-जल परियोजना की समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद अनेक स्थानों पर कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों और नगरवासियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कुंडालिया वृहद बांध से सारंगपुर ब्लॉक के पड़ाना नगर सहित 190 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल निगम राजगढ़ द्वारा लगभग 615.34 करोड़ रुपये की लागत से सतह स्रोत आधारित ग्रामीण समूह नल-जल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। परियोजना का क्रियान्वयन एलएंडटी कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने से योजना की प्रगति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्षेत्र के साधनखेड़ी, नारायणपुर (कोलूखेड़ा), बिलोदा पुरबिया, ईचीवाड़ा सहित कई गांवों में जल टंकियां बनकर तैयार हैं, लेकिन आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। हाल ही में आयोजित रात्रिकालीन जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई था। सोमवार को जल निगम राजगढ़ के डिप्टी मैनेजर रवि यादव एवं

एलएंडटी कंपनी के मैनेजर देवेंद्र कुमार ने पड़ाना नगर का निरीक्षण कर विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान गांधी चौक, बस स्टैंड, सदर बाजार, हाट बाजार और आवास कॉलोनी क्षेत्र में पाइपलाइन संबंधी समस्याओं तथा अधूरे निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया। जनपद सदस्य प्रतिनिधि सोनू मंसूरी एवं स्थानीय नागरिकों ने अधिकारियों को बताया कि नगर के कई हिस्सों में अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। सदर बाजार के एक ओर पाइपलाइन का कार्य अधूरा पड़ा है, जबकि पूर्व में शीघ्र कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था। लोगों ने यह भी बताया कि पाइपलाइन टेस्टिंग के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कई मोहल्लों में आज तक नलों से पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई कई सड़कों की मरम्मत भी नहीं कराई गई, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पथरिया में अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत, शिनाख्त में जुटी पुलिस

दमोह। जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में बुरी तरह चोटिल हो गया। घायल को तत्काल पथरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया।मृतक की पहचान अभी अज्ञात है। पुलिस शिनाख्त करने में लगी हुई है। मौके पर एएसआई सुनील मिंज मौजूद थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

युवा भाजपा नेता रवि शर्मा के जन्मोत्सव पर उमड़ा जनस्नेह, शुभकामनाएं देने उमड़े सैकड़ों समर्थक

आज की जनधारा

पचोर/राजगढ़। भारतीय जनता पार्टी के युवा एवं लोकप्रिय नेता, पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा रवि सत्यप्रकाश शर्मा का जन्मदिवस नगर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय अग्रवाल मैरिज गार्डन में रविवार को आयोजित जन्मोत्सव समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर श्री शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। समारोह के दौरान ढोल-नगाड़ों की गूंज और उत्साहित कार्यकर्ताओं के जयघोष से पूरा वातावरण उत्सवमय बना रहा। उपस्थित लोगों ने पुष्पमालाएं पहनाकर रवि शर्मा का स्वागत किया तथा केक काटकर उनके दीर्घायु, स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना की। जन्मदिवस समारोह में दिनभर शुभेच्छुओं का आगमन जारी रहा और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। रवि शर्मा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी द्वारा सौंपी गई विभिन्न जिम्मेदारियों का निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ निर्वहन कर संगठन में अपनी अलग पहचान बनाई है। कार्यकताओं के बीच उनकी सहजता, सरलता और मिलनसार व्यक्तित्व उन्हें लोकप्रिय बनाता है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने के कारण भी वे क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। विभिन्न धार्मिक आयोजनों, सेवा कार्यों और जनहित के कार्यक्रमों में वे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मां दयालु के प्रति उनकी गहरी आस्था है और वे धार्मिक गतिविधियों में निरंतर सहभागिता निभाते रहे हैं। जन्मोत्सव समारोह में विधायक प्रतिनिधि

सारंगपुर पृथ्वीराज टेटवाल, नगर परिषद अध्यक्ष विकास करोड़िया, भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास दीक्षित, जगदीश नागर, दामोदर लहरी, अजय विजयवर्गीय, मनमोहन गुरगेला, पुरुषोत्तम वैष्णव, राजेश पालीवाल, सीताराम लहरी, राजेश भारतीय, गोलू भंडारी, रघुराज राणा, राधेश्याम गुर्जर, महेश नागर, सुदर्शन सोनी, अरुण खत्री, अमित गोस्वामी, दीपक चौहान, विजय साहू, जगदीश सोनी, विकास शर्मा, भूपेंद्र ठाकुर, राजकुमार जुलानिया, अजय शर्मा, शैलेंद्र मालवीय, संजय भंडारी, सतीश राठौर सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

नरसिंहगढ़ के ऐतिहासिक गुप्तेश्वर-छोटे महादेव क्षेत्र में घोर लापरवाही: सफेद गज हाथी की समाधि क्षतिग्रस्त, सुरक्षा व्यवस्था नदारद

आज की जनधारा

नरसिंहगढ़। छोटे महादेव पर गुप्तेश्वर के बाजू में सफेद गज हाथी की समाधि राजा महाराजा स्टेट टाइम से लगाई गई थी पुरातत्व विभाग ने इसमें ग्रेनाइट पत्थर से लख रुपए का पत्थर चाहिए कोई सुरक्षा नहीं कोई कुछ नहीं और चोर उचक्के शराबियों ने तोड़ दिया फॉरेस्ट के अधिकारी कोई भी सुरक्षा छोटे महादेव गुप्तेश्वर बड़े महादेव पर नहीं है पुरातत्व विभाग की और फॉरेस्ट वन विभाग की कोई भी सुरक्षा नहीं है कोई भी क्या कर रहा है जंगल जल रहा है थोड़ा थोड़ी कर रहा है गदर मचा रहा है लापरवाही लापरवाही भारती जा रही है प्रशासन का कोई डर नहीं खाने को पर्यटक स्थल है और उसकी कोई सुरक्षा नहीं स्टेट टाइम का

इतिहास हकीकत आपको पूरी तरह बताया जाएगा अब प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं नरसिंहगढ़ गुप्तेश्वर छोटा महादेव हाथी समाधि क्षतिग्रस्त कर दी कर चक्की शराबी लोगों ने आए दिन जंगल जल रहा है कोई लापरवाही घोर लापरवाही लापरवाही चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

आज की जनधारा

आज की इस आधुनिक तनावग्रस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में योग ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है इसी महत्व को समझाते हुए आज दिनांक-21/06/2026 को शास.उच्च. माध्यमिक विद्यालय कुमेरियां में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मानीय सरपंच महोदय श्री राधे जी ने की साथ ही साथ ल्र२२ कुमेरिया प्राचार्य श्री राजेंद्र राठौर जी सहित समस्त स्टाफ, माध्यमिक विद्यालय प्रभारी कुमेरिया से श्री राजेंद्र पटेल एवं उनका स्टाफ, व उपस्वास्थ्य केन्द्र कुमेरिया से अठट श्री मती लक्ष्मी कुर्मी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं तथा छात्र छात्राओं सहित ग्रामवासियों ने पूर्ण मनोयोग

से अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। जिसमें ल्र२२ कुमेरिया की योग प्रभारी के रूप में श्री मती कल्पना पटेल (उच्च. माध्यमिक शिक्षक) के द्वारा योग की जानकारी देकर योगाभ्यास का महत्व बताते हुए विभिन्न योगाभ्यास अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ताड़ासन, सूर्यनामकार के 12 आसनों सहित कई आसनों का महत्व बतलाकर अभ्यास कराया गया।

शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मरों की हुई क्षमतावृद्धि

शहर के विद्युत उपभोक्ताओं से पिछले कुछ दिनों से विद्युत व्यवधान की शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं। जिसे अधीक्षण अभियंता अमित चौहान ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल दमोह (शहर) के मेनटेनेंस प्रभारी कनिष्ठ अभियंता एम. एस. राय को निर्देश दिए।

आज की जनधारा

दमोह। शहर के विद्युत उपभोक्ताओं से पिछले कुछ दिनों से विद्युत व्यवधान की शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं। जिसे अधीक्षण अभियंता अमित चौहान ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल दमोह (शहर) के मेनटेनेंस प्रभारी कनिष्ठ अभियंता एम. एस. राय को निर्देश दिए। जिसके परिपालन में श्री राय के निर्देशन में ऊर्जा विभाग दमोह के कर्मचारियों द्वारा शहर के अभिनव होम्स क्षेत्र में स्थापित 100 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि कर 200 के.व्ही.ए. का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। जिससे अभिनव होम्स, सुरेखा कालोनी एवं आसपास के क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया गया। अधीक्षण अभियंता श्री चौहान ने बताया साथ ही महाकाली चौराहा, छोटा नृसिंह मंदिर क्षेत्र में स्थापित 100 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि कर 200 के.व्ही.ए. का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। जिससे महाकाली चौराहा, नृसिंह मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया गया। उन्होने बताया इसके साथ ही टण्डन बगीचा क्षेत्र में स्थापित 200 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। क्षेत्रवासियों से विद्युत व्यवधान की शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं। जिसे दृष्टिगत रखते हुए टण्डन बगीचा में में डिग्री कालेज के पीछे एक अतिरिक्त 100 के व्ही.ए. ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई। जिससे टण्डन बगीचा एवं आसपास के क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। दमोह शहर की सुचारू विद्युत व्यवस्था के उद्देश्य से घंटाघर स्थित 200 के.व्ही.ए. आनंद वाला ट्रांसफार्मर, बड़ी देवी मंदिर रेल्वे फाटक के पास 200 के.व्ही.ए. गंगाराम ट्रांसफार्मर एवं नृसिंह मंदिर 200 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर का मेनटेनेंस भी किया गया। इससे घंटाघर, मेन मार्केट, बूंदाबहु मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, फुटेरा फाटक, नृसिंह मंदिर तथा आसपास के क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, विद्युत उपभोक्ताओं को 24७7 के आधार पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग कृत संकल्पित है, अधीक्षण अभियंता श्री चौहान ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे विद्युत व्यवधान के दौरान धैर्य बनाये रखकर कंपनी को सहयोग प्रदान करें।

राजीव वार्ड में विकास कार्यों की सौगात, अर्चना चिटनिस एवं माधुरी पटेल ने किया लोकार्पण

आज की जनधारा

बुरहानपुर। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस तथा महापौर माधुरी अतुल पटेल ने वार्ड क्रमांक 39 राजीव वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगात दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता : अर्चना चिटनिस- लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए अर्चना चिटनिस ने कहा कि बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनका संकल्प है। नगर के प्रत्येक वार्ड में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास

का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। शहर के पुराने क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं नए क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास कार्यों को गति दी जा रही है।

तीन सीसी रोड निर्माण कार्यों का हुआ लोकार्पण- इस अवसर पर लगभग 11 लाख रुपये की लागत से निर्मित किशोर भंगार वाले के घर से सामुदायिक शौचालय तक सीसी रोड निर्माण कार्य, 5 लाख रुपये की लागत से निर्मित रमेश चक्कीवाले के घर से पुनमचंद पटेल के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य तथा 3 लाख रुपये की लागत से निर्मित नारायण रघुनाथ के घर से गोपाल पटेल के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन निर्माण कार्यों से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी तथा नागरिकों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी।

वार्डवासियों ने पुष्पवर्षा कर किया स्वागत- लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान वार्डवासियों ने अर्चना चिटनिस एवं माधुरी पटेल का पुष्पवर्षा कर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। क्षेत्र के नागरिकों ने विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निर्माण कार्यों से वार्ड की मूलभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। विकास के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम : धनराज महाजन- पार्षद धनराज महाजन ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि राजीव वार्ड के लिए यह गौरव का विषय है कि अर्चना चिटनिस के नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्डवासियों द्वारा रखी गई जनसुविधाओं और विकास कार्यों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृतियां प्रदान की गईं और उन्हें धरातल पर उतारा गया। उन्होंने कहा कि आज सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वह जनप्रतिनिधियों की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। माधुरी पटेल के सहयोग से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जनहित के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

सीईओ जिला पंचायत कूमट ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक की

आज की जनधारा

उज्जैन। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट ने सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि शिकायतों के निराकरण में इस बार उज्जैन जिला छठवें स्थान पर है। बैठक में ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अधिक लंबित शिकायतें प्राप्त होने पर इनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए गए। जन आकांक्षा, सुशासन की पहल के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय सीमा में किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत तराना और खाचरौद में लंबित प्रकरण पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध संयंत्र स्थापित करने की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

उज्जैन में डीपटेक रिचर्स एंड डिस्कवरी सेंटर खुलने की प्रक्रिया तेज हुई

आज की जनधारा

उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए उज्जैन में डीपटेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर खोलने के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। सेंटर को जल्दी प्रारंभ करने के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। मध्यप्रदेश विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री एम. सेलवेंद्रन के साथ संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह की बैठक हुई । बैठक में मध्यप्रदेश विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी के साथ ही आईआईटी की टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश को विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख निवेश (लीड इन्वेस्टमेंट) आकर्षित करने के लिए विशेष कार्य योजना के साथ उज्जैन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए नई कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत

डीपटेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर उज्जैन में खोला जाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के बाद सोमवार को प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री एम. सेलवेंद्रन, मध्यप्रदेश विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी के साथ आईआईटी की टीम के सदस्यों के साथ उज्जैन पहुंचकर संभागायुक्त श्री आशीष सिंह और कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के साथ तारामंडल पर सेंटर की स्थापना को लेकर बैठक आयोजित की गई।

तराना के ग्राम कावलीखेड़ा में जनभागीदारी से तालाब का गहरीकरण सफलतापूर्वक किया गया

आज की जनधारा

उज्जैन। जनपद पंचायत तराना अंतर्गत ग्राम पंचायत कावलीखेड़ा में जनभागीदारी के माध्यम से तालाब गहरीकरण का कार्य पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण एवं कृषि विकास की एक उत्कृष्ट सफलता की कहानी लिखी गई है। यह कार्य बिना किसी सरकारी खर्च के पूर्ण रूप से जन सहयोग से संपन्न हुआ है, जो सामुदायिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाता है। ग्राम पंचायत कावलीखेड़ा के पुराने तालाब में वर्षों से उपयोग के दौरान मिट्टी जमा हो गई थी, जिससे जलधारण क्षमता में भारी कमी आ

गई थी। ग्रीष्मकाल में जल संकट गहराने लगा था और किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इस समस्या को देखते हुए सरपंच एवं सचिव ने मिलकर जनभागीदारी के माध्यम से तालाब गहरीकरण करने का निर्णय लिया। ग्राम पंचायत कावलीखेड़ा के तालाब में जनभागीदारी से लगभग 600 घन मीटर मिट्टी निकाली गई। इससे तालाब की जलधारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे वर्षा जल का बेहतर संरक्षण संभव हो सकेगा और किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधा बढ़ गई है। इस कार्य से जल संरक्षण और कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। इससे भूजल स्तर में सुधार की संभावना भी प्रबल हुई है।

मोहर्रम एवं कानून-व्यवस्था की तैयारियों को मजबूती

कोटवारों और नगर सुरक्षा समिति सदस्यों का 7 दिवसीय एसपीओ प्रशिक्षण संपन्न

आज की जनधारा

बुरहानपुर। आगामी मोहर्रम पर्व, विभिन्न धार्मिक आयोजनों तथा कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बुरहानपुर पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा कोटवारों एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए आयोजित सात दिवसीय विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया। प्रशिक्षण रेणुका पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को पुलिस कार्यप्रणाली, भीड़ नियंत्रण, अनुशासन, परेड, सलामी, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह तथा पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक प्रदीप शेण्डे एवं नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

अपराध नियंत्रण में कोटवारों की भूमिका होगी महत्वपूर्ण : आशुतोष बागरी- समापन समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने कहा कि कोटवार गांवों में प्रशासन और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अपराध होने के बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सूचनाएं अपराधियों तक पहुंचने और अपराधों के खुलासे में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में होने वाली गतिविधियों और चचाओं से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस तक पहुंचाकर कोटवार अपराध नियंत्रण में प्रभावी सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक थाने में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कोटवारों के निरंतर संपर्क में रहेगा। साथ ही सभी कोटवारों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, ताकि सूचना आदान-प्रदान और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नई वर्दी से कोटवारों का आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों का और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे।

सूचना तंत्र की सबसे अहम कड़ी हैं कोटवार : हर्ष सिंह- कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में सूचना तंत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है और इस व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी कोटवार हैं। किसी संभावित घटना या स्थिति की जानकारी समय पर प्रशासन तक पहुंचना कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सात दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कोटवारों को अनुशासन, परेड, सलामी, प्रशासनिक समन्वय एवं पुलिस कार्यप्रणाली की बारीकियों से अवगत कराया गया है। अब वे पुलिस विभाग के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। ग्रामीणों के प्रति जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें : अर्चना चिटनिस- समापन समारोह में उपस्थित अर्चना चिटनिस ने कोटवारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी गांव के आम नागरिकों के प्रति है। उन्होंने कहा कि कोटवार यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा उनका व्यवहार जनहित और सेवा भावना से परिपूर्ण हो। उन्होंने कोटवारों से नई जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रशासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाकर वे समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए इस अभिनव प्रयास की सराहना भी की। बड़ी संख्या में अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित- प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन विजय गुप्ता ने किया।

4 लाख के 13 गुम मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद, मालिकों के खिले चेहरे

आज की जनधारा

भाटपचलाना पुलिस मुख्यालय भोपाल और उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में गुम संपत्तियों की बरामदगी और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भाटपचलाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करणदीप सिंह और एसडीओपी खाचरौद आकांक्षा बेछोटे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सत्येन्द्र सिंह चौधरी और उनकी टीम ने तकनीकी सहायता से करीब 4 लाख रुपये कीमत के 13 गुमशुदा मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। पुलिस ने भारत सरकार के CEIR (Central EQuipment

Identity REGister) पोर्टल और आधुनिक सर्विलांस तकनीकों का सटीक उपयोग करते हुए इन डिवाइसों को अलग-अलग क्षेत्रों से ट्रेस किया। थाना परिसर में जब आवेदकों को उनके खोए हुए कीमती मोबाइल और लैपटॉप वापस मिले, तो उनके चेहरों पर खुशी लौट आई। सभी ने तत्परता से कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन का आभार जताया। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी सत्येन्द्र सिंह चौधरी, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र सिंह सिसोदिया, आरक्षक विजय जाट, आरक्षक मुकेश नागर, हितेश निम्बोला, आरक्षक सुनील चौधरी और आरक्षक उदय यादव की मुख्य और सराहनीय भूमिका रही।

योग भगाए रोग : प्रो विष्णु नारायण सक्सेना योग भारतीय जीवन शैली का हिस्सा : डॉ शीतल कुमार

आज की जनधारा

उज्जैन। योग दिवस के अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में योग सत्र का आयोजन नवांकुर श्रीम गुरुकुल , जन अभियान परिषद द्वारा कियागया, जिसमें पाणिनी विश्वविद्यालय से आए हुए योगाचार्यों ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनों को योग कराया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के एवं विद्यार्थी परिषद भाग अध्यक्ष प्रो. विष्णु नारायण सक्सेना ने विद्यार्थियों को अनुशासन पूर्वक योगाभ्यास करने के टिप्स दिए आपने विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के लिए योग का अभ्यास करते रहने का मार्गदर्शन दिया। वही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विद्यार्थी परिषद के महानगर अध्यक्ष

डॉ. शीतल कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारतीय संस्कृति की विजय पताका चहुं और फैलाने का माध्यम बताया। आपने विद्याथीयों को योग अभ्यास के माध्यम से शारीरिक ,मानसिक, आध्यात्मिक विकास हेतु योग को आवश्यक बताया। इस अवसर पर श्रीम गुरुकुल की ओर से श्री कौस्तुभ शर्मा द्वारा कार्यक्रम के अंत में आभार ज्ञापित किया गया।

उज्जैन NEET परीक्षा में उज्जैन पुलिस बनी विद्यार्थियों की संबल : आधार कार्ड भूलने वाली छात्राओं को तत्काल प्रिंट उपलब्ध कराया

आज की जनधारा

उज्जैन। NEET परीक्षा में उज्जैन पुलिस बनी विद्यार्थियों की संबल : आधार कार्ड भूलने वाली छात्राओं को तत्काल प्रिंट उपलब्ध कराया, अस्वस्थ छात्रा को त्वरित सहायता देकर परीक्षा में कराया शामिल। आज दिनांक को आयोजित नीट (NEET) परीक्षा के दौरान जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा हेतु पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान उज्जैन पुलिस द्वारा मानवीय संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए कई विद्यार्थियों की समय रहते सहायता की गई। परीक्षा केंद्र पर पहुंचीं लगभग चार छात्राएं अपना आधार कार्ड घर पर भूल गई थीं, जिसके कारण उनके परीक्षा में सम्मिलित होने में कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। परीक्षा ड्यूटी में तैनात निरीक्षक गगन बादल के निर्देशन पर सहायक उप निरीक्षक

चंद्रभान सिंह चौहान व प्रधान आरक्षक मनीष यादव द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए छात्राओं के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया तथा व्हाट्सएप के माध्यम से आधार कार्ड की प्रति मंगवाई गई। इसके पश्चात तत्काल प्रिंट आउट की व्यवस्था कर छात्राओं को उपलब्ध कराया गया, जिससे वे निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकीं। इसी प्रकार एक छात्रा की परीक्षा केंद्र के निकट अचानक तबीयत खराब हो गई। सूचना प्राप्त होते ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल पुलिस पेट्रोलिंग वाहन के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई तथा छात्रा को आवश्यक सहयोग एवं प्राथमिक मदद प्रदान की गई, जिससे उसकी स्थिति सामान्य हो सकी। उज्जैन पुलिस द्वारा परीक्षा के दौरान किए गए इन मानवीय एवं संवेदनशील प्रयासों की विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं आमजन द्वारा सराहना की गई। अभिभावकों ने कहा कि पुलिस की तत्परता एवं सहयोगात्मक रवैये के कारण विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण भविष्य प्रभावित होने से बच गया। उज्जैन पुलिस सदैव कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों की सहायता एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार आमजन की हरसंभव सहायता हेतु तत्पर रहेगी।

तापी मिल कर्मचारियों के 11 माह से लंबित वेतन के मुद्दे पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटील की दिल्ली में निर्णायक पहल

आज की जनधारा

बुरहानपुर। गोपाल देवकर। तापी मिल (नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन-एनटीसी) बुरहानपुर के सुरक्षा कर्मियों सहित अन्य कर्मचारियों के लगभग 11 माह से लंबित वेतन के मुद्दे को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने एक बार फिर गंभीर पहल करते हुए नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए सांसद ने इस विषय को प्राथमिकता से उठाया और शीघ्र समाधान की मांग की। कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा- नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव से हुई महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने तापी मिल कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार से रखा। उन्होंने बताया कि मिल के सुरक्षा कर्मियों सहित अन्य

कर्मचारी लगभग 11 माह से वेतन के अभाव में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि कर्मचारियों ने वर्षों तक संस्थान की सेवा की है, लेकिन लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसी गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं कर्मचारी परिवार- बैठक के दौरान सांसद ने इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की कि वेतन नहीं मिलने के कारण अनेक कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। कई परिवारों को कर्ज लेकर जीवनयापन करना पड़ रहा है, जबकि कुछ कर्मचारियों के सामने बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल वेतन भुगतान का विषय नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के भविष्य और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा मामला है। इसलिए इस समस्या का समाधान संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ किया जाना आवश्यक है।

शीघ्र कार्रवाई की मांग- सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने वस्त्र मंत्रालय से आग्रह किया कि लंबित वेतन भुगतान सहित कर्मचारियों से जुड़े अन्य मामलों में शीघ्र निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब उन्हें राहत प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। सांसद ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय कदम उठाने का अनुरोध भी किया। मंत्रालय ने दिया सकारात्मक आश्वासन- बैठक के दौरान वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक स्तर पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेगा तथा संबंधित पहलुओं की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित वेतन भुगतान का मार्ग जल्द प्रशस्त होगा। श्रमिक हितों के लिए लगातार सक्रिय हैं सांसद- उल्लेखनीय है कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटील क्षेत्र के श्रमिकों, कर्मचारियों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को लगातार विभिन्न स्तरों पर उठाते रहे हैं। तापी मिल कर्मचारियों के लंबित वेतन का मामला भी उनके द्वारा लगातार केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष रखा जाता रहा है। क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों ने उम्मीद जताई है कि सांसद के इस प्रयास से जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और लंबे समय से वेतन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

केन्द्रीय जेल उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

आज की जनधारा

उज्जैन। केन्द्रीय जेल अधीक्षक श्री मनोज कुमार साहू द्वारा बताया गया कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय एवं जेल मुख्यालय के निदेर्शों के पालन में गत दिवस 12 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा 20 अधिकारी/कर्मचारी एवं जेल में परिरुद्ध/निरुद्ध 1000 पुरुष, 70 महिला बंदियों को योग करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष कृष्णकांत मिश्रा द्वारा जेल में चल रही सुधारात्मक पहल से प्रेरित होकर जेल के अधिकारियों तथा परिरुद्ध/निरुद्ध बंदियों को जेल में अनुशासन बनाये रखने, सौंपे गये कार्य, स्वच्छता, निरक्षर बंदियों को साक्षर करने, उद्योग कार्य में निपुणता, एवं आई.टी.आई. प्रशिक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने पर ससम्मान विघ्नहर्ता अवार्ड वितरण किया गया।

साथ ही ऐसे बंदी जिनके पुत्र/पुत्रियों द्वारा विभिन्न विद्यालयों से शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किये जाने से पुत्र/पुत्रियों के नाम पर संबंधित बंदियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जसमन सिंह डावर जेल उप अधीक्षक (प्रशा.), श्री सुरेश गोयल (सहा. अधीक्षक), प्रवीण कुमार मालवीय (सहा. अधीक्षक), अंतीम बिरला (सहा. अधीक्षक), एवं बड़ी संख्या में जेल स्टाफ उपस्थित रहा।

क्या जातियों से तय होगी नागरिकता?

संपादकीय

बिहार के भोजपुर जिले की हालिया घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे यहां किसी भी बड़ी घटना का मूल्यांकन तथ्यों और कानून के आधार पर होता है, या फिर उसकी दिशा जातीय पहचान तय करती है? भरत तिवारी को उनके समर्थक सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं और फेसबुक लाइव के जरिए आत्मसमर्पण की बात करते हैं। उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो जाती है। पुलिस एनकाउंटर बताती है। आम जनता इसको हत्या मानती है। घटना की निष्पक्ष जांच अपनी जगह आवश्यक है, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया, राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों ने इसे जातीय चश्मे से देखना शुरू कर दिया। बहस इस बात पर कम हुई कि मुठभेड़ की परिस्थितियां क्या थीं, इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि मृतक किस जाति का था? भारतीय राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल हो, जाति के एंगल से जरूर सोचा जाता है। जातियों में जैसी एकता बढ़ रही है राजनीतिक दल उसे वोट की तरह देखने लग जाते हैं। इस घटना इस बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है कि न्याय, संवेदना और समर्थन भी जाति के आधार पर तय होने लगे हैं।

जब भी भारत में कोई बड़ी घटना होती है, किसी की हत्या, पुलिस एनकाउंटर, बलात्कार, दंगा, आरक्षण का प्रश्न या चुनाव, सबसे पहले जो सवाल उठता है, वह यह नहीं होता कि सच क्या है, बल्कि यह होता है कि वह किस जाति का था? लोग किसी भी निर्णय पर जाति के आधार पर पहुंचते हैं। लोग सोचते हैं यदि मृतक हमारी जाति का है तो वह शहीद है। यदि आरोपी हमारी जाति का है तो उसके बचाव में तर्क खोजे जाने लगते हैं। यदि पीड़ित दूसरी जाति का है तो संवेदनाएं भी जाति के चश्मे से छनकर बाहर आती हैं। आजादी के बाद से भारतीय राजनीति और समाज इसी जाति के आधार से बनता और आगे बढ़ता रहा है। यह केवल राजनीति की विफलता नहीं, बल्कि समाज की गहरी मानसिक बीमारी का संकेत है। भारतीय संविधान ने नागरिक बनाए, लेकिन समाज आज भी जातियों में बंटा हुआ है। हजारों वर्षों पुरानी वर्ण व्यवस्था से इतर जाति व्यवस्था का प्रभाव आज भी हमारे सामाजिक व्यवहार, रिश्तों, विवाह, गांवों की बसाहट और यहां तक कि राजनीतिक सोच पर दिखाई देता है। दुखद यह है कि लोकतंत्र ने इस विभाजन को समाप्त करने के बजाय कई बार उसे और मजबूत किया है।

हर राजनीतिक दल समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की बात करता है। कोई गांधी का नाम लेता है, कोई डॉ. भीमराव अंबेडकर का, कोई भगत सिंह का, कोई दीनदयाल उपाध्याय का, कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो कोई कार्ल मार्क्स और लेनिन का। लेकिन जब चुनाव में उम्मीदवार चुनने की बारी आती है, तब सबसे पहले जिस बात पर नजर जाती है, वह उसकी योग्यता नहीं बल्कि उसकी जाति होती है। सवाल यह है कि यदि राजनीति स्वयं जाति से ऊपर नहीं उठ पा रही, तो समाज से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह जातिवाद छोड़ देगा?

सत्तर के दशक का जेपी आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं था। वह सामाजिक परिवर्तन का भी सपना था। अनेक युवाओं ने अपने नाम से जातिसूचक उपनाम हटा दिए। यह संदेश था कि पहचान व्यक्ति के विचारों और कर्मों से बनेगी, जाति से नहीं। लेकिन समय बीता, मंडल राजनीति आई और सामाजिक न्याय के नाम पर एक नई राजनीतिक धुरी खड़ी हुई। इससे पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला, जो लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इसके साथ ही जाति राजनीतिक शक्ति का सबसे प्रभावी हथियार भी बन गई। बिहार और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। वहां कोई भी बड़ी घटना कुछ ही घंटों में जाति की बहस में बदल जाती है। कानून, न्याय और अपराध की चर्चा पीछे छूट जाती है, जबकि जाति बहस का केंद्र बन जाती है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने राजनीतिक गणित के अनुसार पक्ष और विपक्ष तय करते हैं। ऐसा लगता है मानो न्याय का पैमाना संविधान नहीं, बल्कि जाति समीकरण हो।

यह प्रवृत्ति केवल बिहार या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण जाति एवं सामुदायिक आधार पर बनते-बिगड़ते हैं। कहीं आदिवासी और गैर-आदिवासी की खाई है, कहीं धर्मांतरण को लेकर तनाव है, तो कहीं आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई। पहचान की राजनीति हर राज्य में अलग रूप धारण कर लेती है, लेकिन उसका मूल स्वरूप एक ही है, समाज को अलग-अलग हिस्सों में बांटना।

यह भी सच है कि सदियों तक वंचित रहे समाजों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, उनकी आवाज सत्ता तक पहुंची और लोकतंत्र अधिक समावेशी बना। इसे नकारना इतिहास के साथ अन्याय होगा। लेकिन उतना ही बड़ा सच यह भी है कि यदि हर घटना को केवल जाति के चश्मे से देखा जाएगा तो कानून का शासन कमजोर होगा और समाज में स्थायी अविश्वास पैदा होगा।

कबीर ने सदियों पहले कहा था— 'जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।' दुर्भाग्य यह है कि आज हम ज्ञान नहीं, जाति पूछते हैं। योग्यता नहीं, बिरादरी देखते हैं। विचार नहीं, वोट बैंक तलाशते हैं। यही कारण है कि चुनावी सभाओं से लेकर सोशल मीडिया तक हर बहस का निष्कर्ष अंततः जाति पर आकर रुक जाता है। चुनाव में लोकतंत्र का प्रतिनिधि चुना जाता है लेकिन बाद में देखा जाता है कि वह तो जाति के प्रतिनिधि में बदल गया है। यदि हर हत्या जाति की हत्या बन जाएगी, हर अपराध जाति के सम्मान का प्रश्न बन जाएगा और हर चुनाव जाति जनगणना का गणित बन जाएगा, तो संविधान की आत्मा कमजोर हो जाएगी।

भारत की राजनीति, समाज और प्रशासन को यह स्वीकार करना होगा कि सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति एक ही बात नहीं हैं। सामाजिक न्याय सभी को समान अवसर की बात करता है, जबकि जाति की राजनीति व्यक्ति और समाज को संकीर्ण बनाने की का षड्यंत्र है। एक समाज को जोड़ती है, दूसरी उसे वोट बैंक में बदल देती है। आज सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि किस जाति का वर्चस्व है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आने वाली पीढ़ी भी इसी जाति बोझ के साथ जीने को अभिशप्त रहेगी, जिसे खत्म करने का सपना कबीर ने देखा था, जिसे जेपी ने जगाया था और जिसे संविधान ने समान नागरिकता के रूप में स्थापित किया था। जिस दिन किसी घटना पर हमारा पहला प्रश्न यह होगा कि 'सच क्या है, कानून क्या कहता है और न्याय किसमें है?' यह लोकतंत्र की सफलता होगी। यदि यह पूछा जाता है कि 'वह किस जाति का था?' तो भारतीय समाज का दुर्भाग्य बना रहेगा।

भारत को मिला वैश्विक वित्तीय सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व

महेन्द्र तिवारी

भारत ने वैश्विक वित्तीय सुरक्षा और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ चल रही अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पहली बार किसी भारतीय अधिकारी को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष पद पर चुना गया है। 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विवेक अग्रवाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान में वह भारत सरकार के संस्कृति सचिव हैं। पेरिस में आयोजित संस्था की पूर्ण बैठक में सदस्य देशों ने उन्हें इस पद के लिए चुना। यह केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय शासन व्यवस्था में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रमाण भी है।

यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत 2010 से इस संस्था का सदस्य है, लेकिन पिछले 16 वर्षों में किसी भारतीय को इसके शीर्ष नेतृत्व में स्थान नहीं मिला था। अब पहली बार भारत संस्था के सर्वोच्च नेतृत्व ढांचे का हिस्सा बनेगा और उसकी नीतियों तथा प्राथमिकताओं को आकार देने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाएगा। यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, वित्तीय संस्थागत क्षमता और वैश्विक विश्वसनीयता का संकेत माना जा रहा है।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल विश्व स्तर पर धनशोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से जुड़े वित्तीय नेटवर्कों के खिलाफ मानक निर्धारित करने वाली प्रमुख संस्था है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग अपराधी, आतंकवादी संगठन और अवैध नेटवर्क न कर सकें। यह संस्था सदस्य देशों की नीतियों और कानूनों का मूल्यांकन करती है तथा आवश्यक सुधारों की सिफारिश करती है। इसके निर्णयों का प्रभाव वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था, विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और

आर्थिक विश्वसनीयता पर पड़ता है।

विवेक अग्रवाल की नियुक्ति उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव और वित्तीय अपराधों से निपटने में उनकी विशेषज्ञता का परिणाम मानी जा रही है। वह पहले इस संस्था में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के निदेशक भी रह चुके हैं। वित्तीय खुफिया इकाई का कार्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की निगरानी करना, धनशोधन से जुड़े मामलों की पहचान करना और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना होता है। इस अनुभव ने उन्हें वैश्विक वित्तीय सुरक्षा के जटिल मुद्दों को समझने और समाधान विकसित करने की क्षमता प्रदान की।

भारत के लिए यह उपलब्धि केवल प्रतिष्ठा का विषय नहीं है बल्कि रणनीतिक महत्व भी रखती है। पिछले एक दशक में भारत ने धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ अपने कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया है। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच एजेंसियों ने अनेक मामलों का खुलासा किया है। वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए तकनीकी प्रणालियों को सशक्त बनाया गया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार के साथ सुरक्षा मानकों को भी लगातार बेहतर किया गया है। इन प्रयासों के कारण भारत को वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार और सक्षम साझेदार के रूप में देखा जाने लगा है।

वर्ष 2024 में भारत के मूल्यांकन के दौरान संस्था ने भारत के धनशोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी ढांचे की सराहना की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने प्रभावी परिणाम प्राप्त करने वाला ढांचा विकसित किया है। यही कारण है कि आज भारत को केवल एक सदस्य देश के रूप में नहीं बल्कि नीति निर्माण में योगदान देने वाले नेतृत्वकारी देश के रूप में देखा जा रहा है।

उपाध्यक्ष का पद संस्था की कार्यप्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के साथ मिलकर संस्था के एजेंडा, बैठकों, प्राथमिकताओं और वैश्विक रणनीतियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। सदस्य देशों के बीच सहमति निर्माण, नई चुनौतियों पर नीति निर्धारण और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवेक अग्रवाल इस जिम्मेदारी के साथ उन विषयों पर भी काम करेंगे जो तेजी से बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई वित्तीय तकनीकों से जुड़े हैं।

आज दुनिया के सामने केवल पारंपरिक धनशोधन की चुनौती नहीं है। आभासी परिसंपत्तियां, सीमा पार डिजिटल लेनदेन, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और आतंकवादी नेटवर्कों की बदलती रणनीतियां नई चिंताएं पैदा कर रही हैं। भारत ने एक ओर डिजिटल भुगतान को व्यापक बनाया है तो दूसरी ओर सुरक्षा और निगरानी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। यही अनुभव अब वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण में उपयोगी साबित हो सकता है।

भारत की एक और विशेषता यह है कि उसने वित्तीय समावेशन और वित्तीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। जनधन खातों, आधार आधारित पहचान प्रणाली और डिजिटल भुगतान तंत्र ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा है। साथ ही वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है। यह मॉडल अनेक विकासशील देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। भारत की बढ़ती भूमिका इस अनुभव को वैश्विक मंच पर साझा करने का अवसर प्रदान करेगी।

यह नियुक्ति भारत की विदेश नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज आर्थिक कूटनीति और वित्तीय सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। किसी देश की विश्वसनीयता केवल उसकी सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि उसकी वित्तीय प्रणाली की मजबूती और पारदर्शिता से भी आंकी जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कठोर वैश्विक कार्रवाई की वकालत करता रहा है। ऐसे में इस संस्था के शीर्ष नेतृत्व में भारत की उपस्थिति उसकी आवाज को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी।

अक्सर यह चर्चा होती है कि इस संस्था की निगरानी सूची में शामिल होने का किसी देश पर कितना प्रभाव पड़ता है। जिन देशों को बढ़ी हुई निगरानी के दायरे में रखा जाता है, उन्हें विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय ऋण और वैश्विक वित्तीय लेनदेन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दुनिया के अधिकांश देश संस्था के मानकों को गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि इसके नेतृत्व में स्थान प्राप्त करना किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।

विवेक अग्रवाल की नियुक्ति को भारत सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत की सफलता करार दिया और कहा कि यह वैश्विक आतंकवाद वित्तपोषण नेटवर्कों के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह नियुक्ति इस बात का भी संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत की संस्थागत क्षमता और उसके अनुभव पर भरोसा करता है।

स्वयं विवेक अग्रवाल ने भी इस नियुक्ति को भारत के सामूहिक प्रयासों की मान्यता बताया है। उनके अनुसार यह भारत के धनशोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी ढांचे की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित, समावेशी और लचीला बनाने के लिए सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

व्यंग्य

गर्व से कहो हम पति हैं

सूर्यबाला

महिलाओं को मालूम है कि जिस तरह हर सफल पुरुष के पीछे कोई महिला होती है उसी तरह हर असफल महिला के पीछे भी कोई-न-कोई पुरुष होता है। आप भी माने या न मानें, स्त्री - स्वातंर्त्य या महिला-मुक्ति का आंदोलन भी, जो माकूल स्पीड नहीं पकड़ पा रहा, उसके पीछे भी यही कारण है। इसे यों समझिए कि अपने हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से, बेहिसाब तादात में महिलाएँ, सामाजिक-राजनीतिक विकास की गाड़ी पकड़ने को चुस्त-दुरुस्त तैयार है। इंजन ने सीटी भी मार दी। महिलाएँ हचककर फुटबोर्ड पर लटक भी लीं, लेकिन, चक्का जाम! भई, यह तो वही बात हुई कि इंडियन एअरलाइंस के आसमान से टूटे तो भारतीय रेलवे के खजूर में अटके। गाड़ी थी कि न टस, न मस।

पड़ताल हुई तो पता चला कि पिछले पहियों के नट-बोल्ट इतने खस्ताहाल हैं कि ये अगलों को खिसकने ही नहीं दे रहे।

यहाँ हम इन पाठकों का परिचय इन पिछले पहियों से करा दें। ये पिछले पहिए, पुरुष हैं। पाठकों को यह भी ज्ञात होगा कि स्त्री और पुरुष को हमने समाज और परिवार की गाड़ी के दो पहिए माना है। अब एक पहिए धुआँधार चालू हो और दूसरा पूरी तरह पंचर, तो कैसे चलेगा भई!

बस इसलिए हम जागरूक और प्रबुद्ध महिलाओं ने सोचा, चलो, पहले अपनी भारतीय रेलगाड़ी के इन जाम चक्कों की मरम्मती और दुरुस्ती पर ध्यान दिया जाए। इनके बिगड़ैल पूर्वाग्रह के स्पीड-ब्रेकर सपाट किए जाएँ, तभी अपनी गाड़ी सरपट दौड़ेगी। वरना यह क्या कि हम तो प्रगति और विकास की नसेनी पर सोत्साह फेंटा कसकर चढ़ने को तैयार, लेकिन यह मुआ (सॉरी पुरुष) अभी बेड टी के इंतजार में सोया पड़ा है। इसका क्या ठिकाना, नींद के झोंके में एक पाँव फटकारेगा तो हमारी लगाई सीढ़ी, धड़ाम से चारों खाने नीचे चित्त वही, हर असफल महिला के पीछे एक पुरुष।

इसलिए कई महिला संगठनों ने अनेक शिखर-वार्ताओं के बाद यह निर्णय लिया कि नहीं, हमें काउंटर-पार्ट, बेचारे पुरुष को यूँ ही सोता नहीं छोड़ना है। अर्थात उसे जगा कर ही छोड़ना है, क्योंकि - 'उठ जाग मुसाफिर देर भाई... तुझे नहीं, मुझे तो ऑफिस जाना है...।

सो, हे पति! हे पुरुष! इनमें से एक या दोनों, उठ! और अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हमारी दूरदर्शिता और उदारता का लोहा मान... जो हमने 'अपनी' दशा सुधारने का काम बीचों-बीच छोड़कर, तुझे उठाने और तेरी धूल-धक्कड़ झाड़ने का टास्क हाथ में ले लिया है।

यह काम उतना आसान नहीं। इसके लिए हमें पूरी तरह समर्पित और एकजुट होकर काम करना होगा। क्योंकि महिलाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि आज का पुरुष अनेक प्रकार की हीनता-बोधों से ग्रस्त है। अनेक अहं, अनेक वहम, अकर्मण्यता तथा आलस्य इसके मूल कारण हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी वर्तमान, गिरी हुई दशा पर तरस खाएँ तथा उन्हें उनकी संकीर्ण विचारों की चारदीवारी से बाहर लाने की हर चंद कोशिश करें।

इसके लिए सबसे पहले तो रैलियाँ निकाली जाएँ और उनकी तख्तियों पर उत्साहवर्धक वाक्य लिखवाएँ जाएँ। जैसे - 'पति एक सम्मानजनक ओहदा है' ...या फिर 'पतित्व हीनता नहीं, गौरव का प्रतीक है...' अथवा 'गर्व से कहो, हम पति हैं...' आदि इत्यादि। सर्वे से प्राप्त सूचना के अनुसार, 'पत्नी' और 'परिवार' के नाम से नर्वस होनेवाले पतियों की संख्या में भी इधर बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। कुछ पति तो इसी भय के कारण ड्यूटी आवर्स के बाद भी ताश-पपलू आदि के बहाने मारकर, ऑफिस में ही पड़े रहते हैं। ऐसे पतियों को समझना चाहिए कि यह पलायनवाद अर्थात भगोड़ापन है। यही कारण है कि उनका पुरुष समाज अर्थात पूरा का पूरा पुरुष समाज, पलायन करते-करते आज इस दीन-हीन दशा को पहुँच गया है। हमारे देश की दुर्गति का प्रमुख कारण भी यही है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब पुरुष वर्ग पलायन करता रहा, तब-तब देश रसातल को जाता रहा, यानी हमेशा ही...।

फिलहाल देश और रसातलवाले मुद्दे को छोड़कर हम अपने मेनिफेस्टों पर आते हैं जिसके अनुसार इन सामूहिक तथा एकजुट अभियानों के अतिरिक्त, पारिवारिक स्तर पर भी, हर पत्नी का फर्ज बनता है कि वह कम से कम एक अदद पुरुष अर्थात पति को स्वावलंबी बनाने में प्राण पर से जुट जाए! मिसाल के तौर पर अदि वह किसी जरूरी काम में फँसी है तो निठल्ले पति द्वारा डपटकर पानी माँगे जाने पर हरगिज न उठे। उसे स्वयं उठकर पानी लेने की आदत डलवाएँ। साथ ही उसे स्वयं पानी शर्ट में बटन टाँगने तथा पाजामे में नाड़ा डालने के लिए प्रेरित करें।

पत्नी को स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे मौकों पर पति पहले झल्लाएगा, डपटेगा तथा पत्नी को पागलखाने में भर्ती करने की धमकी भी देगा। किंतु पत्नी को अपनी फर्ज अदायगी से डिगना नहीं चाहिए। उसे फौरन समझ लेना है कि यह पुरुष नहीं, उसकी हीन भावना बोल रही है।

कविता संसार

बदली हुई तहज़ीब

चन्द्रकांत खुंटे 'क्रांति'

सोचता हूँ...
कितने सीधे और मासूम थे वो लोग
जो अपनी मोहब्बत, अपनी यादें
किताबों के पन्नों के बीच
एक गुलाब की शक्ल में महफ़ूज़ रखते थे।
वो कागज़ की खुशबू और पंखुड़ियों का सूखना
एक पूरा दौर था सादगी का।
और आज का यह आधुनिक दौर देखिए...
जहाँ लोग किताबें तो नहीं खोलते
पर जब भी मुँह खोलते हैं
तो लफ़्ज़ों की जगह ज़हर उगलते हैं।
तरक्की के इस नए ज़माने में
दिलों की जगह नफ़रत ने ले ली है।
अब किसी के पास वक़्त नहीं
कि वो किसी को याद करे
पर हर किसी के पास पूरा वक़्त है
कि वो अपनी तीखी जुबान से
दूसरों के वजूद को छलनी कर दे।
अजीब विडंबना है—
वो गुलाब रखने वाले कल के लोग पिछड़े कहलाए,
और जुबान पर ज़हर रखने वाले
आज के लोग 'बेहद स्मार्ट' और कामयाब बन बैठे।।

यूपी में तन-मन भिगोने जल्द आ रहा है मानसून

-संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में गर्मी से परेशान लोगों के लिये जल्द अच्छी खबर आने वाली है। यूपी में मानसून 27 से 30 जून तक पूर्वी-पश्चिमी क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है, जो 5 जुलाई तक पूरे राज्य में पूरी तरह छा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, जून के तीसरे सप्ताह से मानसूनी गतिविधियां तेजी से बढ़ेगी और महीने के अंत तक अधिकांश जिलों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पिछले वर्षों के ट्रेंड और आईएमडी की भविष्यवाणी के आधार पर, इस बार भी मानसून 27 से 30 जून के बीच राज्य में पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ विचलन के कारण पूर्वी यूपी में पहले और पश्चिमी यूपी में थोड़े बाद में आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रवेश आमतौर पर दो चरणों में होता है। पूर्वी हिस्सों में मानसून 15 से 20 जून के बीच दस्तक देता है, जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में 25 से 27 जून के बीच फैल जाता है। मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून 27-30 जून तक आने की संभावना है। इस तरह पूर्वी यूपी में मानसून पहले प्रवेश करेगा और धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में छाएगा। 5 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह छा जाएगा। वर्तमान में (22 जून 2026) देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री-मानसून एक्टिविटी है और 23 जून के आसपास मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, जो जून से सितंबर तक केन्द्रित होती है। राज्य की कुल वर्षा में पहाड़ी क्षेत्रों में वार्षिक औसत 170 सेमी तक हो सकता है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में 84 सेमी तक रहता है। इस बार भी उम्मीद है कि मानसून जमकर बरसेगा, लेकिन मौसम के तेवरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बारिश सावधानी भी मांगती है, क्योंकि भीषण गर्मी से राहत मिलने जा रही है, लेकिन तेज बारिश से थोड़ा-बहुत भी हो सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता 25 फीसदी से कम, जबकि शेष उत्तर प्रदेश में 25 से 50 फीसदी के बीच रहती है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में वर्षा कहीं कम तो कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। राज्य के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राप्त होती है। यह एक महत्वपूर्ण पैटर्न है, क्योंकि बुंदेलखंड पिछले वर्षों से वर्षा की कमी से परेशान है और इस क्षेत्र में कृषि पर सीधा प्रभाव होता है। पूर्वी यूपी में वर्षा अधिक होने के कारण खेती बेहतर होगी, लेकिन पश्चिमी यूपी में भी पर्याप्त वर्षा की उम्मीद है। मध्य यूपी में वर्षा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच के स्तर पर रहने की संभावना है।

सुरक्षा की जीत, गरिमा की हार? नीट-यूजी पुनर्परीक्षा का दोहरा चेहरा

-प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

21 जून 2026 को नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा समाप्त हुई। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते लाखों विद्यार्थियों के चेहरों पर राहत थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा बोझ भी झलक रहा था। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल इस परीक्षा को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में आयोजित किया गया। 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों, 95 हजार परीक्षा कक्षों, 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरों, 51 हजार जैमरों, हजारों बायोमेट्रिक कर्मचारियों और कड़ी फ्रिस्किंग के बीच परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पेपर लीक की आशंकाएं लगभग समाप्त रहीं और परिणामों पर विश्वास बहाल होने की उम्मीद जगी। इसके लिए एनटीए और केंद्र सरकार बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस सफलता के बीच एक सवाल खड़ा है—क्या निष्पक्षता की यह कीमत हमारी युवा पीढ़ी की गरिमा और मानसिक शांति से वसूली जानी चाहिए?

पिछले वर्षों में बार-बार हुए पेपर लीक कांडों ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंचाई थी। मई 2026 की घटना के बाद सरकार और एनटीए ने पूरे तंत्र को लगभग रीसेट कर दिया। प्रश्न-पत्र तैयार करने से लेकर उनके परिवहन तक अभूतपूर्व गोपनीयता बरती गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ स्थानों पर भारतीय वायुसेना की सहायता से प्रश्न-पत्र पहुंचाए गए, जीपीएस ट्रैकिंग, पुलिस एस्कॉर्ट और एआई आधारित निगरानी तंत्र सक्रिय किए गए। राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग हुई। हजारों पर्यवेक्षक, साइबर निगरानी दल और खुफिया एजेंसियों का त्रिस्तरीय सुरक्षा नेटवर्क परीक्षा की हर गतिविधि पर नजर रखे रहा। यह व्यवस्था किसी शैक्षणिक आयोजन से अधिक एक राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान जैसी प्रतीत होती थी।

इन उपायों का सकारात्मक परिणाम भी सामने आया। लाखों विद्यार्थियों को भरोसा मिला कि इस बार उनकी मेहनत संगठित नकल या पेपर लीक के कारण व्यर्थ नहीं जाएगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े माता-पिता को भी संतोष था कि उनके बच्चों का भविष्य किसी अपराधी गिरोह या भ्रष्ट नेटवर्क के हाथों बंधक नहीं बनेगा। लंबे समय से अपेक्षित विश्वास बहाली की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। निष्पक्षता किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आत्मा है और उसे बचाने के लिए कठोर कदमों का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है। किंतु हर सफलता कुछ ऐसे प्रश्न भी छोड़ जाती है जिन्हें केवल आंकड़ों और प्रशंसाओं से ढंका नहीं जा सकता।

सबसे बड़ा प्रश्न उस अनुभव का है जिससे विद्यार्थी गुजरे। आधार आधारित फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट सत्यापन, जेबों, कानों, जूतों और यहां तक कि कपड़ों की चेन, जिप तथा धागों तक की जांच—यह सब उस युवा पीढ़ी के साथ हुआ जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची थी। 38,795 फ्रिस्किंग कर्मी और 48,448 बायोमेट्रिक कर्मचारी व्यवस्था की आवश्यकता रहे होंगे, लेकिन विद्यार्थियों के मन में यह अनुभव भी दर्ज हुआ कि उन पर पहले संदेह किया गया, बाद में विश्वास। कई अभ्यर्थियों ने स्वयं को अपराधियों की तरह टटोला जाता महसूस किया। यह भावना किसी परीक्षा की सफलता का हिस्सा नहीं होनी चाहिए।

इस पूरी प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषकर छात्राओं के लिए फ्रिस्किंग कई बार असहजता और तनाव का कारण बनी। यद्यपि महिला कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, फिर भी मानसिक दबाव पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। माता-पिता दूर खड़े अपने बच्चों को डिजिटल और भौतिक निगरानी के घेरे में प्रवेश करते देखते रहे। शिक्षा का मंदिर कई स्थानों पर सुरक्षा चौकी जैसा दिखाई देने लगा। यह दृश्य केवल परीक्षा व्यवस्था का नहीं, बल्कि उस सामाजिक अविश्वास का भी प्रतीक है जो धीरे-धीरे संस्थाओं और नागरिकों के बीच बढ़ता जा रहा है। जब एक छात्र परीक्षा देने से पहले स्वयं को संदिग्ध साबित होने से बचाने की प्रक्रिया से गुजरता है, तब कहीं न कहीं शिक्षा का मूल उद्देश्य भी आहत होता है। दरअसल समस्या का मूल कारण विद्यार्थी नहीं हैं। समस्या उस व्यवस्था में है जिसने वर्षों तक पेपर लीक, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरियों को पनपने दिया। यदि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत होती, तो शायद इतनी कठोर सुरक्षा की आवश्यकता न पड़ती। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें, कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली की ओर संक्रमण, उन्नत डिजिटल सुरक्षा उपाय तथा एनटीए में संरचनात्मक सुधार लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। इस बार की सफलता सिद्ध करती है कि इच्छाशक्ति हो तो व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन यदि सुधार केवल सुरक्षा तक सीमित रहेगा और मूल समस्याएं जस की तस रहेंगी, तो हर वर्ष विद्यार्थियों को इसी प्रकार की कठिन और तनावपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देश को अब तय करना होगा कि भविष्य की परीक्षा प्रणाली कैसी हो। क्या हम हर वर्ष युद्ध जैसी तैयारियां करेंगे, या ऐसे तकनीकी और संस्थागत सुधार विकसित करेंगे जिनसे सुरक्षा और सम्मान दोनों साथ चल सकें? फ्रिस्किंग को अधिक संवेदनशील और कम अपमानजनक बनाया जा सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया को चरणबद्ध, डिजिटल और लीक-प्रूफ बनाया जा सकता है। सुरक्षा का उद्देश्य भय नहीं, विश्वास पैदा करना होना चाहिए। यदि कोई व्यवस्था निष्पक्ष तो हो जाए, पर उसमें मानवीय गरिमा खो जाए, तो वह अधूरी सफलता ही कहलाएगी।

नीट-2026 की पुनर्परीक्षा भारत की परीक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस बार परीक्षा सफल रही, विवादों से अपेक्षाकृत मुक्त रही और लाखों छात्रों के परिश्रम को न्याय मिलने की संभावना मजबूत हुई। यह उपलब्धि छोटी नहीं है। फिर भी यह घटना चेतावनी देती है कि केवल सुरक्षा बढ़ाना समाधान नहीं है। मां-बाप के सपनों से जुड़ी यह व्यवस्था कब तक चलेगी? क्या हम अपने युवाओं को पंख देकर उड़ाना चाहते हैं या उन्हें बायोमेट्रिक सलाखों के बीच भविष्य तलाशने के लिए छोड़ देना चाहते हैं?

अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं : मुख्यमंत्री

- वृद्ध की शिकायत पर सीएम योगी ने मथुरा के डीएम को निर्देश
- समस्याओं की जांच करा यथोचित कार्रवाई का दिया निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हर फरियादी से एक-एक कर मुलाकात की। उनका प्रार्थना पत्र लिया और समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों के उचित व समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं अतिक्रमण की शिकायत पर मुख्यमंत्री सख्त हुए और तत्काल इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया।

'जनता दर्शन' में मथुरा से एक वृद्ध भी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि चकरोड पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रूख अपनाते हुए जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वे स्वयं मौके पर जाएं और यथास्थिति देखें। अतिक्रमण होने की स्थिति में इसे तत्काल हटाएं और दोषियों पर कार्रवाई करें। सीएम ने फिर कहा कि अतिक्रमण की शिकायत कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सभी अधिकारी, प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, विकास प्राधिकरण समेत जिम्मेदार संस्थाएं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग भी करती रहें।

'जनता दर्शन' में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, बिजली के तार, पुलिस, राजस्व से जुड़े प्रार्थना पत्र भी आए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रार्थना पत्र लेकर पीड़ितों की बातें सुनीं, फिर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार जनता से जुड़ी हर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। आप सभी की समस्याओं का भी समाधान होगा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर परिस्थिति में 25 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है।

सीएम ने भीषण गर्मी में आए फरियादियों का सबसे पहले हालचाल जाना, फिर उनकी समस्याएं पूछीं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से आए लोगों से कहा कि अभी गर्मी व धूप अधिक है। बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों से कहा कि बहुत जरूरत होने पर ही दोपहर में घर से निकलिए। सीएम ने संयमित खानपान के लिए भी कहा।

मायावती का नया दावा

इस बार के चुनाव परिणाम में बसपा की सरकार बनेगी

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने कहा ने कहा कि बसपा ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आमचुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र जबसे अपरकास्ट समाज और उसमें से ख़ासकर ब्राह्मण समाज उनके साथ जुड़ने लगा है और इसी को ध्यान में रखकर उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ गई है। सन् 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की संभावना प्रतीत होता है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वैसे भी यह सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपरकास्ट में से ख़ासकर 'ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है', जिस अपनी इस 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के सिद्धान्त, नीयत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर-सम्मान के साथ-साथ उन्हें हर स्तर पर पूरी-पूरी भागीदारी देकर यह साबित भी कर दिया है, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आपको काफी उपेक्षित, असुरक्षित व ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं।

इतना ही नहीं बल्कि 'ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक भाईचारा के आधार पर बी.एस.पी. से जुड़ने की इनकी तैयारियों को ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा इन्हें बी.एस.पी. की आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा यह यक़ीन भी है कि बी.एस.पी. की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर-सम्मान ज़रूर दिया जायेगा, जो कि इनकी वास्तविक चिन्ता व दूसरी पार्टियों से मुँह मोड़ने का कारण है। साथ ही, अपरकास्ट में से क्षत्रिय, वैश्य आदि व अन्य समाज के लोगों को भी उनकी बी.एस.पी. से जुड़ने की तैयारी अर्थात् 'जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी' के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार भी ज़रूर बनाया जायेगा, जिसकी तैयारी हर स्तर पर लगातार जारी है।

बी.एस.पी., दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को 'लॉलीपाप' थमाने की संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिन्ता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य समझती है और इसीलिये बी.एस.पी. की नीति व कार्यक्रम जनहित व जनकल्याण तथा अपराध नियंत्रण व क़ानून व्यवस्था के मामले में भी देश व जनहित में बेहतरीन होते हैं।

सार समाचार

अमरनाथ मिश्र ने जगेश्वर धाम में की योग साधना

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आज लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने

सुप्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ स्थल जगेश्वर धाम पहुंचकर भगवान महादेव के चरणों में रविवार 21 जून को योग साधना की। इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से बाबा भोलेनाथ का पूजन-अर्चन किया और फिर परिसर में योगाभ्यास किया। अमरनाथ मिश्र ने योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करते हुए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि योग हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति का अनमोल उपहार है, जो शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और व्यापारिक तनाव के बीच मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महादेव स्वयं योग के आदिगुरु हैं, इसलिए उनके पावन धाम में योग साधना करना अत्यंत सौभाग्य और असीम शांति की अनुभूति कराता है।

अखिलेश यादव के खिलाफ लगे पोस्टरों पर सपा कार्यकर्ताओं का विरोध

लखनऊ। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लाला लाजपत राय वार्ड एवं जयशंकर प्रसाद वार्ड सहित कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के युवा नेता व पूर्व पार्षद प्रत्याशी शैलेंद्र वर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विभिन्न स्थानों पर लगे पोस्टरों को हटाते हुए फाड़ दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह सब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की छवि को खराब करने की किसी भी साजिश को समाजवादी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई।

एआई तकनीक से नकली दुल्हन बनाकर करोड़ों की ठगी

कानपुर। मैरिज ब्यूरो और कॉल सेंटर की आड़ में खेल खेला जा रहा है। टेलीकॉलर को दुल्हन की मां बनाकर इस्तेमाल किया, फिर फर्जी पहचान से पीड़ितों को जाल में फंसाकर ठगी की। पुलिस जांच में ठगी के नए खुलासे हुए है। गिरोह पर 5 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। शादी तय कराने के नाम पर वसूली भी की गई। इसके लिए नकली रिश्तों का जाल बिछाकर करोड़ों ठग लिए गए। एआई, फर्जी दस्तावेजों से रची गई साजिश में कई राज्यों के लोगों को शिकार बनाया गया है। पुलिस गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी गई है।

आंदोलन हिंसक नहीं है तो कार्रवाई क्यों होती है : माता प्रसाद पांडेय

लखनऊ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सवाल उठाया कि यदि आंदोलन हिंसक नहीं है तो कार्रवाई क्यों होती है। इस पर स्पीकर सतीश महाना ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से प्रतिक्रिया मांगी। जवाब में खन्ना ने कहा कि वे 37 वर्षों से सदन में हैं और लंबे समय तक विपक्ष में रहे। उस दौरान उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए, यहां तक कि एक ऐसे व्यक्ति की हत्या का मामला भी लगाया गया, जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। यह मुकदमा 12 साल चला और अंततः वे बरी हो गए। उन्होंने कहा कि उस समय विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर जेल भेजना आम बात थी।

राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी दुखद : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी पर कहा, 'जो खबरें आ रही हैं वह दुखद हैं। भगवान राम के प्रति लोगों की श्रद्धा और लगाव की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। लोग यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे को लेकर भी ऐसी खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर गठित की है लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, यह भी बड़ा सवाल है। भाजपा ने यह साबित कर दिया कि धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी।'

यूपी पुलिस की तकनीकी पहल को राष्ट्रीय सम्मान

- अपराध विश्लेषण पोर्टल को मिला एसकेओसीएच पुरस्कार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवाओं ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाने के लिए विकसित किए गए अपराध विश्लेषण पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एसकेओसीएच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है।

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने इस सम्मान का प्रमाण पत्र भेंट किया। इस उपलब्धि को उत्तर प्रदेश पुलिस की आधुनिक और तकनीक आधारित कार्यप्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवाओं ने इस पोर्टल को स्वयं विकसित किया है। इसका उद्देश्य अपराधों की जानकारी का बेहतर विश्लेषण कर पुलिस को समय रहते प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयार करना है। पोर्टल के माध्यम से अपराध से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उसी के आधार पर पुलिस बल की तैनाती की रणनीति तैयार की जाती है। इस पोर्टल में अपराध से जुड़े पुराने रिकॉर्ड, निगरानी कैमरों की जानकारी और भौगोलिक सूचनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके जरिए अपराध वाले स्थानों की पहचान, घटनाओं के संभावित केंद्रों का पता लगाने और अपराधियों के भागने वाले रास्तों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है।

सड़क, नहर, रेलवे मार्ग, जंगल और अन्य संभावित रास्तों की जानकारी के आधार पर पुलिस अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली केवल घटना के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहकर पहले से तैयारी करने वाली व्यवस्था की ओर बढ़ रही है।

पुलिस विभाग के अनुसार, आंकड़ों के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त, निगरानी, पुलिस चौकियों, आपात सेवा वाहनों और निगरानी कैमरों की तैनाती को बेहतर तरीके से किया जा रहा है। करीब 11 लाख निगरानी कैमरों से मिलने वाली सूचनाओं और अपराध विश्लेषण के परिणामस्वरूप वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में कई प्रमुख अपराधों में कमी दर्ज की गई है।

इन क्षेत्रों में लूट की घटनाओं में लगभग 55 प्रतिशत, चोरी के मामलों में लगभग 23 प्रतिशत, महिलाओं से जुड़े अपराधों में लगभग 10 प्रतिशत और गौ-तस्करी के मामलों में लगभग 27 प्रतिशत तक कमी आने का दावा किया गया है। इस पोर्टल को विकसित करने और अपराध रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तरू माथुर, कृष्ण मुरारी और अर्पित गुप्ता को विशेष रूप से सराहा गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी क्षमता, नवाचार और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। अपराध नियंत्रण में आंकड़ों और तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव पर हमला लोकतंत्र पर हमला : यादव महासभा

लखनऊ। सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव पर हुए कथित प्राणघातक हमले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, गाजीपुर के प्रतिनिधिमंडल ने कार्यकारी जिलाध्यक्ष रामज्ञान यादव के नेतृत्व में सैदपुर स्थित ब्लॉक प्रमुख के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की, घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया तथा प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर इस प्रकार का हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के विश्वास पर सीधा प्रहार है। यदि जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है।

यादव महासभा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व डीआईजी बलिकरन सिंह यादव ने कहा कि सैदपुर ब्लॉक प्रमुख पर हुए हमले ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक वातावरण पर चिंताजनक सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राजनीति का स्वरूप इतना विषाक्त होता जा रहा है कि जनसेवा के लिए चुने गए प्रतिनिधि भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है।

उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले यदि इसी प्रकार बढ़ते रहे और उन पर समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में अराजकता का माहौल पैदा होगा। कानून का भय समाप्त होने पर सामाजिक संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों को गंभीर क्षति पहुंचेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए तथा उन्हें ऐसी सजा मिले जो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं के लिए नजीर बने।

लद्दाख के किसानों की समस्याओं पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को देंगे ज्ञापन

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने प्रेस ब्रीफिंग में लद्दाख की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत किसान यूनियन ने लद्दाख क्षेत्र के किसानों, बागवानों, भेड़-बकरी पालकों, युवाओं, महिलाओं तथा आम नागरिकों की गंभीर समस्याओं को लेकर भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि लद्दाख देश का सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन यहां के नागरिक आज भी अनेक मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। कठोर जलवायु, सीमित संसाधन, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी, कृषि योग्य भूमि का अभाव तथा पर्यावरणीय चुनौतियां यहां के लोगों के जीवन को कठिन बनाती हैं। मोहम्मद अरशद खान ने लद्दाख की समस्याओं से अवगत कराते हुए मुख्य समस्याओ को पेश किया।

भारत किसान यूनियन का मानना है कि लद्दाख केवल देश की सीमा का प्रहरी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामरिक धरोहर भी है। यदि यहां के किसानों, बागवानों, पशुपालकों और आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए तो लद्दाख देश के सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर क्षेत्रों में शामिल हो सकता है।

भारत किसान यूनियन राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से अनुरोध करती है कि लद्दाख के विकास, पर्यावरण संरक्षण, किसान कल्याण तथा स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। और उपर्युक्त विषयों को लेकर भारत किसान यूनियन आंदोलन भी चलाएगी।

सुल्तानपुर में चोरी की कोशिश नाकाम

सुल्तानपुर। जनपद के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिनोवा पुरी बायपास रोड स्थित नखराही गांव में बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे अज्ञात चोरों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, चोर देर रात राकेश उपाध्याय के घर में चोरी की नीयत से घुसे थे। घर के सेकंड फ्लोर पर संदिग्ध गतिविधियां देख परिजन और ग्रामीण सतर्क हो गए। शोर मचने पर ग्रामीणों ने चोरों का पीछा किया, जिसमें दो चोरों को मौके पर पकड़ लिया गया, जबकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूचना मिलने पर थाना देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (Pyy B W 1545) भी बरामद हुई है, जिसके संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बाइक आरोपियों की है या किसी अन्य व्यक्ति की। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है तथा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों और चोरी की घटनाओं से जुड़े संभावित नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।

अवधा आई एंड फेस क्लिनिक का उद्घाटन

- पलक सर्जरी, आंखों के कैंसर, भेंगापन से मिलेगी लोगों को राहत

लखनऊ। बचपन से अब तक की नानी की स्मृतियों को संजोते हुए उनके जन्मदिवस के अवसर को नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ0 पल्लवी सिंह ने अपनी अवधा आई एंड फेस क्लिनिक के उद्घाटन के लिए चुना। उनकी इस भावनात्मक सोच का समर्थन करते हुए उनकी लगभग 90 वर्षीय नानी श्रीमती इंदिरा सिंह ने फीता काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया।

डॉ0 पल्लवी सिंह एम्स, नई दिल्ली तथा कैलिफोर्निया (अमेरिका) से प्रशिक्षित नेत्र सर्जन हैं, जो ऑक्युलोप्लास्टिक सर्जरी (पलक, आंखों के कैंसर एवं आंखों के आसपास की पुनर्निर्माणात्मक एवं प्लास्टिक सर्जरी), भेंगापन (स्क्विंट) के उपचार तथा बच्चों की आंखों की बीमारियों के इलाज की विशेषज्ञ हैं। उन्हें इस क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है।

डॉ0 पल्लवी सिंह ऑक्युलोप्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्हें देश-विदेश के अनेक वैज्ञानिक सम्मेलनों एवं विशेषज्ञ बैठकों में आमंत्रित वक्ता के रूप में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता रहा है। अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय योगदान के लिए उन्हें इस क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एम्स, नई दिल्ली में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें सर्वश्रेष्ठ सीनियर रेजिडेंट के सम्मान से भी नवाज़ा गया था।

विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पलकों की जटिल सर्जरी, आंखों के कैंसर के उपचार तथा उन्नत ऑक्युलोप्लास्टिक सेवाओं जैसी अत्यधिक विशिष्ट सुविधाएं उत्तर प्रदेश में पहली बार इस स्तर के सुपर-स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञ द्वारा एक ही केंद्र पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे प्रदेश के मरीजों को महानगरों अथवा अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता कम होगी।

नई टीम को लेकर दिल्ली में मंथन तेज, संघ पर सबकी नजर

यूपी भाजपा में संगठन बदलाव की आहट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन के पुनर्गठन को लेकर कवायद अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। प्रदेश संगठन की नई टीम को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े संगठनात्मक बैठकों में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि नई टीम के गठन को लेकर नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ पदों और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर अंतिम समय में बदलाव की गुंजाइश अभी बनी हुई है।

भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश संगठन का महत्व हमेशा से सबसे अधिक रहा है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में शामिल भाजपा के लिए यूपी न केवल चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, बल्कि संगठन की मजबूती का भी बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसे में प्रदेश टीम में होने वाली नियुक्तियों को लेकर पार्टी बेहद सतर्कता बरत रही है।

सूत्रों के मुताबिक, नई संगठनात्मक टीम के गठन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ-साथ संगठन में सक्रिय नेताओं के अनुभव को भी ध्यान में रखा जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि ऐसी टीम तैयार की जाए जो आने वाले राजनीतिक अभियानों और चुनावी तैयारियों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सके।

इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रूस) के सुझावों को भी अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण नामों और जिम्मेदारियों को लेकर संघ की राय को विशेष महत्व दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रदेश भाजपा की नई टीम के स्वरूप में संघ की सोच और संगठनात्मक अनुभव की छाप दिखाई दे सकती है।

सूत्रों के अनुसार, एक प्रदेश महामंत्री और संघ के एक क्षेत्र प्रचारक की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में प्रभावशाली रही है। संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को लेकर उनकी राय को महत्वपूर्ण माना गया है।

भाजपा संगठन में पदों का बंटवारा केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं होता, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति से भी जुड़ा होता है। यही वजह है कि पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों के चयन में ऐसे चेहरों को प्राथमिकता देना चाहती है जिनकी संगठन में सक्रिय भूमिका रही हो और जो कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बना सकें। हालांकि अभी अंतिम सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में चल रही बैठकों के बाद जल्द ही प्रदेश संगठन की तस्वीर साफ होने की संभावना है। नई टीम में किन चेहरों को जगह मिलती है, किन क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है और संगठन में किस तरह का संतुलन बनाया जाता है, इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ राजनीतिक विश्लेषकों की भी नजर टिकी हुई है।

उत्तर प्रदेश भाजपा में यह बदलाव ऐसे समय हो रहा है जब पार्टी संगठन को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए और मजबूत करने की तैयारी में है। ऐसे में नई टीम केवल पदों का बदलाव नहीं होगी, बल्कि आने वाले समय की भाजपा की रणनीति का आधार भी मानी जा रही है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा की मौजूदगी में सांची स्तूप पहाड़ पर आयोजित हुआ योगा अभ्यास कार्यक्रम

प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूलों के बच्चों और आम नागरिको ने किया सामूहिक योगाभ्यास

आज की जनधारा

रायसेन। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन स्थल सांची स्थित स्तूप पहाड़ी पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को सुबह 6:00 बजे सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष जसवंत सिंह मीणा, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता सीईओ कमल सोलंकी, एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य विभागों के अधिकारियों सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चों एवं आम नागरिकों ने सामूहिक रूप से योग अभ्यास कार्यक्रम में विभिन्न आसन के साथ योगा किया। इस अवसर पर योग कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने योगार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बहुत ही

अच्छा दिन है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर हम सभी पर्यटन स्थल सांची की स्तूप पहाड़ी पर योग कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरूआत कर पूरे देश भर में योग के प्रति जो संदेश दिया है उसका हम सभी अनुसरण कर रहे हैं। श्री पटेल ने कहा कि योगाभ्यास करने से मानसिक एवं शारीरिक विकास तो होता ही है इसके साथ ही हमारे शरीर के अंदर की कई बीमारियां भी योग करने से ठीक हो जाती है और हम योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ महसूस भी करते हैं, उन्होंने कहा कि योग सिर्फ एक दिन ही नहीं हमेशा करते रहना चाहिए इससे हम लोग हमेशा के लिए फिट एवं स्वस्थ बने रह सकते हैं,अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सभी आम नागरिकों एवं स्कूली बच्चों के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे इस मानव जीवन में योग का बहुत ही महत्व है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरूआत कर पूरे विश्व को संदेश दिया है । श्री शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा हम अन्य दिनों में भी योगा करें तो पूर्णता हमारा शरीर हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकता है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री पटेल का जन्म दिवस मनाया गया:- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का जन्मदिन भी मनाया गया । इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा एवं अन्य जन प्रतिनिधि तथा आम नागरिकों से लेकर स्कूली बच्चों ने श्री पटेल को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शर्मा ने स्वास्थ्य राज मंत्री श्री पटेल का चुनरी एवं गुलदस्ता के साथ मंच पर सम्मान किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत यशवंत सिंह मीणा,सांची नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू रेवाराम, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत कमल सोलंकी, एसडीएम मनीष शर्मा, तहसीलदार श्री मांडरे, सहित आम नागरिकगण एवं बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चे,मीडिया कर्मी मौजूद रहे।

जिला पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में योग कार्यक्रम आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ आयोजन

आज की जनधारा

विजय अरोड़ा। गंजबासौदा। जिला पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में संपन्न हुआ। जिसमें बड़ी संख्या में योग साधक, गणमान्य नागरिक, सामाजिक संस्थाएं एवं महा विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने पूर्ण उत्साह के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं अतिथि गण द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ एवं तत्पश्चात पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी जगदीश यादव, जिला महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी सुनीता भावसार के मार्गदर्शन में योग अभ्यास प्रारंभ हुआ। योग अभ्यास निर्धारित समय से प्रारंभ हुआ एवं सभी योग क्रियाओं के उपरांत शांति मंत्र एवं भारत माता के जयघोष के साथ निर्धारित समय पर समापन किया गया। अतिथि के रूप में पधारें खादी ग्रामोद्योग विकास निगम उपाध्यक्ष डॉ राकेश सिंह जादौन, पूर्व नपाध्यक्ष मोहन भावसार, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, पूर्व जनपद अध्यक्ष अंजलि यादव, समाज सेवी विमलचंद ओसवाल, अशोक अग्रवाल मंकूजी, राजेंद्र व्यास, घनश्याम अग्रवाल, शांतिप्रकाश ओसवाल, देवेंद्र वर्मा, सुरेंद्र दांगी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजनों ने साथ में पूर्ण उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का संचालन महाविधालय योग शिक्षिका पूनम तिवारी एवं योग शिक्षक देवसिंह लोधी ने किया। एवं आभार वरिष्ठ शिक्षिका एवं एनसीसी प्रभारी निधि शर्मा ने किया। सामूहिक योग अभ्यास के उपरांत प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर चयनित महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक योग प्रस्तुति भी की गई। योग अभ्यास के समापन के पूर्व उपस्थित सभी जनों ने मंच के आह्वान पर निरंतर योग करने का संकल्प भी लिया एवं कार्यक्रम उपरांत मानस साधना मानक आधारित स्वल्पाहार ग्रहण किया।

मंडी शुल्क वृद्धि के विरोध में 23 जून को जिले की सभी कृषि मंडियां रहेंगी बंद

आज की जनधारा

नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंडी शुल्क में की गई वृद्धि के विरोध में सकल मध्य प्रदेश अनाज, दलहन, तिलहन व्यापारी महासंघ के आह्वान पर 23 जून को प्रदेशभर की कृषि उपज मंडियों में एक दिवसीय व्यापार बंद रखा जाएगा। इसी क्रम में नरसिंहपुर जिले की समस्त कृषि मंडियां भी बंद रहेंगी और व्यापारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिला अनाज, दलहन, तिलहन एवं दाल उत्पादक व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष सतीश नेमा तथा महामंत्री ताराचंद शाह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मंडी शुल्क को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किए जाने से व्यापारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने बताया कि 11 जून 2026 को महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में लागू मंडी शुल्क की

जानकारी प्रस्तुत करने का आग्रह किया था तथा दो-तीन दिनों में पुनः चर्चा कर निर्णय लेने का आश्वसन दिया था व्यापारियों का कहना है कि चर्चा और सहमति की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कृषि विभाग एवं मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने जल्दबाजी में गजट प्रकाशित कर 16 जून से नई शुल्क दरें लागू कर दीं। इसके बाद प्रदेशभर के व्यापारियों में असंतोष बढ़ गया है और विभिन्न जिलों में इसका विरोध शुरू हो गया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मंडी शुल्क में वृद्धि से व्यापार की लागत बढ़ेगी, जिसका प्रभाव किसानों और उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। इसी के विरोध में 23 जून को प्रदेश की सभी मंडियों में व्यापार बंद रखकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी व्यापारी संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार के साथ होने वाली चर्चा में समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो आगामी दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा तथा आगे की रणनीति महासंघ द्वारा तय की जाएगी।

पांव से मोहताज फिर भी घर में बैठकर किया योगा

आज की जनधारा

सांची। नगर के पूर्व पार्षद रतन लाल जायसवाल लगभग एक वर्ष से अपनी घुटनों की बीमारी से पीडित हैं तथा घर में आराम कर रहे हैं। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का समाचार मिलते ही मजबूरी होने के बाद भी अपने पलंग पर बैठ कर योगा कार्यक्रम का हिस्सा बने तथा योग किया। इसके साथ ही श्री जायसवाल ने 21 जून को ही योगा कार्यक्रम में शामिल होने आये मप्र शासन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल का जन्मदिन होने पर उन्हें बधाई दी तथा तथा उनके यहां पहुंचने वालों को बिस्किट बांटकर जन्मदिन मनाया इस अवसर पर उनके साथ उनके सहयोगी भी रहे।

खजांची रामकली बाई इंग्लिश स्कूल में आयोजित A.I. और रोबोटिक्स समर कैंप का आज समापन कार्यक्रम सम्पन्न

आज की जनधारा

करेली। नगर एवं जिले की अग्रणी शैक्षणिक संस्था खजांची रामकली बाई आदर्श इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में दिनांक 8 जून से 21,जून तक 15 दिनों का समर कैंप आयोजित किया गया जिसमें बच्चों ने अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा पर आधारित समर कैंप में अ्र टूल्स तथा रोबोटिंगी 3ऊ प्रिंटिंग इत्यादि स्किल सीखी तथा शानदार प्रोजेक्ट बनाकर अपनी प्रस्तुति दी आज 21जून 2026 को आदर्श शिक्षण समिति के सचिव राजीव अग्रवाल, सहसचिव अनिल पालीवाल सहकोषाध्यक्ष रविंदरपाल सिंह लाम्बा एवं समिति सदस्य आदर्श कोहली की उपस्थिति में कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा सम्मानिति यूथ आइकन शिवम मिश्रा रहे,जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए के आर बी विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की,कार्यक्रम में अभिभावकों की और से मित्र मिलन

के अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल ने समर कैंप के दिनों में बच्चों के द्वारा मोबाइल से दूरी बनाकर प्रोजेक्ट वर्क पर कार्य कर रहे पर आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी इस तरह के कैंप आयोजित किए जाने की सराहना की कार्यक्रम को आदर्श शिक्षण समिति के सचिव राजीव अग्रवाल,सहसचिव अनिल पालीवाल,सदस्य आदर्श कोहली ने भी संबोधित किया,कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट वितरण किए गए तथाएमडल इन्नोवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रसिद्ध डेटा साइंटिस्ट इंजी. सुनील पटेल तथा इंजी. नेतराम पटेलों के द्वारा के आर बी विद्यालय में अपने 15 दिन के अनुभव का साझा किया तथा विद्यालय के अनुशासन व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लगातार विद्यालय को उनकी टीम के द्वारा सहयोग तथा सतत मार्गदर्शन भी विद्यार्थियों को देने का आश्वासन दिया । कार्यक्रम का मंच संचाल विद्यालय प्राचार्य द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन वरिष्ठ शिक्षक अनुराग सोनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकअभिभावक, एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

शराब दुकान पर कट्टा लहराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, देशी कट्टा और चाकू बरामद

आज की जनधारा

कटनी। शहर के व्यस्त स्टेशन चौराहा स्थित शराब दुकान में कर्मचारी को कट्टा दिखाकर धमकाने और दहशत फैलाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे शहर में इसकी चर्चा हो रही थी।

वायरल वीडियो के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई- पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए मुख्य आरोपी गोलू सक्सेना (पिता विजय सक्सेना, निवासी गांधीगंज) को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ वारदात में शामिल जानू उर्फ महेंद्र चौहान (पिता

छोटेलाल चौहान) एवं अंशुल भारती (पिता राजेश भारती), निवासी रंगनाथ नगर को भी हिरासत में लिया गया है।

मुख्य आरोपी से देशी कट्टा और कारतूस बरामद- पुलिस की तलाशी के दौरान मुख्य आरोपी गोलू सक्सेना के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं उसके दोनों साथियों के पास से धारदार चाकू जब्त किए गए हैं। पुराने विवाद के चलते हुई वारदात-प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि शराब दुकान के कर्मचारी और मुख्य आरोपी के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने दुकान पहुंचकर कर्मचारी को धमकाने का प्रयास किया।

बड़ी साजिश के एंगल से भी जांच- कोतवाली पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि मामला केवल डराने-धमकाने तक सीमित था या इसके पीछे किसी बड़ी पूर्व नियोजित साजिश की योजना थी। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके आपसी संबंधों की भी जांच कर रही है। आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई जारी- पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद हथियारों को जब्त कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

रात 2 बजे संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, 17 वर्षीय बालिका का विवाह रुकवाया

आज की जनधारा

कटनी। विकासखण्ड कटनी के ग्राम जरवाही में बीते रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे होने जा रहे बाल विवाह को कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा गठित महिला एवं बाल विकास ,राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कोर टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए रोक दिया। बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त हुई थी की, ग्राम जरवाही में एक 17 वर्षीय बालिका का बाल विवाह हो रहा है, इस पर मुस्तैद जिला प्रशासन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से इसे रुकवाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन से सूचना प्राप्त होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति कटनी

एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।

दस्तावेजों की जांच कर की कार्यवाही- जिला प्रशासन की संयुक्त टीम में सम्मिलित श्री मनीष तिवारी, बाल संरक्षण अधिकारी, कटनी, श्री योगेश बघेल, अध्यक्ष एवं श्री दुर्गेश शर्मा, सदस्य, बाल कल्याण समिति कटनी एवं श्री संजय दुबे, थाना प्रभारी, माधव नगर द्वारा मौके पर पहुँच कर पाया गया कि बालिका के विवाह की तैयारी की जा रही थी। संयुक्त टीम द्वारा बालिका के आयु सम्बन्धी दस्तावेजों की जाँच की गई। बालिका के जन्म प्रमाण पत्र अनुसार उसकी आयु 17 वर्ष पाई गई।जो विवाह की वैधानिक आयु से कम थी।

परिजनों को परामर्श देकर रुकवाया बाल विवाह- प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि विवाह के लिए बालिका की वैधानिक आयु 18 वर्ष है। इससे कम आयु में होने वाला विवाह बाल विवाह कहलाता है और यह कानूनन अपराध है। जिला प्रशासन की टीम द्वारा परिजनों को समझाइश और परामर्श दिए जाने के बाद परिजनों ने सहमति व्यक्त की कि वे अब बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही करेंगे।

लमतरा ब्रिज हादसा: अब होगी बड़ी कार्रवाई! कलेक्टर का एक्शन, माफियाओं में हड़कंप

आज की जनधारा

कटनी। लमतरा ब्रिज पर हुए भीषण हादसे में चार लोगों की मौत के बाद अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे खनिज कारोबार और प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। हादसे के बाद अवैध पत्थर परिवहन को वैध साबित करने के लिए कथित तौर पर ई-खनिज पोर्टल का दुरुपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 जून को सतना कलेक्टर को पत्र भेजकर संबंधित स्टॉक होल्डर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की है।

हादसे के बाद जनरेट हुई ईटीपी, उठे बड़े सवाल- जानकारी के मुताबिक 14 जून की शाम लगभग

4 बजे से 4:15 बजे के बीच लमतरा ब्रिज पर यह दर्दनाक हादसा हो चुका था। लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के लिए ईटीपी नंबर 2610398685 करीब आधे घंटे बाद शाम 4:44 बजे ऑनलाइन जनरेट की गई। बताया जा रहा है कि यह ईटीपी सतना जिले के रघुराजनगर क्षेत्र स्थित ग्राम सकरिया के पट्टाधारक एवं स्टॉक होल्डर आशुतोष मिश्रा और बद्री विशाल मिश्रा के खाते से जारी हुई थी।

दूरी और समय के गणित ने खोली पोल- सूत्रों के अनुसार सतना से कटनी की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है, जिसे तय करने में चार घंटे से अधिक का समय लगता है। ऐसे में शाम 4:44 बजे जनरेट हुई ईटीपी के आधार पर वाहन रात करीब 8:54 बजे के बाद ही कटनी पहुंच सकता था। जबकि संबंधित वाहन हादसे के समय पहले से ही लमतरा ब्रिज पर मौजूद था। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या दुर्घटना के बाद अवैध परिवहन को वैध दिखाने के लिए दस्तावेज तैयार किए गए।

कलेक्टर ने मांगी कठोर कार्रवाई- सूत्रों के मुताबिक कटनी कलेक्टर द्वारा भेजे गए पत्र में इस पूरे मामले को शासकीय डिजिटल प्रणाली के दुरुपयोग और गंभीर अनियमितता बताते हुए संबंधित पक्षों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी यह भी है कि सतना प्रशासन अब मामले में एफआईआर दर्ज कराने, जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। लीज निरस्तीकरण तक की सिफारिश-सूत्रों का दावा है कि संबंधित खदान और स्टॉक होल्डर की लीज, पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य अनुमतियों की समीक्षा कर उन्हें निलंबित या निरस्त किए जाने की भी अनुशंसा की गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जांच के घेरे में पूरा नेटवर्क- मामले के सामने आने के बाद अब जांच का दायरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह पता लगाया जाएगा कि 14 जून की शाम 4:44 बजे ईटीपी किसके निर्देश पर और किस कंप्यूटर आईडी अथवा लॉगिन के माध्यम से जारी की गई। लमतरा ब्रिज हादसे में चार लोगों की जान जाने के बाद अब प्रशासन की नजर केवल दुर्घटना पर ही नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद कथित अवैध परिवहन और दस्तावेजी हेरफेर के पूरे नेटवर्क पर है।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने प्रभावी कदम उठाएं : कलेक्टर, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

आज की जनधारा

रायसेन। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने किए जा रहे कार्यो और गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर विश्वकर्मा तथा एसपी आशुतोष गुप्ता द्वारा गत बैठक के पालन प्रतिवेदन अनुसार संबंधित अधिकारियों से अभी तक की गई कार्यवाही की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर विश्वकर्मा तथा एसपी गुप्ता ने जिले में ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए दुर्घटना संभावित स्थलों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने विभिन्न उपायों पर चर्चा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने शीघ्र कार्यवाही के निर्देश

दिए। बैठक में स्कूल, कॉलेज चिकित्सालय सहित अन्य स्थलों के समीप सड़कों पर कैट आई, विभिन्न संकेतक चिन्ह या साइन बोर्ड, रैलिंग लगाने के भी निर्देश दिए। बैठक में स्कूल, कॉलजों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित किए जाने पर भी चर्चा की गई। साथ ही हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रकरणों पर चर्चा कर प्रभावितों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक, यातायात प्रभारी लता मालवीय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मऊगंज प्रशासन की नाक के नीचे न्याय का 'चीरहरण': 3 दिन में खड़ी हो गई अवैध दीवार, फरियादी काटता रहा दफ्तरों के चक्कर

न्यायालय में लंबित है मामला, फिर भी दबंगों ने तान दी इमारत; 'कलेक्टर' के नाम का बहाना बना कर तमाशा देखता रहा प्रशासनिक अमला

आज की जनधारा

सुशासन और कानून के दावों के बीच मऊगंज से एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सूबे की सरकार भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों पर नकेल कसने का दम भरती है, वहीं दूसरी तरफ मऊगंज में एक फरियादी अपनी ही रजिस्ट्री शुदा जमीन को लुटता देखने के लिए विवश कर दिया गया। पूरा मामला खसरा नंबर 74/1/1 का है। माजन गांव के फरियादी विकास तिवारी ने अपनी गाढ़ी कमाई के लाखों रुपये देकर यह जमीन भू-स्वामी पार्वती तिवारी से कानूनी तौर पर क्रय की थी। रजिस्ट्री विकास तिवारी के नाम पर है, जिसमें चौहद्दी का स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन रसूख और प्रशासनिक लापरवाही के गठजोड़ ने इस वैध दस्तावेज को महज एक रद्दी का टुकड़ा बना दिया। 3 दिन में 'साहबों' की सुस्ती और विपक्ष की 'फुर्ती' हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन पर कब्जा हुआ, उसका मामला मऊगंज कलेक्टर न्यायालय में लंबित है और अगली सुनवाई 25 जून को नियत है। लेकिन न्यायालय की अवमानना करते हुए दूसरे पक्ष

ने महज तीन दिनों के भीतर विवादित जमीन पर न सिर्फ घर खड़ा कर दिया, बल्कि उस पर शीट (छत) भी रख दी। आशंका है कि आगामी चौबीस घंटों में वहां रहना भी शुरू कर दिया जाएगा। इन तीन दिनों के भीतर फरियादी विकास तिवारी ने अपनी जमीन बचाने के लिए कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। वह तहसीलदार, पटवारी, थाना, एस डी एम और जिला कार्यालय की चौखट पर सिर पटकता रहा, लेकिन साठगांठ या सुस्ती के शिकार हो चुके अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इंतजार' के पीछे की कड़वी सच्चाई जब पीड़ित अधिकारियों के पास गुहार लगाने पहुंचा, तो उन्हें जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के नए-नए बहाने सौंप दिए गए। किसी ने कहा– कलेक्टर साहब के यहां से आदेश लेकर आइए। किसी ने तर्क दिया– स्टे (स्थगन आदेश) की अवधि समाप्त हो चुकी

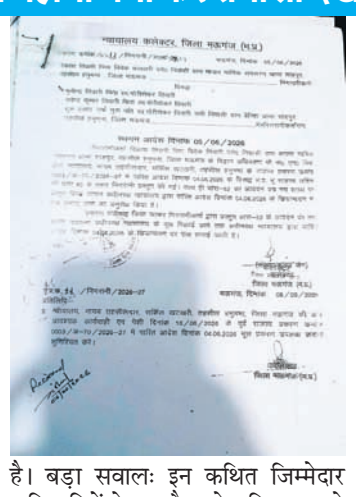

है। बड़ा सवालः इन कथित जिम्मेदार अधिकारियों से यह कौन पूछेगा कि अगर स्टे समाप्त होने का दावा है, तो उसका लिखित आदेश कहां है? किस कानून की किताब में लिखा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने पर भी दूसरा पक्ष तीन दिनों में पक्का निर्माण कर सकता है जब विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो पुलिस और राजस्व अमले ने 'थाने' और 'तहसील' में बैठकर निर्माण होने ही क्यों दिया

कानून का पालन करने वाले को मिली 'सजा'?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दुखद पहलू यह है कि विकास तिवारी ने कानून को हाथ में नहीं लिया। वह बिना किसी विवाद या हिंसक टकराव के, एक सभ्य नागरिक की तरह न्याय के लिए दर-दर भटकता रहा। लेकिन प्रशासन की इस मूक सहमति ने यह संदेश दे दिया है कि मऊगंज में कानून का पालन करने वाले की सुनवाई नहीं, बल्कि कानून को ठेंगा दिखाने वाले की 'जीत' तय है। अब देखना यह है कि न्यायालय में विचाराधीन मामले को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करने वाले विपक्ष पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता हैं? क्या विकास तिवारी को उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी जमीन वापस मिलेगी, या फिर मऊगंज का यह प्रशासनिक अमला आगे भी 'लिखित आदेश' की आड़ में अपनी फाइलों को दबाए बैठा रहेगा।

खाद-बीज की मांग को लेकर हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद उतारा गया

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हर्रहवा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब खाद-बीज नहीं मिलने से नाराज एक युवक अपनी मांगों को लेकर हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक कृषि कार्य के लिए खाद और बीज उपलब्ध नहीं होने से परेशान था। अपनी समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। काफी देर तक चले समझाइश और बातचीत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस टीम ने युवक को शांत कराया। इसके बाद युवक स्वेच्छा से टावर से नीचे उतर आया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन और पुलिस के लिए बढ़ती चुनौती सिंगरौली जिले में अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर मोबाइल टावर या बिजली के टावरों पर चढ़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाएं न केवल संबंधित व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालती हैं, बल्कि प्रशासन और पुलिस के लिए भी गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। घटना के बाद पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।

विकास के दावों के बीच बदहाल वैगा बस्ती, मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे आदिवासी परिवार

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिला मुख्यालय क्षेत्र में विकास और आधारभूत सुविधाओं के दावों के बीच नगर निगम के वार्ड क्रमांक-22 स्थित वैगा बस्ती की तस्वीर आज भी बदहाल बनी हुई है। बस्ती में रहने वाले आदिवासी परिवार बिजली, पेयजल, सड़क, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला बनने के बाद शहर के कई हिस्सों में विकास कार्य हुए, लेकिन वैगा बस्ती अब भी उपेक्षा का शिकार है। बस्तीवासियों के अनुसार क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं होने से गंदगी फैली रहती है। बरसात के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। वहीं स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को दूषित पानी का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बना रहता है। बिजली और सड़क की समस्या से बढ़ रही परेशानियां स्थानीय निवासियों का कहना है कि बस्ती में बिजली व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। कई परिवारों को आज भी पर्याप्त विद्युत सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। सड़क और आवागमन की बेहतर व्यवस्था न होने के कारण लोगों को आने-जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा सीधा असर वैगा बस्ती में रहने वाले बच्चों का भविष्य भी सुविधाओं के अभाव से प्रभावित हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि सड़क, बिजली और अन्य

बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कई बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित होने से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। चुनाव के बाद भूल जाते हैं जनप्रतिनिधि बस्तीवासियों ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि बस्ती में पहुंचकर विकास के बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों का कहना है कि वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। मूलभूत सुविधाओं की मांग वैगा बस्ती के निवासियों ने जिला प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि क्षेत्र में तत्काल सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, नियमित सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि विकास तभी सार्थक होगा जब शहर के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे और आदिवासी बस्तियां भी मुख्यधारा के विकास से जुड़ सकें।

डिक्की मध्यप्रदेश ने तैयार किया उद्यमिता विस्तार का रोडमैप, सिंगरौली के प्रतिनिधियों ने निभाई अहम भूमिका

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले में डिक्की (दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित उद्यमिता विस्तार कार्यशाला-2026 में प्रदेशभर के जिला एवं संभागीय समन्वयकों, पदाधिकारियों और उद्यमियों ने भाग लेकर उद्यमिता को नई दिशा देने संबंधी महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। कार्यशाला में सिंगरौली जिले का प्रतिनिधित्व डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंजी. विद्याभूषण ने किया। कार्यशाला में प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला उद्यमिता कोर टीम गठित करने का निर्णय लिया गया। यह टीम नए उद्यमियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी। साथ ही एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने पर भी सहमति बनी। स्थानीय उद्यमों को मिलेगा प्रोत्साहन बैठक में सामूहिक सुविधा केंद्र , क्लस्टर आधारित उद्यमिता, शासकीय खरीद, वेंडर डेवलपमेंट, निर्यात संवर्धन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा युवाओं, महिलाओं

और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। कार्यशाला का शुभारंभ डिक्की मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष डॉ. पंकज पाटिल ने किया। उन्होंने कहा कि डिक्की केवल एक उद्योग संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सशक्त मंच है, जो नए उद्यमियों के निर्माण और आर्थिक नेतृत्व विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमिता पर विशेष फोकस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं डिक्की मध्यप्रदेश के अध्यक्ष डॉ. अनिल सिरवैया ने कहा कि आगामी दो से तीन वर्ष अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने जिला स्तर पर संगठित प्रयास, उद्यमिता प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार उपलब्धता और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एक जिला-एक उत्पाद निर्यात संवर्धन, एमएसएमई प्रोत्साहन, विक्रेता विकास और शासकीय खरीद जैसे विषयों पर भी विस्तृत मार्गदर्शन दिया।सिंगरौली में उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा सिंगरौली से शामिल हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंजी. विद्याभूषण ने कहा कि जिले के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए डिक्की के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंगरौली की औद्योगिक संभावनाओं, स्थानीय संसाधनों और युवाओं की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए नए उद्यमियों को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। कार्यशाला के समापन अवसर पर डिक्की मध्यप्रदेश ने अपना विजन प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के हर जिले में उद्यमिता का मजबूत नेटवर्क विकसित करने का संकल्प दोहराया। संगठन का उद्देश्य रोजगार सृजन, आर्थिक सशक्तिकरण और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यशाला में सिंगरौली से डिविजनल कोऑर्डिनेटर विजय शंकर नीरत ₹रोमी₹, डिक्की सदस्य बसंत कुमार साकेत सहित जिले के अन्य उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भी भाग लिया। सभी प्रतिनिधियों ने सिंगरौली में उद्यमिता विस्तार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का संकल्प व्यक्त किया।

NH-39 पर मौत बनकर दौड़ा कोयला लदा ट्रक, दो बाइक सवारों को रौंदते हुए खाई में पलटा

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले में वर्षों से बदहाली का शिकार राष्ट्रीय राजमार्ग-39 (NH-39) एक बार फिर गंभीर सड़क हादसे का गवाह बना। जियावन थाना क्षेत्र के ग्राम जोगनी स्थित खाखन पुल के पास सोमवार सुबह सिंगरौली से सीधी की ओर जा रहा कोयला लदा ट्रक दो बाइक सवारों से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक भी वाहन के केबिन में फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खाखन पुल के समीप अचानक हुई इस दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जियावन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को केबिन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं घायल बाइक सवारों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में अलग-अलग चर्चाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रक चालक बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जबकि कुछ लोग सड़क की खराब स्थिति और तेज रफ्तार को भी हादसे की वजह मान रहे हैं। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। NH-39 की बदहाली पर फिर उठे सवाल इस हादसे के बाद एक बार फिर NH-39 की बदहाल

स्थिति चर्चा में आ गई है। सिंगरौली-सीधी मार्ग की महत्वपूर्ण सड़क मानी जाने वाली इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है। जगह-जगह सड़क क्षतिग्रस्त है, निर्माण कार्य अधूरा है और सुरक्षा इंतजाम भी नाकाफी बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां अब तक ठोस समाधान नहीं निकाल सकी हैं। लगातार हादसों से बढ़ रही चिंता क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पिछले डेढ़ दशक से अधूरी पड़ी NH-39 परियोजना के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। लगातार हो रहे हादसों ने निर्माण एजेंसियों और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

NH-39 किनारे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका से क्षेत्र में फैली सनसनी

आज की जनधारा

सिंगरौली। सिंगरौली जिले के सिंगरौली-सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-39) के किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सरजू खैरवार (40 वर्ष) पुत्र प्रेमलाल खैरवार, निवासी ग्राम भर्रा, थाना चितरंगी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सरजू खैरवार शुक्रवार को गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका। शनिवार को उनका शव सिंगरौली-सीधी मार्ग स्थित NH-39 के किनारे मिलने की सूचना सामने आई। शव मिलने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और परिजन भी मौके पर पहुंच गए। घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। शव मिलने की परिस्थितियों को देखते हुए हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है और मामले की जांच जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मोरवा पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले में पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के कुशल निर्देशन तथा सुश्री रोशनी कुर्मी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिंगरौली के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोरवा निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह की टीम के द्वारा बलात्कार के प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी में बताया गया कि फरियादी अनन्त कुमार पनिका पिता रामधारी पनिका उम्र 38 वर्ष निवासी पिपरखड़ थाना मोरवा जिला सिंगरौली (म.प्र.) थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17.06.2026 को सुबह 06 बजे मैं काम (मजदूरी) करने घर से बाहर गया था। करीब 11 बजे दिन जब घर वापस आया तो मेरी पत्नी बताई कि लड़की सुबह करीब 07 बजे बकरी चराने के लिये गांव में गयी थी। जो घर वापस नहीं आयी तब हम लोग सोचे की कहीं पास पड़ोस में गई होगी लेकिन जब बहुत समय तक नहीं लौटी तो पता तलाश करने लगे

लेकिन कोई पता नहीं चला। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाना व उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी दिनेश पनिका पिता मिरई पनिका उम्र 21 वर्ष निवासी पिपरखड थाना मोरवा जिला सिंगरौली को आज दिनांक 21.06.26 को जरिये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपी अपने घर मे है जिसकी सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मोरवा द्वारा एक टीम बनाकर रवाना किया गया जो ग्राम पिपरखड के पास पहुंचकर आरोपी दिनेश पनिका को घेराबंदी कर पकडा गया गिरफ्तार कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपी को जिला जेल सिंगरौली भेजा गया है। उक्त करवाई में उप.निरी.एन.पी.तिवारी, सउनि.संतोष सिंह, सउनि.संजीत सिंह, प्र.आर.अर्जुन सिंह, प्रआर. 376 कुलदीप शर्मा, आर.अजय यादव, कमलेश तिवारी,रियाज आलम, राकेश यादव की महत्तवपूर्णभूमिका रही।

सिंगरौली में पुलिस की बड़ी नाइट कॉम्बिंग, 222 बदमाशों और आरोपियों पर कार्रवाई

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सिंगरौली पुलिस ने रविवार रात व्यापक स्तर पर नाइट कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिलेभर में 222 बदमाशों एवं आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिससे अपराधियों में दहशत और आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के मार्गदर्शन तथा पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत, पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा रेंज हेमंत चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के निर्देशन में जिले के सभी अनुभागीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। इसके लिए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन तलाशी और गश्त की गई। 20 स्थाई वारंटी सहित 222 लोगों पर कार्रवाई अभियान के दौरान पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 20 स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 81 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई। वहीं 69 निगरानी बदमाशों और 52 गुंडा बदमाशों की जांच एवं सत्यापन किया गया। पुलिस ने तकनीकी शाखा के सहयोग से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कट-ऑफ प्वाइंट स्थापित कर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। रातभर चले इस अभियान में संवेदनशील इलाकों, बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी गई। संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी नाइट कॉम्बिंग गश्त के

दौरान प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच की गई। देर रात बिना कारण घूम रहे लोगों से पूछताछ कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही यात्रियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की त्वरित सहायता व्यवस्था भी सक्रिय रखी गई। इसके अतिरिक्त बैंकों और एटीएम परिसरों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अपराधियों पर शिकंजा, नागरिकों में बढ़ा भरोसा पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य रात्रिकालीन कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। पुलिस की सक्रिय मौजूदगी से अपराधियों में भय का माहौल बना रहा, जबकि नागरिकों ने राहत और सुरक्षा का अनुभव किया। सिंगरौली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे।

सिंगरौली में शराबी चालकों पर बड़ी कार्रवाई, 12 पर लगा 1.05 लाख रुपये का जुमार्ना

आज की जनधारा

सिंगरौली । सिंगरौली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रभावी पालन को लेकर सिंगरौली यातायात पुलिस ने रविवार देर रात विशेष जांच अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान 12 वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए, जिनके वाहनों को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने सभी मामलों में कुल 1.05 लाख रुपये से अधिक का जुमार्ना अधिरोपित किया है। पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रजापति के मार्गदर्शन में 21 और 22 जून की मध्यरात्रि को यह विशेष अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर के माजन मोड़, निगाही मोड़, अमलोरी तिराहा और पुराने ट्रैफिक तिराहा सहित प्रमुख स्थानों पर औचक वाहन जांच की। 120 वाहनों की जांच, 12 चालक मिले नशे में अभियान के दौरान करीब 120 वाहनों की जांच की गई। जांच के समय पुलिस ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद वाहन चलाने से

मानसिक संतुलन और वाहन पर नियंत्रण प्रभावित होता है, जिससे गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। जांच के दौरान 12 चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। सभी वाहनों को जब्त कर वैधानिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया, जहां दोषी चालकों पर एक लाख पांच हजार रुपये से अधिक का जुमार्ना लगाया गया। छह माह के लिए निलंबित हो सकते हैं लाइसेंस यातायात पुलिस के अनुसार न्यायालय के आदेश के आधार पर सभी दोषी वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित कराने संबंधी प्रस्ताव जिला परिवहन कार्यालय को भेजा जाएगा। यातायात पुलिस का कहना है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिला है। वर्ष 2025 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। पुलिस का मानना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहने से सड़क सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। यातायात पुलिस की अपील यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का पालन कर न केवल स्वयं सुरक्षित रहें, बल्कि दूसरों की जान भी सुरक्षित रखें।

कलेक्टर की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित

जनकल्याण योजनाओं की प्रगति पर कलेक्टर की सख्त समीक्षा

लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के स्पष्ट निर्देश

आज की जनधारा

खरगोन। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागृह में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, राजस्व सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए जनहित से जुड़े मामलों में तत्परता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने कहा कि शासन की प्राथमिक योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुँचना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई और पंजीयन बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। 28 जून को झिरन्या में महामहिम राज्यपाल के संभावित दौरे को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य

व्यवस्थाओं की विशेष समीक्षा की गई। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने निर्देश दिए कि झिरन्या में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविर में एनीमिया के लिए पृथक काउंटर लगाया जाए। साथ ही आयुष्मान, सिकल सेल, टीबी, जनरल हेल्थ, ब्लड डोनेशन कैंप एवं आधार काउंटर अलग-अलग एवं सुव्यवस्थित रूप से स्थापित किए जाएँ, ताकि आमजन को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएँ सुगमता से उपलब्ध हो सकें। बैठक में पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) की समीक्षा में निर्धारित 14 दिवस से कम अवधि तक बच्चों को रखने के मामलों पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इस पर सीडीपीओ खरगोन एवं भगवानपुरा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सिविल सर्जन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को नियमित भ्रमण कर केंद्रों की गुणवत्ता, उपचार एवं व्यवस्थाओं की सतत जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही आयुष विभाग को निर्देशित किया गया कि एनआरसी में रुकने वाली माताओं के लिए योग एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की नियमित व्यवस्था कराई जाए, जिससे माताओं व बच्चों के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार हो। बैठक में सिकल सेल स्क्रीनिंग को प्रभावी बनाने के लिए भगवानपुरा एवं भीकनगांव क्षेत्रों में पृथक-पृथक विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों की समय पर जांच हो सके और आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आंगनवाड़ी पंजीयन में लापरवाही सामने आने पर महेश्वर, बड़वाह एवं भगवानपुरा के सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक बाल देखभाल एवं पोषण शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने तथा तकनीकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ मिल सके। बैठक में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान पाठ्य-पुस्तकों का वितरण दो दिनों के भीतर पूर्ण करने तथा ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व विभाग अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी प्रकरणों को समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। बैठक में जनकल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश सभी विभागों को दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

ई-रिक्शा रैली से दिया हरित भविष्य का संदेश, सैकड़ों महिलाओं के साथ विधायक निवास पहुँचीं मनोरमा सोलंकी

आज की जनधारा

देवास। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन बचत के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रविवार को अनूठी ई-रिक्शा रैली का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनोरमा सोलंकी के नेतृत्व में निकली इस रैली में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया और शहरवासियों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। ई-रिक्शा रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर निकली। रैली के दौरान महिलाओं ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण का आह्वान किया। रैली जहां-जहां से गुजरी, वहां लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सकारात्मक संदेश प्रसारित हुआ। रैली का समापन विधायक गायत्री राजे पंवार के निवास पर हुआ, जहां महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विधायक का

स्वागत कर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मनोरमा सोलंकी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में ई-वाहनों का उपयोग समय की मांग बन गया है। यदि हम आज से ही स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को अपनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी किसी भी जनजागरूकता अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी उद्देश्य से महिला मोर्चा ने ई-रिक्शा रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने भी लोगों से अधिक से अधिक ई-वाहनों के उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव संभव हैं और हर नागरिक की सहभागिता से ही स्वच्छ, हरित और स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है।

रक्तदान महादान - जीवन बचाने का संकल्प

जेआईटी बोरावाँ में जागरूकता, सेवा और राष्ट्रधर्म का संगम

एनसीसी कैडेट्स बने मानव सेवा की मिसाल

आज की जनधारा

खरगोन। 36 एमपी एनसीसी बटालियन खंडवा के पीआई स्टाफ, एनसीसी अधिकारियों एवं कैडेट्स द्वारा रक्तदान महादान की भावना को सशक्त रूप देते हुए जेआईटी कॉलेज बोरावा में व्यापक रक्तदान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 76 के अंतर्गत संपन्न हुआ, जिसमें जिला अस्पताल खरगोन की ब्लड बैंक टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को रक्तदान के महत्व, सामाजिक दायित्व और मानव जीवन की रक्षा में इसकी भूमिका से अवगत कराना रहा। जिला अस्पताल की टीम ने कैडेट्स को बताया कि रक्तदान ऐसा महादान है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पतालों में रक्त की आपूर्ति केवल स्वैच्छिक रक्तदाताओं पर ही निर्भर रहती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है और इससे शरीर पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इस अवसर पर कमान अधिकारी कर्नल के. राजेश ने अपने संदेश में कहा कि एनसीसी कैडेट्स सदैव समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। रक्तदान मानवता की सर्वोच्च सेवा है और युवाओं को इसके प्रति जागरूक होकर आगे आना चाहिए। उन्होंने कैडेट्स से भविष्य में नियमित स्वैच्छिक रक्तदाता बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया गया तथा इसके स्वास्थ्य लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई। कैडेट्स को बताया गया कि एक यूनिट रक्त से कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है तथा दुर्घटना, शल्य चिकित्सा एवं गंभीर बीमारियों के समय रक्तदान जीवनरक्षक सिद्ध होता है। शिविर में पात्र अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कैडेट्स ने स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव सेवा का प्रेरक संदेश दिया। जिला अस्पताल खरगोन की टीम द्वारा रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी कैडेट्स ने रक्तदान के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने एवं पात्र होने पर नियमित स्वैच्छिक रक्तदान करने का संकल्प लिया।

दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार

पल्स पोलियो अभियान

उज्जैन। भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेर्शानुसार वर्ष 2026 में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल द्वारा बताया कि जिला उज्जैन में राष्ट्रीय पल्स पोलियो का आयोजन 28 जून 2026 रविवार को किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों को दो बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। विभाग द्वारा इस के लिए सम्पूर्ण जिले में पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां दो बूंद पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। दिनांक 28 जून को पोलियो की दवाई पीने से वंचित बच्चों को दिनांक 29 व 30 जून 2026 को घर-घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के दौरान ईंट भट्टे, निर्माण स्थल, झुग्गी-झोपड़ियां एवं घुमक्कड़ आबाद स्थल पर विशेष ध्यान देकर लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति का प्रयास किया जाएगा। अतः समस्त माता-पिता, अभिभावकों से अपील है कि अपने 0 से 5 वर्ष उम्र के सभी बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की दवाई अवश्य पिलाएं।

जिला दिव्यांग पुनर्वास केद्र में रोजगार मेले का आयोजन किया गया

आज की जनधारा

उज्जैन। संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भोपाल के निदेर्शानुसार एवं अहमदाबाद के सहयोग से दिव्यांगजनों को उनकी योग्यता के अनुरूप निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, जिला चिकित्सालय परिसर, उज्जैन में रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। इसमें जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, उज्जैन में आयोजित रोजगार मेले में 56 दिव्यांगजनों ने पंजीयन कर सहभागिता की। रोजगार मेले में अहमदाबाद से श्रीमती

प्रतीक्षा दुबे के द्वारा 17, बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन से श्री राजकुमार पटेल के द्वारा 26, नेशनल करियर सेंटर (व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र), जबलपुर से श्री चंद्रकांत पाटिल के द्वारा 24 तथा डॉ. रेड्डीज फाउंडेशन, इंदौर से श्री रविन्द्र प्रजापति के द्वारा 18 तथा स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से श्रीमती शिल्पा निगम द्वारा 12 दिव्यांगजनों का रोजगार हेतु चिन्हांकन कर उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के आधार पर संक्षिप्त सूची में नाम दर्ज कराया गया एवं रोजगार संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस अवसर पर संयुक्त संचालक श्री सतीश सोलंकी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उज्जैन तथा प्रशासनिक अधिकारी, वोकेशनल काउंसलर व जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, उज्जैन के कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया गया तथा बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने इसमें सहभागिता की।

योग से स्वस्थ जीवन का संदेश: मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी

आज की जनधारा

मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का आयोजन बड़े उत्साह, ऊर्जा और अनुशासन के साथ किया गया। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग को केंद्र में रखते हुए यूनिवर्सिटी परिसर में विशेष योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम की शुरूआत सकारात्मक ऊर्जा और शांति के वातावरण के साथ हुई। इस अवसर पर योग विशेषज्ञ सुश्री अंजू सिंह ने प्रतिभागियों को योग एवं प्राणायाम के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया और उनके स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव को कम कर व्यक्ति को

आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में योग को अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विशेष रूप से बढ़ती उम्र में योग शरीर को सक्रिय, मन को स्थिर और जीवन को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस अवसर पर कहा कि मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सदैव विद्यार्थियों के समग्र विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और सकारात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक बल्कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी सशक्त बनाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने स्वस्थ, संतुलित एवं जागरूक जीवन के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन ने यूनिवर्सिटी परिसर में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मकता का संदेश प्रसारित किया।

आचार्य विराग विशुद्ध सागर महाराज के शिष्यों ने नंदीश्वर जिनालय की प्रतिमाओं की वंदना अगवानी में गूंजे जयकारे

आज की जनधारा

भोपाल। आचार्य विराग सागर महाराज के शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के आज्ञानुवृति आचार्य विभव सागर महाराज सा संघ राजधानी के नंदीश्वर जिनालय पहुंचे यहां पाद प्रक्षालन कर अगवानी की गई, प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया आचार्य संघ में छह मुनिराज और तीन आर्यिका माता है आचार्य संघ ने नंदीश्वर जिनालय की वंदना की और साथ ही परिसर में श्रावक संस्कार साहित्य केंद्र शास्त्र भंडार का अवलोकन किया, अध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने जिनालय का इतिहास बताया आचार्य श्री ने कहा ये विशाल नंदीश्वर जिनालय शहर ही नहीं देश विदेश के श्रद्धालुओं का श्रद्धा भक्ति आस्था का केंद्र है, जिनालय में विराजमान प्रतिमाओ के

दर्शन मात्र से जन्म जन्मान्तर के कर्मों का नाश हो जाता हे,, श्रद्धालुओं ने आचार्य संघ को नवधा भक्ति पूर्वक आहार चर्या कराई, आचार्य श्री को आहार कराने का सौभाग्य पंडित विमल सोरया डॉ सर्वज्ञ जैन पारिवार को प्राप्त हुआ इस अवसर पर प्रमोद चौधरी एडवोकेट डॉ सर्वज्ञ जैन विवेक जैन शैलेश जैन मुन्ना कवि मधुर जैन पदम जैन घर अशोक जैन योगाचार्य शीलचंद लचक्या जीतू सिलवानी प्रभात बरेला नितिन जैन नीरज प्रियेश शरद जैन सहित अनेक लोग मौजूद थे।

गांधी पी.आर. महाविद्यालय, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

आज की जनधारा

गांधी पी.आर. महाविद्यालय, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने सहभागिता कर योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर योग के महत्व एवं स्वस्थ जीवन में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग करने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया।

हर घर जल के लक्ष्य को लेकर कलेक्टर की सख़्त समीक्षा

जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता, गति और जवाबदेही पर जोर

आज की जनधारा

खरगोन। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुश्री मित्तल ने स्पष्ट किया कि जलापूर्ति से जुड़ा प्रत्येक कार्य समय-सीमा, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण होना चाहिए। बैठक में प्रगतिरत एवं शेष बचे कार्यों की ब्लॉकवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि जिन योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका तत्काल हैंडओवर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने कूप गहरीकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए कूप बंधाई, जल गुणवत्ता परीक्षण (वाटर टेस्टिंग) एवं विद्युत कनेक्शन जैसे सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में स्व सहायता समूहों द्वारा की जा रही जल कर वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुश्री मित्तल ने कहा कि वसूली की प्रक्रिया नियमित, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे ग्राम पंचायतों की जल व्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके। बैठक में महेश्वर एवं बड़वाह में जल वितरण व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर सुश्री मित्तल ने गंभीरता से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां-जहां वाल मैन की उपलब्धता नहीं है, वहां तत्काल नियुक्ति की जाए। साथ ही जल निगम एवं पंचायत की संयुक्त टीम गठित कर

जनसामान्य के साथ बैठक आयोजित कर मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया जाए। बैठक में पंचायत विभाग को निर्देशित किया गया कि नल जल उपभोक्ताओं का पंजीकरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराया जाए, जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन जल कर वसूली प्रारंभ हो सके। इससे नागरिकों को डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी तथा पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री मिलिंद कुमार नागदेवे, समस्त जनपद सीईओ एवं पीएचई विभाग के इंजीनियर उपस्थित रहे। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल से जुड़ी किसी भी समस्या को हल्के में न लिया जाए और आमजन को निर्बाध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मंदिरों की आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच हो – मुकेश नायक

आज की जनधारा

मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े विभिन्न मंदिर ट्रस्टों द्वारा धर्म, आस्था और सनातन परंपरा के नाम पर जनता की भावनाओं का राजनीतिक दोहन किया गया है। आज देश और प्रदेश के कई प्रमुख मंदिरों से जुड़े भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और चोरी के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। श्री नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश में महाकाल लोक, ओरछा स्थित श्री राम महालोक तथा धर्म एवं संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार और विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ओरछा परियोजना में 50 प्रति वर्गफुट की टाइल को 350 प्रति वर्गफुट की दर से खरीदे जाने जैसी शिकायतें सार्वजनिक हुई हैं, जो सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी अनेक गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियरों द्वारा निर्माण कार्य में लगभग 40 प्रतिशत तक

अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। इन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया है। श्री नायक ने कहा कि राम मंदिर परिसर में लगे कैमरों के बंद रहने तथा चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठे हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर निर्माण के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा दान में दी गई सोने-चांदी की राम शिलाओं का मुद्दा भी गंभीर चिंता का विषय है। बताया जाता है कि इनमें एक अत्यंत मूल्यवान शिला भी शामिल थी, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी। इन शिलाओं के संबंध में यह कहा गया कि उन्हें मंदिर की नींव में स्थापित कर दिया गया है, किंतु इस संबंध में कोई सार्वजनिक और पारदर्शी प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि देश की जनता और करोड़ों श्रद्धालुओं को यह जानने का अधिकार है कि धार्मिक परियोजनाओं और मंदिर ट्रस्टों में प्राप्त धन, दान और संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया गया। धर्म और आस्था के नाम पर एकत्रित धन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पूरे समाज के विश्वास पर आघात है। श्री नायक ने मांग की कि मध्य प्रदेश और देश के सभी प्रमुख मंदिर ट्रस्टों, मंदिर निर्माण परियोजनाओं तथा धार्मिक संस्थाओं के वित्तीय लेन-देन, निर्माण कार्यों और दान प्रबंधन की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ऑडिट कराई जाए। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके और दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो सके।

तिरछी नज़र से

महँगाईः टमाटर ने क्लास बदली – अब वह Middle Class नहीं रहा

प्रभातदत्त झा

सुधी पाठकों, इस देश में 'महँगाई' शब्द का उच्चारण करते ही नेता जी की भौंहें तन जाती हैं – 'कौन कह रहा है महँगाई है? देखिए, Inflation तो Control में है।' सरकारी आँकड़ों में Inflation 4-5% है। पर बाज़ार में जाइए – टमाटर सौ रुपये किलो, प्याज साठ, दाल डेढ़ सौ। हम पूछते हैं – 'यह Inflation किस बाज़ार में Control में है? हमें भी बताइए, हम भी वहीं से सब्ज़ी लेंगे।'

हमारी रसोई में एक मूक क्रांति हो रही है। पहले थाली में दाल, सब्ज़ी, चावल, रोटी होती थी। अब थाली में 'Budget Management' होता है। गृहिणियाँ अब गृहमंत्री नहीं – Finance Minister हैं। हर सुबह वे Market Survey करती हैं, तुलना करती हैं, और ऐसे विकल्प खोजती हैं जिनकी कल्पना कोई अर्थशास्त्री नहीं कर सकता।

जैसे — 'आज दाल नहीं, पर दाल जैसी दिखने वाली चीज़ बनाएँगे।' यह Culinary Innovation है, जो महँगाई की कोख से जन्मी है।

टमाटर की बात करें तो यह सब्ज़ी अब सब्ज़ी नहीं रही — यह Investment है। जब टमाटर दो सौ रुपये किलो था, तब लोग उसे तिजोरी में रखते थे। **एक सज्जन ने बताया** — 'भाई साहब, मैंने पाँच किलो टमाटर खरीदे थे। घर में रखे, दाम और बढ़े – तो बेच दिए। पाँच सौ का मुनाफा।' मैंने कहा, 'यह तो Trading है।' बोले, 'जी – Tomato Futures।' शेयर बाज़ार वाले नोट कर लें।

'थाली' पर राजनीति बड़ी रोचक है। हर सरकार कहती है — 'हमने सस्ती थाली दी।' विपक्ष कहता है – 'थाली खाली है।' सच यह है कि थाली है – पर उसमें जो होना चाहिए, वह या तो महँगा है, या 'Imported' है, या 'Out of Stock'। CSDS के एक सर्वे के अनुसार शहरी मध्यम वर्ग अब भोजन पर अपनी आय का 35-40% खर्च करता है – जो दस साल पहले 25% था। मतलब – जितना कमाते हैं, उसका बड़ा हिस्सा पेट में जाता है। पेट देशभक्त नहीं होता – वह सिर्फ भूखा होता है।

सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जो किसान टमाटर उगाता है, उसे पाँच रुपये किलो मिलता है। जो बीच में है, उसे पचास। और जो शहरी खरीदता है, वह डेढ़ सौ देता है। इस सफर में टमाटर का दाम तीस गुना बढ़ता है – पर किसान की आय नहीं। यह 'Supply Chain' है – जिसमें Supply किसान करता है और Chain बाकी सब पहनते हैं।

और जब महँगाई बढ़ती है तो नेता जी का प्रिय वाक्य आता है – 'जनता को कम खाना चाहिए, Obesity बढ़ रही है।' यानी समस्या का समाधान – समस्या को ही लक्ष्य बना दो। महँगाई ने Diet Control कर दिया – तो यह तो Health Policy है। सरकार और स्वस्थ्य को मिलकर इसका पेटेंट करा लेना चाहिए।

***निष्कर्ष — महँगाई कोई आँकड़ा नहीं है** — वह हर घर की रसोई में रोज़ जलती आग है, जो गृहिणी की आँखों में दिखती है जब वह बाज़ार से लौटती है और थैला हल्का होता है पर बिल भारी। असली सवाल यह है – जब थाली सिकुड़ती जा रही है, तो 'विकसित भारत' में आम आदमी की भूख का हिसाब कौन रखेगा?*

हर तीसरे दिन एक मौतः श्रमिक सुरक्षा अब भी अधूरा वायदा

कारखानों में श्रमिक और अन्य कामगारों की सुरक्षाः वर्तमान स्थिति और सुधार के सुझाव

अवनीश झा

रायपुर से बिलासपुर तक फैली रेलवे लाइन के किनारे जब कोई इस्पात कारखाने की चिमनी देखता है, तो उसे शायद यह न पता हो कि उस चिमनी के नीचे एक ऐसी दुनिया चलती है जहाँ हर सुबह काम पर जाने वाला मज़दूर यह भरोसा लेकर नहीं जाता कि वह शाम को सही-सलामत लौटेगा। बलौदाबाजार के धौराभाठा में कुछ महीने पहले हुई औद्योगिक दुर्घटना ने इस डर को फिर सच कर दिया - जांच में सामने आया कि किल्न का शटडाउन किए बिना मज़दूरों से जोखिमपूर्ण काम कराया गया, हाईड्रोलिक स्लाइड गेट बंद नहीं था, वर्क परमिट जारी नहीं हुआ था, और मज़दूरों को हीट रेसिस्टेंट एप्रन, सुरक्षा जूते व हेलमेट जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण तक नहीं दिए गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कारखाने के एक हिस्से का संचालन तत्काल रोकना पड़ा।

यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह उस तंत्र की झलक है जिसमें उत्पादन की रफ्तार अक्सर सुरक्षा की सीढ़ियाँ फलांगकर आगे निकल जाती है।

आंकड़े जो डराते हैं

श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते पाँच वर्षों में लगभग 6,500 मज़दूर फैक्ट्री, खदानों और निर्माण कार्यों में हुए हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत हादसे कारखानों में हुए। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक यह है कि 2017 और 2020 के बीच, भारत के पंजीकृत कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण हर दिन औसतन तीन मज़दूरों की मौत हुई और 11 घायल हुए, और इस दौरान कम से कम 3,331 मौतें दर्ज की गईं।

- रोज़ाना औसत 3 मौतें, 11 घायल (2017-2020, पंजीकृत कारखाने)
- 5 वर्षों में 96,500 मौतें (फैक्ट्री, खदान, निर्माण क्षेत्र)
- 14,710 दोषी ठहराए गए(2010-2020, धारा 92 व 96ए)
- सिर्फ़ 14 को सज़ा मिली(2018-2020 के बीच)

सबसे विचलित करने वाला आंकड़ा सज़ा को लेकर है - कानून किताबों में सख्त है, पर अमल में लगभग बेदम। और यह आंकड़े केवल पंजीकृत कारखानों के हैं – देश में लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके हादसों का कोई पुख्ता आंकड़ा ही दर्ज नहीं होता।

हाल की रिपोर्टिंग भी यही दिखाती है - 2025 में महाराष्ट्र और हरियाणा के कारखानों में 2,500 से ज़्यादा मज़दूर घायल हुए, जबकि निरीक्षण न तो पर्याप्त हैं और न ही उनमें श्रमिकों की कोई भागीदारी होती है।

शोध क्या कहता है

IIT कानपुर के एक अध्ययन ने इस संकट की जड़ें साफ़ पहचानी हैं। शोध के मुताबिक, बॉयलर जैसे संवेदनशील उपकरणों का संचालन अक्सर अप्रशिक्षित संविदा श्रमिकों के हवाले होता है, जिनके पास सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया की कोई ठीक ट्रेनिंग नहीं होती। साथ ही, कई उद्योग लागत घटाने के नाम पर वेंटिलेशन और अग्नि सुरक्षा जैसे बुनियादी ढांचे की अनदेखी करते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक पुराना पर अब भी प्रासंगिक अध्ययन बताता है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रति श्रमिकों की अनभिज्ञता ही ज़्यादातर औद्योगिक दुर्घटनाओं से न बच पाने की मूल वजह है, और इसके लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण ज़रूरी है।

छत्तीसगढ़ की ज़मीनी तस्वीर

छत्तीसगढ़ में स्थिति को सुधारने की कोशिशें ज़रूर हुई हैं, लेकिन चुनौतियाँ बड़ी हैं। रायगढ़ जिले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने हाल ही में पाँच कारखानों पर सख्ती दिखाई – जांच में सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी पाए जाने पर श्रम न्यायालय ने दोषी प्रतिष्ठानों पर कुल पाँच लाख पच्चीस हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया। उप संचालक राहुल पटेल का कहना था कि श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राज्य में निरीक्षण व्यवस्था को भी डिजिटल किया गया है। ALIS यानी ऑटोमेटेड लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम अब कंप्यूटर के ज़रिए रैंडम तरीके से कारखानों का चयन करता है और निरीक्षक को 48 घंटों के भीतर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है। इसके अलावा राज्य ने एक नई सुरक्षा फोर्स की दिशा में भी कदम बढ़ाया है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर उद्योगों को सुरक्षा, ऑडिट और आपदा प्रबंधन सेवाएं देगी।

बावजूद इसके, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिलों की एक हालिया बैठक में अधिकारियों ने कारखाना प्रबंधकों को फिर वही बुनियादी हिदायतें दोहराईं- सुरक्षा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और आपात मॉकड्रिल। यह दोहराव खुद बताता है कि निर्देश और अमल के बीच की खाई अब भी बनी हुई है।

सुधार की दिशा में क्या ज़रूरी है

संविदा श्रमिकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण : खासकर बॉयलर, किल्न और रासायनिक प्रक्रियाओं वाले कार्यों में स्थायी और ठेका श्रमिकों के बीच भेद खत्म कर समान सुरक्षा प्रशिक्षण देना।

निरीक्षण को मज़बूत और पारदर्शी बनाना : ALIS जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं का दायरा बढ़ाकर असंगठित क्षेत्र के छोटे कारखानों तक ले जाना।

सज़ा को वास्तविक बनाना : केवल जुर्माना नहीं, बल्कि बार-बार उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन जैसी ठोस कार्रवाई।

सुरक्षा समिति को वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य बनाना : हर पंजीकृत कारखाने में श्रमिक प्रतिनिधित्व वाली सक्रिय सुरक्षा समिति।

असंगठित क्षेत्र का डेटा संग्रह : जब तक 90 प्रतिशत श्रमिकों के हादसों का रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा, तब तक नीति निर्माण अधूरा रहेगा।

अंत में सुरक्षा हेलमेट और दस्तानों से कहीं ज़्यादा, यह भरोसे का सवाल है – उस भरोसे का, जो एक मज़दूर अपने घर से निकलते वक्त अपने परिवार को देता है कि वह लौटेगा। जब तक यह भरोसा कानून की किताबों से निकलकर फैक्ट्री के फर्श तक नहीं पहुंचता, तब तक हर चिमनी का धुआं किसी न किसी अनकही कीमत की याद दिलाता रहेगा।

एक कारखाना तभी सच में उत्पादक है, जब उसकी मशीनें चलें : मगर उससे पहले भी, और उससे ज़्यादा यह तय हो कि उसके मज़दूर हर शाम सही-सलामत घर लौटें।

-अवनीश झा,जालना महाराष्ट्र
(इंडस्ट्री-मामलों,मजदूर-आंदोलन और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और विशेषज्ञ)

शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य : बढ़ते बोझ के बीच उपेक्षित मुद्दा

रविकांत ठाकुर

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों, रिक्त पदों की कमी और डिजिटल दबाव के कारण खुद मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स और अध्ययनों में सामने आया है कि शिक्षकों में तनाव, बर्नआउट, चिंता और अवसाद की समस्या बढ़ती जा रही है, जो सीधे शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर रही है।

बढ़ते बोझ के प्रमुख कारण

कार्यभार की अधिकता - 30 हजार से अधिक रिक्त शिक्षक पदों के कारण एक शिक्षक कई कक्षाओं, विद्यार्थियों और प्रशासनिक कार्य संभाल रहा है। मिड-डे मील, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, चुनाव ड्यूटी जैसी जिम्मेदारियां पढ़ाई के साथ जुड़ गई हैं।

डिजिटल बोझ - 27 से अधिक एप्स और पोर्टलों पर बार-बार डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग। तकनीकी दिक्कतें, समय-सीमा और दोहराव शिक्षकों को मानसिक रूप से थका रहे हैं।

अन्य चुनौतियां - कम वेतन, पदोन्नति में देरी, संसाधनों की कमी, अभिभावकों-समाज का दबाव, COVID के बाद बढ़ी ऑनलाइन शिक्षण की आदतें और व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियां। ग्रामीण क्षेत्रों में अकेलेपन और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

प्रभाव क्या है?

शिक्षकों में लगातार थकान, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन और उदासीनता बढ़ रही है।

कई शिक्षक बर्नआउट की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जिससे कक्षा में उत्साह कम हो रहा है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

लंबे समय में यह डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

अध्ययनों के अनुसार, शिक्षकों का खराब मानसिक स्वास्थ्य विद्यार्थियों के सीखने, व्यवहार और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक असर डालता है।

समाधान की दिशा में कदम

कार्यभार संतुलन — रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू कर डुप्लिकेट काम कम करें।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता - स्कूलों में काउंसलिंग सेंटर, नियमित वर्कशॉप, योग-ध्यान कार्यक्रम और हेल्पलाइन की व्यवस्था।

ट्रेनिंग और सपोर्ट - शिक्षकों को स्ट्रेस मैनेजमेंट, समय प्रबंधन और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दें।

नीतिगत बदलाव - शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सर्वेक्षण कर समाधान निकालें। कई राज्यों में सफल मॉडल (जैसे टीचर वेलफेयर प्रोग्राम) अपनाए जा सकते हैं।

समाज की भूमिका - अभिभावक और समाज शिक्षकों का सम्मान बढ़ाएं, अनावश्यक दबाव कम करें।

निष्कर्षतः शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। यदि उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत नहीं होगा, तो शिक्षा व्यवस्था भी कमजोर रहेगी। छत्तीसगढ़ हो या मध्यप्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शिक्षकों के कल्याण और बेहतर शिक्षा वातावरण के लिए निरंतर आवाज उठाती रहेगी।

रविकान्त ठाकुर, (बच्चों को समुचित और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु शासकीय और अशासकीय स्तर पर कार्य करते हुए कई पुरस्कार प्राप्त, शिक्षकों के प्रशिक्षण में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण में महती भूमिका। म. प्र. और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को शैक्षिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान)

शून्य में गूँजती थापः एक विदा हो चुके पिता के नाम फादर्स डे

कैलेंडर की तारीखें जब 'फादर्स डे' की दस्तक देती हैं, तो दुनिया उत्सव के रंग में रंग जाती है। हर तरफ बधाइयों के शब्द और उपहारों के सिलसिले तैरने लगते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, जिसके लिए यह दिन किसी उत्सव का नहीं, बल्कि एक निशब्द एकांत और आँखों के कोरों में सिमटी नमी का होता है। मेरे पापा अब इस नश्वर संसार में नहीं हैं। उनके जाने से जीवन में जो खालीपन आया है, वह कोई ऐसा गड्ढा नहीं जिसे वक्त भर दे; वह तो एक अनंत शून्य है, जिसमें बस उनकी यादों की प्रतिध्वनि गूँजती रहती है।

पिता का होना दरअसल किसी उत्सव जैसा नहीं, बल्कि घर की अदृश्य नींव जैसा होता है। वे छत की तरह दिखते भले न हों, लेकिन पूरे वजूद को थामे रहते हैं। जब तक वे थे, दुनिया की हर धूप छाँव सी लगती थी और हर मुश्किल एक अदने से तिनके जैसी। उनके रहने से जो बेफिक्री का एक सुरक्षा-कवच मिला हुआ था, उनके जाते ही वह अचानक टूट गया। तब समझ आया कि कंधों पर ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना क्या होता है।

आज जब वे भौतिक रूप से मेरे पास नहीं हैं, तो मुझे अहसास होता है कि पिता केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार हैं, एक संस्कार हैं। वे मेरे भीतर के उस विवेक में जीवित हैं जो मुझे सही और गलत का अंतर बताता है। जब भी मैं जीवन के किसी दोराहे पर थका हुआ हारने लगता हूँ, तो मेरे भीतर से एक मद्धम सी आवाज़ आती है–वही ढाँढस, वही अनुशासन, जो कभी पापा की आवाज़ हुआ करती थी। वे विलीन भले ही पंचतत्व में हो गए हों, लेकिन मेरे अस्तित्व के कण-कण में उनका अक्स आज भी महकता है।

इस फादर्स डे पर मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है, न ही मैं उनके गले लगकर अपनी भावनाएं जता सकता हूँ। मेरे पास केवल स्मृतियों के कुछ अछूते पन्ने हैं और कृतज्ञता से भीगी हुई आँखें हैं। पापा, आप जहाँ भी ब्रह्मांड के किसी कोने में एक तारा बनकर चमक रहे हों, आपकी दी हुई सीख मेरी हर सांस का संबल बनी रहेगी।

मर्मस्पर्शी काव्यांजलि

विदा हुआ वो साया सिर से, रह गई बस तन्हाई,
महफ़िल के इस शोर में पापा, याद आपकी आई।
ढूँढती हैं ये आँखें तुमको क्षितिज के उस पार कहीं,
छूकर गुज़रे जो ठंडी हवा, लगता है आप यहीं।

आपने जो बोए थे मुझमें, वो संस्कार ज़िंदा हैं,
आपकी आँखों के देखे, वो सारे सपनें ज़िंदा हैं।
जिस्म जुदा हुआ तो क्या, रूह में आप समाए हो,
मेरी हर एक धड़कन में, तुम बनकर अक्स आए हो।

तर्पण में क्या अर्पण करूँ, शब्द मेरे कमज़ोर हैं,
इस सूने अम्बर में बस, आपकी यादों के छोर हैं।
जब तक ज़िंदा हूँ इस जग में, आपका नाम बढ़ाऊँगा,
पापा, आपके ही अंश को मैं, हर पल सार्थक बनाऊँगा।

डॉ. निधि गुप्ता
बिलासपुर
(पी. एच.डी., एम.लिब., एल.एल.बी., बी.एस.सी.)

नशा नहीं, ज़िंदगी चुनिएः एक पीढ़ी के बचने की कहानी.....

रात के करीब नौ बजे थे। बिलासपुर के एक मोहल्ले में रामलाल जी अपने दरवाजे पर बैठे थे, निगाहें गली के मोड़ पर टिकी हुई थीं। बेटा हर शाम इसी वक्त लौटता था- कभी हंसता हुआ, कभी थका हुआ, पर लौटता जरूर था। आज तीसरी रात है कि वह नहीं लौटा। रामलाल जी को अब तक नहीं पता था कि 'दोस्तों के साथ टाइम पास' शब्द कब 'नशे की लत' में बदल गया था। यह कहानी सिर्फ रामलाल जी की नहीं है- यह हर उस घर की कहानी है जहां माता-पिता रात-रात जागते हैं, बिना यह जाने कि उनका बच्चा किस दलदल की ओर बढ़ रहा है।

26 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हर साल लाखों परिवारों की पीड़ा और करोड़ों युवाओं के भविष्य पर मंथन का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व नशा रिपोर्ट 2025 के मुताबिक साल 2023 में दुनिया भर में लगभग 31.6 करोड़ लोगों ने किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन किया, जो 15 से 64 वर्ष की आबादी का करीब 6 प्रतिशत है। इनमें भांग का सेवन करने वालों की संख्या 24.4 करोड़, ओपिओइड 6.1 करोड़, एम्फेटामाइन 3.07 करोड़, कोकीन 2.5 करोड़ और एक्स्टसी 2.1 करोड़ रही। रिपोर्ट यह भी आगाह करती है कि संगठित नशा तस्करी गिरोह वैश्विक संकटों का फायदा उठाकर समाज के सबसे कमजोर और सबसे युवा वर्ग को निशाना बना रहे हैं।

भारत की तस्वीर भी कम चिंताजनक नहीं है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, जिनमें 16

करोड़ शराब और करीब 12 करोड़ अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले हैं। इनमें से लगभग 6 करोड़ लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, मगर समुचित पुनर्वास सुविधाओं के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता। हर साल तंबाकू जनित बीमारियों से लगभग 20 लाख और शराब से जुड़े कारणों से करीब 5 लाख भारतीयों की जान चली जाती है- ये आंकड़े किसी युद्ध के हताहतों से कम नहीं।

छत्तीसगढ़ और बिलासपुर भी इस लड़ाई से अनछुए नहीं हैं। राज्य सरकार ने मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद में विशेष एनडीपीएस अदालतें गठित कर 11 मई 2026 से प्रभावी किया है, जो दर्शाता है कि नशे के मामले अब सिर्फ पुलिस थानों तक सीमित नहीं, बल्कि न्यायपालिका की प्राथमिकता बन चुके हैं। शहर के कोनी थाना क्षेत्र में हाल में गांजे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तारी जैसी घटनाएं बताती हैं कि सुदूर गांवों से लेकर शहर की गलियों तक नशे का जाल किस तरह फैल चुका है। राहत की बात यह है कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अब तक देशभर में 15.78 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है, जिनमें 5.26 करोड़ युवा और 3.31 करोड़ महिलाएं शामिल हैं, और 4.31 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान इस मुहिम से जुड़ चुके हैं।

सवाल यह है कि आखिर युवा पीढ़ी नशे की ओर क्यों खिंचती चली जा रही है। परीक्षा का दबाव, बेरोजगारी की चिंता, टूटते सामाजिक रिश्ते, सोशल मीडिया पर दिखावे की होड़ और दोस्तों का दबाव- ये सब मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बना देते हैं जिसमें नशा 'राहत' का झूठा भरोसा देता प्रतीत होता है। जबकि सच्चाई यह है कि यह राहत क्षणिक होती है और इसके पीछे टूटते परिवार, बिगड़ता स्वास्थ्य और खोता आत्मविश्वास जैसी स्थायी क्षतियां छिपी रहती हैं।

समाधान किसी एक संस्था या सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। परिवार को संवाद का माध्यम बनना होगा, स्कूल-कॉलेजों को जीवन-कौशल शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, और समुदाय को नशा मुक्ति केंद्रों तथा परामर्श सेवाओं को सुलभ बनाना होगा। मीडिया, धर्मगुरु, खेल जगत के नायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि- सभी को इस मुहिम में साझीदार बनना होगा, ताकि नशा छोड़ने की इच्छा रखने वाला कोई भी युवा संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए।

शहर चाहे बिलासपुर हो या अमृतसर, भुवनेश्वर हो या जयपुर...जो शिक्षा और साहित्य, संस्कृति के केंद्र रहे हैं, हरेक शहर के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाकर रखे।

नशा किसी को रातोंरात नहीं पकड़ता, यह कदम-कदम पर दस्तक देता है- कभी जिज्ञासा के बहाने, कभी दोस्ती के दबाव में। और ठीक इसी तरह, इससे बचाव भी कदम-कदम पर होता है- एक संवाद, एक भरोसा, एक वक्त पर बढ़ाया गया हाथ। 26 जून सिर्फ एक दिवस नहीं, हर माता-पिता, हर शिक्षक और हर युवा के लिए यह सवाल है: क्या हम अपने आसपास किसी रामलाल जी को दरवाजे पर अकेला बैठा रहने देंगे, या समय पर हाथ बढ़ाएंगे?

- प्रभात दत्त झा
देवेन्द्रनगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495001

'न चेकिंग, न ड्रेस कोड, प्राइवेट कर्मचारियों से गिनवाए जा रहे थे नोट', चंदा चोरी में एसआईटी का बड़ा खुलासा

लखनऊ। राम मंदिर चढ़ावे चोरी मामले की एसआईटी जांच कर रही है. इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है. एसआईटी को हर स्तर पर घोर लापरवाही मिली है. राम मंदिर ट्रस्ट की रकम में बैंकिंग का काम देख रही एसबीआई का ही नोट अलग कराने/गड्डी बनवाने और गिनवाने का काम था. एसबीआई निजी सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारियों को ठेके पर लेकर नोट गिनवाती थी.

आने जाने के दौरान नहीं होती थी चेकिंग

जानकारी के अनुसार एसबीआई ने वाराणसी की निजी सिक्योरिटी एजेंसी को ठेका दिया था. निजी सिक्योरिटी एजेंसी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की सिफारिश पर अयोध्या के ही लड़कों को नोट गिनवाने के काम में रख दिया था. परिचित की सिफारिश पर ही नौकरी मिलने की प्रथा पर अनुकल्प मिश्रा ने अपने साले लवकुश मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट में नौकरी पर लगवा दिया था।

ड्यूटी पर आने-जाने के दौरान चेकिंग में भी लापरवाही सामने आई है. कौन क्या लेकर आ रहा क्या लेकर जा रहा, कोई जांच नहीं होती थी. घरेलू कपड़ों में ही कर्मचारी राम मंदिर ट्रस्ट के कमरे में बैठकर नोट गिनने लगते थे. सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने में भी लापरवाही सामने आई है. चोरी करने के लिए कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे और चोरी कर लेते थे।

ड्रेस कोड का भी नहीं होता था पालन

सभी के लिए ड्रेस कोड बनाया गया था और एक ड्रेस भी दी गई थी. लेकिन पहनता कोई नहीं था. एसआईटी की पड़ताल में मंदिर परिसर से दान पेटी ट्रस्ट के कमरे में ले जाने से लेकर बैंक में नोट जमा होने तक हर स्तर पर लापरवाही सामने आई है.

इधर अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है. जिस पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई संभावित है. मामला कोर्ट नंबर-2 में सूचीबद्ध किया गया है.

याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मोहित अशोक शर्मा ने बताया कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख (मेंशनिंग) कर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया जाएगा. उनके अनुसार यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और व्यापक जनहित से जुड़ा है, इसलिए इस पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की अपेक्षा की जा रही है. याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर मामले को पूरक सूची (सप्लीमेंट्री लिस्ट) में शामिल कराने का अनुरोध भी किया जा सकता है.

जांच की जद में आए कर्मचारियों को अयोध्या छोड़ने की मनाही

प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद SIT विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी. वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने जांच के दायरे में आए सभी लोगों को बिना सूचना अयोध्या छोड़ने से मना कर दिया है.

जांच में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे शहर छोड़ने से पहले एसआईटी को जानकारी दें. यह फैसला जांच को प्रभावित होने से रोकने और जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से तुरंत पूछताछ सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. फिलहाल एसआईटी मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है।

भाजपा ने महमूद गजनी की तरह राम मंदिर को लूटा : संजय राउत

मुंबई। राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है और भाजपा की तुलना लुटेरे महमूद गजनी से कर दी है। संजय राउत ने कहा कि यह लूट और कानून व्यवस्था का पतन है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में लिखे लेख में संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा।

मुखपत्र सामना के लेख में लगाए बड़े आरोप

सामना के संपादकीय में संजय राउत ने लिखा, 'देश ने अब देख लिया है कि मंदिर विकास का असल मतलब क्या होता है। अयोध्या के राम मंदिर में दान पेटियों की लूट। राम मंदिर में दान, सोना, चांदी और आभूषणों की खुलेआम लूट हुई। कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपना खून बहाया, फिर भी भाजपा ने उसी मंदिर को लूटा। जिस तरह से महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसी तरह से भाजपा ने राम मंदिर को लूटा है।'

अंबाबाई मंदिर के गलियारे के निर्माण पर शाह पर साधा निशाना

राउत ने लिखा, 'कम से कम अंबाबाई मंदिर में चोरी और डकैती तो नहीं हुई। राम मंदिर में दान पेटी की चोरी कानून व्यवस्था का पतन है। वे राम मंदिर की रक्षा तक नहीं कर सकते, फिर भी हमारे अंबाबाई मंदिर के विकास की बात करते हैं।' उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमित शाह ने कोल्हापुर का दौरा किया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को एकमात्र शिवसेना कहा था। साथ ही अमित शाह ने माता अंबाबाई मंदिर के जीर्णोद्धार और गलियारे के निर्माण का भी एलान किया था।

अमित शाह पर बोला तीखा हमला

संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 'पिछले एक दशक में देश के कई प्रमुख मंदिरों को लूटा गया और ये सभी लुटेरे भाजपा के भीतर ही मौजूद हैं और अमित शाह की गोद में बैठे हैं। अमित शाह आरोप लगाते हैं कि उद्धव ठाकरे, कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। यह उनका महाराष्ट्र विरोध है। ये लोग खुद राम मंदिर के लुटेरे और लोकतंत्र के हत्यारे हैं।' इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आप नेता अरविंद केजरीवाल भी राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर भाजपा पर निशाना साध चुके हैं।

सौगत रॉय ने बजट सत्र से पहले सरकार पर उठाए सवाल

बागी टीएमसी सांसदों की सदस्यता रद्द करें स्पीकर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने बागी सांसदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस दौरान सौगत रॉय के साथ चार अन्य सांसद भी इस बैठक में शामिल थे। करीब एक घंटे तक चली इस बातचीत में टीएमसी नेताओं ने बागी सांसदों के कदम को नियम के खिलाफ बताया।

सौगत रॉय ने स्पीकर से कहा कि जो सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं, उन्हें कानून के हिसाब से लोकसभा से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि इन बागी सांसदों ने किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय (मर्जर) के नियमों का पालन नहीं किया है।

इसलिए उनके नए गुट को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। सौगत रॉय को उम्मीद है कि स्पीकर संविधान के अनुसार फैसला लेंगे।

पश्चिम बंगाल बजट सत्र से पहले सौगत रॉय ने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह देखना चाहते हैं कि भाजपा सरकार घाटे के कर्ज और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से कैसे निपटती है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने बगावत कर दी। इन सांसदों ने नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने और संसद में एनडीए (NDA) का समर्थन करने का फैसला किया है। बागी सांसदों ने स्पीकर से मिलकर सदन में अलग बैठने की जगह भी मांगी थी। उनका दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है।

टीएमसी नेतृत्व इस कदम से बेहद नाराज है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने इसे मतदाताओं के साथ बड़ा धोखा बताया। उन्होंने कहा कि ये सांसद ममता बनर्जी के चेहरे और टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए थे। अब एनडीए का साथ देना उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया था। वहीं, मदन मित्रा ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का जाना बताता है कि 'दाल में कुछ काला है।'

मेरे अकाउंट के पैसों से अंतिम संस्कार करना...

शख्स ने ली परिवार की जान, फिर की खुदकुशी

अमरावती। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार की जान ले लीच इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. खुदकुशी करने से पहले शख्स ने अपने टीवी स्क्रीन पर सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने अपने जुर्म की दिल चीर देने वाली वजह का खुलासा किया था.

30 साल के दामू ने अपनी पत्नी की लाइलाज बीमारी से परेशान होकर अपने परिवार की जान ले ली और फिर आत्महत्या कर ली. दामू, एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र था, जो अपनी पत्नी निर्मला (25), अपने बेटे दिलीप और बेटी श्रीविद्या के साथ रहता था। दामू की जिंदगी में बुरा मोड़ तब आया, जब उसकी पत्नी निर्मला को दिमाग से जुड़ी एक गंभीर बीमारी हो गई. कई स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद भी, परिवार को बताया गया कि उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है।

पत्नी और बच्चों के खाने में मिलाया जहर!

अपनी पत्नी को तकलीफ में नहीं देख पाने और उसके बिना अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए दामू ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाया. पुलिस को शक है कि उसने फांसी लगाने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों के खाने में जहर मिला दिया था. इस घटना का पता अगली सुबह तब चला जब घर में ताला लगा होने पर परेशान पड़ोसियों ने पुलिस को बताया।

अमोनिया गैस रिसाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हुई, विधानसभा में विपक्ष का हंगामा

चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में अमोनिया गैस रिसाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। राज्य के श्रम कल्याण मंत्री जे मोहम्मद फरवास ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर उनके गृह राज्य भेजने की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 21 जून को दो महिला श्रमिकों की मौत हुई थी, जबकि सोमवार सुबह तीन अन्य प्रवासी महिला श्रमिकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हादसे में मृतकों की संख्या पांच हो गई है।

मुख्यमंत्री ने गठित की संयुक्त जांच समिति

विधानसभा में बयान देते हुए मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने हादसे की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की है। इस टीम को 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक और तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है तथा पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मंत्री ने कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति सुरक्षा या परिचालन संबंधी लापरवाही का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जवाबदेही तय करने में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी।

74 श्रमिक हुए थे प्रभावित

मंत्री ने बताया कि पाइपलाइन में अचानक हुए अमोनिया गैस रिसाव के कारण 70 महिलाओं सहित कुल 74 श्रमिक प्रभावित हुए और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्यवश इस हादसे में पांच महिला श्रमिकों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए राहत राशि की घोषणा की है और सरकार उनके पार्थिव शरीरों को गृह राज्य भेजने का पूरा खर्च वहन करेगी।'

सीफूड प्रोसेसिंग यूनिट में हुआ था हादसा

यह हादसा 21 जून को एक निजी सीफूड प्रोसेसिंग एवं निर्यात इकाई में हुआ था। नियमित औद्योगिक कार्य के दौरान अमोनिया गैस का रिसाव होने से वहां मौजूद श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रभावित श्रमिकों में अमोनिया गैस के संपर्क में आने के कारण सांस लेने में तकलीफ, आंखों और श्वसन तंत्र में जलन, खांसी, सीने में दर्द तथा गंभीर श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे लक्षण देखे गए।

पुणे पोर्शे केस : आरोपी के पिता की जमानत रद्द कराने की मांग

- अदालत पहुंची पुलिस; वायरल वीडियो बना मुसीबत

पुणे। पुणे पुलिस ने पोर्शे कार हादसे के नाबालिग आरोपी के पिता, विशाल अग्रवाल की जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस का आरोप है कि विशाल अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह अर्जी शिवाजीनगर सत्र न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे के माध्यम से दी गई है। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है।

वायरल वीडियो बना मुसीबत

यह कदम तब उठाया गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में विशाल अग्रवाल अपने परिवार के साथ जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वह एक स्थानीय रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बेटे के साथ नाच रहे हैं और पीछे संगीत बज रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा गया और

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे।

पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य विधि विभाग से अदालत जाने की अनुमति ली गई। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि जमानत मिलने के बाद इस तरह का जश्न मनाना गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इससे गवाहों पर दबाव पड़ने की आशंका है। पुलिस अदालत को बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें रखी थीं, उन्हें पूरी तरह तोड़ा गया है।

अग्रवाल परिवार ने क्या कहा?

दूसरी ओर, अग्रवाल परिवार ने इस वीडियो को पूरी तरह गलत और पुराना बताया है। विशाल अग्रवाल की कानूनी टीम ने एक बयान जारी कर कहा कि यह वीडियो साल 2023 का है। उनके मुताबिक, यह वीडियो गोवा के एक होटल में उनकी शादी की 25वीं सालगिरह के जश्न के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने साफ किया कि यह कार्यक्रम 19 मई 2024 को पुणे के यरवदा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए पोर्शे हादसे से बहुत पहले का है।

पुलिस ने इस वीडियो के सिलसिले में विशाल अग्रवाल और उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस इन बयानों और डिजिटल सबूतों को अदालत के सामने पेश करेगी। अदालत ने विशाल अग्रवाल को इस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला 19 मई 2024 का है, जब कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्शे कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। आरोप है कि कार विशाल अग्रवाल का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था। विशाल अग्रवाल उन 10 आरोपियों में शामिल हैं, जिन्हें खून के नमूने बदलने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

बागियों को आदित्य ठाकरे ने बताया बिकाऊ

- वफादारी पर भी सवाल, कहा- लालच में विचारधारा छोड़ी

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी के बागी सांसदों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने बागी सांसदों पर विचारधारा के बजाय निजी लालच को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। आदित्य ठाकरे ने इन सांसदों को बिकाऊ करार दिया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने उन मतदाताओं के साथ धोखा किया है जिन्होंने उन्हें महाविकास अघाड़ी (MVA) और 'इंडिया' गठबंधन के समर्थन से जिताया था।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये सांसद कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की मदद से चुनाव जीते थे। मतदाताओं ने एनडीए (NDA) के उम्मीदवारों और उनकी विचारधारा के खिलाफ वोट दिया था। लेकिन अब इन सांसदों ने अपनी वफादारी और प्रतिष्ठा को शर्मनाक तरीके से बेच दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। आदित्य के अनुसार, इन सांसदों ने रातों-रात अपनी

विचारधारा सिर्फ इसलिए बदल ली क्योंकि वे लालची हो गए थे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि चुनाव के समय इन नेताओं ने ही गठबंधन के बड़े नेताओं से अपने क्षेत्र में रैलियां करने की मांग की थी।

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) ने पार्टी की बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) अनिल देसाई ने यह नोटिस भेजा है। इसमें सांसदों को सख्त चेतावनी दी गई है कि उन्हें दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। सांसदों को 24 घंटे के भीतर लिखित में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। पार्टी ने साफ किया है कि अगर वे जवाब नहीं देते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने खुद ही पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। इसके बाद संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उन पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा।

यह विवाद तब और गहरा गया जब दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में नो में से केवल तीन लोकसभा सांसद ही पहुंचे। बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे शामिल हुए। जबकि संजय दीना पाटिल समेत छह सांसद गायब रहे। गायब रहने वाले अन्य सांसदों में नागेश आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, ओमप्रकाश राजेनिंबाल्कर और भाऊसाहेब वाकचौरे के नाम शामिल हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पहले ही कह दिया है कि इन अनुपस्थित सांसदों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये छह सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया है कि इन सांसदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इन सांसदों का यह व्यवहार शर्मनाक है और उन्होंने जनता के भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया है।

ग्रेट निकोबार परियोजना पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल

- केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल को पत्र लिखा है। इस पत्र में जयराम रमेश ने परियोजना के तहत बनने वाले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास को लेकर कई स्पष्टीकरण मांगे हैं। पत्र में जयराम रमेश ने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास के लिए निजी कंपनी की भागीदारी के लिए निविदाएं जारी करने की समय-सीमा और निजी कंपनी के चयन की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

उन्होंने यह भी पूछा कि परियोजना में निजी क्षेत्र की न्यूनतम हिस्सेदारी 55 प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो क्या 100 प्रतिशत निजी स्वामित्व की अनुमति होगी, या फिर सार्वजनिक संस्थाओं के लिए भी न्यूनतम हिस्सेदारी तय की गई है? जयराम रमेश ने प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता भी जताई।

निजी स्वामित्व और फंडिंग पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि समिति के रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में कम से कम 55 प्रतिशत हिस्सेदारी किसी भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली इकाई के पास होनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह दावा कि परियोजना का उद्देश्य रक्षा और ट्रांसशिपमेंट अवसंरचना का विकास है, जबकि यह भ्रामक है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस परियोजना का असल उद्देश्य एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाना है ताकि वह देश की सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकीय भूमि पर होटल और कैसीनो विकसित कर सके। ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साथ एक नागरिक-सह-नौसैनिक हवाईअड्डा, टाउनशिप और बिजली संयंत्र विकसित करने की भी योजना है।

अब श्रीलंका पर अमेरिका का फोकस, दो सीनियर अफसर दौरे पर

नई दिल्ली। कोलंबो में अमेरिका के दो वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग दौरों पर श्रीलंका पहुंचे हैं. इनमें पैसिफिक एयर फोर्सेज के कमांडर जनरल केविन श्नाइडर भी शामिल हैं. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ये दौरे रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित हैं. रणनीतिक रूप से अहम हिंद महासागर क्षेत्र में वॉशिंगटन की बढ़ती सक्रियता के बीच इन दौरों को अहम माना जा रहा है.

अमेरिकी दूतावास के मुताबिक, श्नाइडर रविवार को तीन दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे और उनका दौरा 24 जून को खत्म होगा. दक्षिण और मध्य एशियाई

मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री एस पॉल कपूर भी रविवार को ही तीन दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे. ये हाई प्रोफाइल दौरे ऐसे समय में हो रहे हैं जब हिंद महासागर क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और हाल के वर्षों में चीन ने बुनियादी ढांचे में निवेश और समुद्री मौजूदगी का दायरा बढ़ाया है।

शांति समझौते की ओर बढ़े अमेरिका और ईरान!

अमेरिका अपनी व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत श्रीलंका समेत क्षेत्र के देशों के साथ रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक जुड़ाव को और गहरा करने की कोशिश में है. अमेरिकी मिशन के अनुसार, श्नाइडर अपने दौरे के दौरान श्रीलंका सरकार और रक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे. इनमें रक्षा मंत्रालय और श्रीलंका वायुसेना के नेता भी शामिल हैं. दूतावास ने कहा कि बातचीत का फोकस हवाई और समुद्री क्षेत्र की निगरानी, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा.

श्नाइडर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना के सभी कर्मियों और संसाधनों की निगरानी करते हैं. दूतावास ने इस यात्रा को अमेरिका-श्रीलंका रक्षा साझेदारी की बढ़ती मजबूती का संकेत बताया.

पहले भी कई मंत्रियों को लिख चुके हैं पत्र

- जयराम रमेश इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी कई पत्र लिख चुके हैं। इन पत्रों में उन्होंने परियोजना से होने वाले संभावित पर्यावरणीय विनाश और पारिस्थितिकीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई है।
- हाल ही में उन्होंने पर्यावरण मंत्री यादव को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर्याप्त नहीं हैं और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है।

उन्होंने तीन प्रमुख सवाल उठाए

- क्या 55 प्रतिशत न्यूनतम निजी हिस्सेदारी का मतलब है कि परियोजना में 100 प्रतिशत निजी स्वामित्व की अनुमति होगी?
- क्या बंदरगाह क्षेत्र में स्वामित्व का विविधीकरण सुनिश्चित किया जाएगा या फिर हवाईअड्डों की तरह ऐसी स्थिति बनने दी जाएगी, जहां एक ही निजी कंपनी अधिकांश परिसंपत्तियां हासिल कर ले?
- जब पीपीपीएसी ने परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) अनुदान देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तो क्या मंत्रालय अपने बजट से पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराएगा?

स्वत्वाधिकारी अभिव्यक्ति प्रकाशन प्रा.लि.के लिए प्रकाशक सुभाष मिश्रा के लिए, मुद्रक नरेश मंगतानी द्वारा श्रीबालाजी प्रिंटर्स, 21 एच, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल म.प्र.से मुदित एवं एसआर-4-102, रुद्राक्ष पार्क फेस-1 बावड़ियां कलां, भोपाल, म.प्र.से प्रकाशित, प्रधान संपादक -सुभाष मिश्रा, सलाहकार संपादक- भालचन्द्र जोशी, स्थानीय संपादक- अंशुमन खरे आरएनआई रजि. नं.RNI.NO.MPHIN/ 25/A3544 पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।